नई दिल्ली
रविवार 5 जुलाई 2026
आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष,
पंचमी वर्ष : 30, अंक : 77
पृष्ठ 12 मूल्य 2.00

मौसम
अधि. 36
न्यून. 29

हरिभूमि
दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित
समाचार ही नहीं, विचार भी
haribhoomi.com

राजधानी में हुए एक मीडिया संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री

अभावों से निकलकर विकसित भारत के निर्माण की रही 12 वर्षों की यात्रा : राजनाथ सिंह

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल से जुड़ी रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। जिसमें उन्होंने कहा कि बीते एक दशक से अधिक लंबी देश की हमारी यह यात्रा अभावों से आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से विकसित भारत के निर्माण की ओर प्रगति की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही नतीजा है कि आज हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा में बदलाव आया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दुनिया भारत के दृष्टिकोण को ध्यान से सुनती है। रक्षा मंत्री ने यह जानकारी राजधानी में हुए एक मीडिया संगठन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। उनके इस बयान को रक्षा मंत्रालय ने मीडिया से साझा किया है।

मीडिया को नसीहत, रक्षा-सुरक्षा जिम्मेदारी वाले विषय, निष्पक्षता संग तटस्थता बनाए रखनी चाहिए

यूं पड़ती विकसित भारत की मजबूत नींव

राजनाथ सिंह के मुताबिक, अपने पहले कार्यकाल में सरकार ने अभावों को दूर कर अवसरों को बढ़ाया और कार्य करने की संस्कृति में बदलाव लाया। दूसरे में आकांक्षाओं को उपलब्धियों में तब्दील कर देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। जबकि मौजूदा तीसरे कार्यकाल में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति के जरिए केंद्र विकसित भारत की दृढ़ता से नींव रख रहा है। उन्होंने चौथे कार्यकाल को लेकर विश्वास जताते हुए कहा कि उस दौरान समूचा विश्व एक विकसित भारत के उदय का भी साक्षी बनेगा।

असंभव मामलों का निकाला समाधान : उन्होंने जम्मू-कश्मीर से धारा-370 की समाप्ति और नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए चल रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सरकार के उस दृढ़ संकल्प का नतीजा है। जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। केंद्र उद्यमियों को रोजगार उत्पन्न करने वाले और धन निर्माता के रूप में स्वीकार ▸▸ शेष पेज 5 पर

स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई

उन्होंने कहा कि 2014 में जब हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। तब कुछ लोगों ने इसे असफल बताया था। लेकिन यही योजना है, जिसने सफलता के नए मानक स्थापित किए। आज भी यही क्रम बना हुआ है। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भी मेक इन इंडिया जैसी ही असफलता की सोच हावी रही। लेकिन इसके बावजूद देश में प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचा मॉडल वाले सेमीकंडक्टर पार्कों की स्थापना से सरकार ने तमाम आलोचनाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया। यही सबसे बड़ा कारण रहा है, जिससे पिछले साल 2025 में हमने स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया। इसके अलावा 2013-14 के आंकड़े से तीन गुना बढ़कर वार्षिक रक्षा उत्पादन 2025-26 में अपने सर्वोच्च उच्च स्तर 1.78 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इसी तरह से रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38 हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। जो 2013-14 की अवधि से 57 गुना ज्यादा है।

सूचना की विश्वसनीयता बनती चुनौती

रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में मीडिया को भी नसीहत दी और कहा कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता की वास्तविक ताकत केवल सूचना के प्रचार में नहीं बल्कि समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन देने, सच्चाई को सामने लाने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की है। उन्होंने ये भी कहा, आज चुनौती सूचना की कमी की नहीं है। बल्कि उसकी सटीकता और विश्वसनीयता की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से हुई तकनीकी प्रगति से पत्रकारिता पर भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन यह किसी भी रूप में मानवीय रचनात्मकता और बुद्धि को पीछे नहीं छोड़ पाएगी।

गलत सूचना से प्रभावित होता मनोबल

उन्होंने बताया कि पत्रकारिता के भविष्य की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह एआई की क्षमताओं और मानवीय सहानुभूतियों के मध्य कितना बेहतर संतुलन व तालमेल स्थापित कर पाती है। एआई जहां पत्रकारिता को तेज और सटीक बनाएगा। वहीं भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह सुनिश्चित करेगी कि ये मानवीय और विश्वसनीय बनी रहे। गलत सूचना समाज, रक्षा बलों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव डालती है। पत्रकारिता में सबसे पहले खबर देना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सही खबरें देना है। खासतौर पर जब मामला रक्षा बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों से जुड़ा हुआ हो। तो हर शब्द राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन जाता है। मीडिया को हमेशा सटीकता, निष्पक्षता और तटस्थता को बनाए रखना चाहिए।

पेट्रोल में ई-20 एथेनॉल मिश्रण पर केंद्र सरकार की बड़ी सफाई

भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं सोशल मीडिया के दावे गलत

एआई इमेज

सरकार ने गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाने वाले वीडियो को फर्जी बताया। ईंधन ग्रेड का एथेनॉल में चीनी का अंश नहीं होता है, इसलिए गाड़ियों में चींटियां लगने की बात वैज्ञानिक रूप से गलत

इससे वाहनों के इंजन माइलेज बीमा या वारंटी पर कोई भी विपरीत असर नहीं

कॉन्फ्रेंस में ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गजों ने रखी अपनी राय

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

पेट्रोल में 20 फीसदी तक एथेनॉल मिलाने (ई-20 ईंधन) को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अफवाहों पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करते हुए इन सभी भ्रामक दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि ई-20 ईंधन पूरी तरह सुरक्षित है और इससे वाहनों के इंजन, माइलेज, बीमा या वारंटी पर कोई भी विपरीत असर नहीं पड़ता है।

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि एक लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी बर्बाद होता है, जिसे सरकार ने पूरी तरह गलत बताया है। वास्तव में प्रति लीटर एथेनॉल उत्पादन में मात्र 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी लगता है, और आधुनिक प्लांट इस पानी को रीसाइकिल ▸▸ शेष पेज 5 पर

- ▸▸ साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था
- ▸▸ प्रति लीटर एथेनॉल उत्पादन में मात्र 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी लगता है
- ▸▸ अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और जापान जैसे कई विकसित देशों में इसका इस्तेमाल

यह जांची-परखी साइंटिफिक प्रोसेस

सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों-रात नहीं हुआ। यह एक जांची-परखी, साइंटिफिक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसका टेस्ट कर चुकीं हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री शेष पेज 5 पर

मारुती सुजुकी के राहुल भारती ने कहा

ई-20 के हिसाब से बन रहीं गाड़ियां

राहुल भारती

मारुती सुजुकी के एक्जिक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने बताया कि ई-20 को लेकर सोशल मीडिया पर मिथ ज्यादा हैं और सच्चाई कम हैं। उन्होंने कहा कि हम ▸▸ शेष पेज 5 पर

ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, धमकी मिलने के बाद जांच शुरू

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह 8 से 10 जुलाई तक की जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की यात्रा से ठीक पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा अधिकारी व्यापक जांच-पड़ताल में जुट गए हैं। अभी तक फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख डिजिटल समाचार मंच और अखबार 'द ऑस्ट्रेलिया टुडे' की एक रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी निकलकर सामने आई है। जिसमें यह दावा किया गया है कि 'अब मुस्तफा' नामक एक फेसबुक अकाउंट से कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री को जान से मारने की यह धमकी दी गई है। जिसमें लिखा है कि '9 जुलाई को ▸▸ शेष पेज 5 पर

■ अगले सप्ताह 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे पीएम

वैभव ने शेफाली-सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा

15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ 'खेले'

एजेंसी ⏭ मैनचेस्टर

वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 99 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेला। वैभव को उपकप्तान तिलक वर्मा ने डेब्यू कैप दी। वैभव ने शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। शेफाली ने 15 साल 239 दिन और सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में पहला मैच खेला था। भारत ने दूसरे टी-20 में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। वैभव 10 बॉल पर 14 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा 24 बॉल पर 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वैभव सूर्यवंशी ▸▸ शेष पेज 5 पर

■ हालांकि चले नहीं 14 रन पर ही आउट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला

सोने से मढ़ी 5 करोड़ रुपए की रामचरितमानस चोरी!

एजेंसी ⏭ अयोध्या

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे को लेकर खड़ा हुआ विवाद गहराता जा रहा है। अब पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि मंदिर को भेंट की गई उनकी सोने से मढ़ीबहुमूल्य रामचरितमानस गायब हो गई है। उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को राम मंदिर ट्रस्ट को सवा क्विंटल वजन की रामचरितमानस भेंट की थी। हालांकि, उन्हें आज तक इसकी रसीद नहीं मिली और 3-4 महीने बाद ही यह मंदिर से गायब हो गई। जब वे इस सिलसिले में अयोध्या पहुंचे, तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन्हें 9 घंटे इंतजार कराया और हाथ जोड़ने पर भी रूखा व्यवहार किया। चंदे ▸▸ शेष पेज 5 पर

■ चंपत राय के इस्तीफे पर कल फैसला

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इंदौर में कहा

बीएलओ ही निर्वाचन के आधार स्तंभ और लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी

मध्य प्रदेश ने किया उत्कृष्ट कार्य

हरिभूमि न्यूज ⏭ इंदौर

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार शनिवार को इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इंदौर आगमन पर उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर की पावन नगरी की सराहना की। उनका यह दौरा मुख्य रूप से बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) से संवाद और चुनावी व्यवस्थाओं की समीक्षा पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ को निर्वाचन आयोग की पूरी व्यवस्था का आधार स्तंभ और लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के संधारण से लेकर जमीनी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने तक बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण ▸▸ शेष पेज 5 पर

टेलीग्राम पर केंद्र सरकार का सख्त रुख

फिल्मों व वेब सीरीज की पायरेसी रोकने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

पूरा ध्यान जवाबदेही तय करने पर

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

फिल्म और ओटीटी कंटेंट की चोरी (पायरेसी) करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने मशहूर मैसेजिंग एप टेलीग्राम को एक सख्त नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर की जा रही पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य ऑडियो-विजुअल कंटेंट पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम से अगले 15 दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब छोटे-मोटे स्तर पर लिंक्स या चैनल्स को ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। अब सरकार का पूरा ▸▸ शेष पेज 5 पर

चुनौतीपूर्ण, अस्थिर शांति मिशन में सुनिश्चित की नागरिकों की सुरक्षा और व्यवस्था को बनाया सुदृढ़

यूएन ने सराहे कांगो में भारतीय शांति सैनिकों के प्रयास, 651 को किया सम्मानित

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

लंबे वक्त से जारी सशस्त्र हिंसा और जटिल मानवीय चुनौतियों से जूझ रहे अफ्रीका महाद्वीप के देश पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में शांति स्थापना के लिए जारी भारतीय शांति सैनिकों (ब्लू हेलमेट) के प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरजोर अंदाज में सराहा गया है। सेना के कुल 651 शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) पदक से सम्मानित किया गया है। बीते 3 जुलाई को कांगो के ▸▸ शेष पेज 5 पर

2023 में भारत को यूएन का सर्वोच्च शांति सम्मान, 'डॉग हैमरशॉल्ड' पदक से सम्मानित किया गया था

यूएन के जनादेश का किया पालन

दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण अस्थिर शांति मिशनों में से एक माने जाने कांगो में तैनात भारतीय दल ने आम लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने और उससे जुड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने, हिंसा प्रभावितों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के साथ-साथ सशस्त्र हिंसा, मुश्किल मानवीय चुनौतियों के बीच यूएन के जनादेश के प्रभावी ढंग से ▸▸ शेष पेज 5 पर

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
के सहयोग से
दिल्ली यातायात पुलिस
द्वारा आयोजित
विशेष
लोक अदालत
12 जुलाई, 2026 को
इन सात कोर्ट परिसरों में

कोर्ट परिसर
पटियाला हाउस | कड़कड़डूमा | तीस हजारी | साकेत
रोहिणी | द्वारका | राऊज एवेन्यू
1. केवल दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल पर लंबित और 31.03.2026 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य यातायात चालान/नोटिस ही इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे जाएँगे।
2. नोटिस/चालान डाउनलोड करने और प्रिंटआउट लेने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लॉग इन करें: https://traffic.delhipolice.gov.in/ lokadalat या क्यूआर कोड स्कैन करें।
3. नोटिस/चालान का प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है। न्यायालय परिसर में प्रिंटआउट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
क्यूआर कोड 1 स्कैन करें: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की पूरी जानकारी के लिए
क्यूआर कोड 2 स्कैन करें: नोटिस एवं चालान डाउनलोड करने के लिए
यह लिंक 06.07.2026 को सुबह: 10.00 बजे से सक्रिय होगा और चालान / नोटिस की सीमा 2,00,000 समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा। प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान / नोटिस ही डाउनोड किए जाएंगे।
अधिक जानकारी के लिए
हमें फॉलो करें :- व्हाट्सएप: 8750871493 @dtptraffic @dtptraffic @dtptraffic
24 घंटे यातायात हेल्पलाइन 011-25844444/1095
दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण
राऊज एवेन्यू जिला कोर्ट्स कॉम्पलेक्स, तीसरा तल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002
हेल्पलाइन: 1516
एक यातायात प्रहरी बनें ऐप डाउनलोड करें
Google Play App Store
DP/9894/2026
वेबसाइट: www.traffic.delhipolice.gov.in | ई-मेल: info.traffic@delhipolice.gov.in

खबर संक्षेप

पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट पर श्वेत-पत्र जारी करे सरकार

नई दिल्ली। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट पर दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. नरेश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले पर एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए और स्पष्ट किया जाए कि पुरानी गाड़ियों को होने वाले संभावित नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी, ई-20 नीति से वास्तविक आर्थिक लाभ किसे मिल रहा है, पेट्रोल की कीमतों में कमी क्यों नहीं की गई और यदि जनता को नुकसान हो रहा है तो उसका लाभ आखिर किसे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन सभी सवालों के स्पष्ट और पारदर्शी जवाब चाहती है। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट के मुद्दे पर डॉ. नरेश ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े कई अहम सवालों के जवाब अभी भी देश की जनता को नहीं मिले हैं। डॉ. नरेश ने कहा कि सरकार का दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, लेकिन यदि पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो पेट्रोल की कीमतों में उसी अनुपात में कमी क्यों नहीं की गई।

महापौर ने दिए स्पा सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली। महापौर प्रवेश वाही ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम के जनस्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में महापौर वाही ने सख्त निर्देश दिए की निगम के नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी स्पा सेंटरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में वाही ने ई-कार्ट पॉलिसी जल्द से जल्द लाने के निर्देश भी दिए। महापौर ने कहा कि लखनऊ एवं मालवीय नगर जैसी घटना दोबारा घटित न हो इस संदर्भ में सख्ती से कार्य करने की जरूरत है। सभी उप स्वास्थ्य अधिकारी अपने क्षेत्रों में हर सप्ताह बैठक करें और सभी क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाते हुए कार्रवाई करें। बैठक में महापौर वाही के अलावा, उप महापौर डॉ मोनिका पंत, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक रावत एवं डॉ लल्लन राम वर्मा सहित सभी 12 क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे।

नई ईवी नीति को लेकर सरकार से लगाई गुहार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई ऑटो-टैक्सी ईवी नीति जो आगामी 1 जनवरी 2027 से लागू होगी पर दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों में रोष के साथ चिंता भी साफ बनी हुई है। ऐसे में ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रकोष्ठ ने नई नीति पर गंभीर चिंता जताई है और सरकार से कुछ मांगे रखी है। संगठनों के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा कि किसी भी नई परिवहन नीति का उद्देश्य केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि लाखों ऑटो-टैक्सी चालकों, उनके परिवारों तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के रोजगार, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की भी समान रूप से रक्षा होनी चाहिए।

रणहौला इलाके का मामला

पत्नी की हत्या के बाद खुद भी जहर खाकर दी जान

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में पत्नी की बैटरी से वार कर हत्या के बाद एक शख्स ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमॉर्टम संजय गांधी अस्पताल में करवाया है।

पुलिस के अनुसार घटना एक महिला की उसके पति द्वारा हत्या की कोशिश की सूचना मिलने पर एक टीम तिलंगपुर कोटला गांव में घटनास्थल पर पहुंची थी। किराये के कमरे की ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने पर विनय नाम के शख्स की पत्नी निशा (24) गंभीर हालत में सिर पर गहरी चोट के साथ मिली। शुरुआती जांच से पता चला कि निशा की शादी विनय से 4-5 साल पहले हुई थी और उनकी लगभग 3 साल की एक बेटी भी है। परिवार पिछले 6-7 महीनों से उस पते पर किरायेदार के तौर पर रह रहा था। विनय उत्तम नगर इलाके में प्राइवेट नौकरी करता था। आगे पता चला कि विनय ने निशा के सिर पर इनवर्टर बैटरी से हमला किया था। उसे गंभीर रूप से घायल करने के बाद, उसने सल्फास की गोलियां खा लीं। इसके बाद वह अपनी 3 साल की बेटी को लेकर अपनी मां के किराये के कमरे पर गया, जो कोटला विहार, फेज-1 में लगभग 150 गज की दूरी पर था। इसके बाद विनय ने अपनी बहन प्रिया को घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि शाम करीब 6 बजे उसने अपनी पत्नी निशा की हत्या कर दी थी क्योंकि वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। उसके बाद उसने भी सल्फास की गोलियां खा ली। उसने बहन प्रिया से निशा की हालत देखने के लिए कहा। प्रिया तुरंत निशा के किराये के कमरे में गई, जहां उसने निशा को खून से लथपथ हालत में पाया। वह घबराकर तुरंत घर से बाहर भागी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी।

पीड़िता निशा और आरोपी विनय दोनों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, मंगोलपुरी ले जाया गया। डॉक्टरों ने निशा को मृत घोषित कर दिया। विनय (28) पुत्र काली चरण को भी मृत घोषित कर दिया गया। दोनों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और शव अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिए गए हैं। इस घटना के संबंध में रणहौला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

युवक की चाकू से हमला कर हत्या

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी जिले के शास्त्री पार्क स्थित डीडीए पार्क में शनिवार सुबह एक 18 वर्षीय युवक की लाश पाई गई। मृतक की पहचान मोहम्मद तौहीद के रूप में हुई है। मृतक पर चाकू से हमला किया गया था। उसके शरीर पर कई जगह चाकू के गहरे घाव मिले हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार तौहीद के पिता मोहसिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। परिवार ने बताया कि रात करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच घर में खाना बन रहा था। गर्मी अधिक होने के कारण तौहीद घर से बाहर गली में टहलने और हवा खाने निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार ने उसे फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। परिवार को रात 1 बजे खोजबीन के दौरान शास्त्री पार्क के डीडीए पार्क से तौहीद की लाश मिली। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश और झगड़ा नहीं था। तौहीद अपने पिता के साथ मजदूरी करता था। पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिये आगे की जांच कर रही है।

सीजेपी का धरना जारी

भूख हड़ताल के सातवें दिन वांगचुक की हालत और खराब

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग व पेपर सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का धरना प्रदर्शन लगातार 15वें दिन शनिवार को भी जारी रहा। वहीं गत सात दिनों से धरना स्थल पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की हालत और खराब होने लगी है।

इस मुद्दे पर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, उनका वजन पांच किलोग्राम से अधिक घट चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम हो रहा है और स्तर और गिरा है, जिसके चलते उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि मेडिकल टीम नियमित जांच कर रही है और जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण किए जा रहे हैं। इस मामले पर दीपके ने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक वांगचुक की भूख हड़ताल जारी रहेगी।

इस बीच समर्थक लगातार जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता जता रहे हैं। वहीं शाम के समय दीपके ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से राजेंद्र नगर पहुंचकर सीधा संवाद किया जिसमें छात्रों ने खुलकर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। दीपके ने कहा कि उनकी आवाज को जंतर-मंतर से उठाई जा रही है जिसे अब और जोर शोर से उठाया जाएगा।

कॉपर वायर चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

■ पांच गिरफ्तार, चार लाख का कॉपर वायर बरामद

महरौली पुलिस ने अंतरराज्यीय चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब चार लाख का कॉपर वायर बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह मोबाइल की बजाय वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन स्थापित करता था। अभी तक की जांच में यह गिरोह दिल्ली एनसीआर में चोरी के 18 मामलों में शामिल पाया गया।

डीसीपी अनंत मित्तल के अनुसार इसी साल 12/13 मई की रात चोरों ने महरौली के इग्नू रोड पर स्थित बिजली के सामान की एक दुकान का शटर तोड़कर तांबे के तार के बंडल व नकदी चोरी की थी। इस संबंध में महरौली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एसीपी सोम नाथ परुथी की देखरेख और एसएचओ रितेश शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने कैमरा फुटेज का विश्लेषण किया, तकनीकी सबूत जुटाए। स्थानीय खुफिया जानकारी विकसित करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि चोरी करने के लिए नकली रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली स्कोडा फैबिया गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। लगातार निगरानी के दौरान आरोपी सोनू को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के साथ पकड़ा गया। उससे चोरी किए गए तांबे के तार के 22 बंडल और दुकान के शटर तोड़ने में इस्तेमाल होने वाली दो लोहे की रॉड बरामद हुई। उसकी जानकारी के आधार पर आरिफ और चांद को गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच में गिरोह के मुख्य साजिशकर्ताओं, अयूब और उबैस को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने बताया कि वे रात के समय खास तौर पर बिजली के सामान की दुकानों को निशाना बनाते थे और बातचीत के लिए वॉकी टॉकी सेट और इंटरनेट डोंगल का इस्तेमाल करते थे, ताकि पुलिस की निगरानी से बच सकें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना पड़े। फरार आरोपी अकबर को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं।

द्वारका मोड़ से रोहित लांबा गिरोह का गुर्गा अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

■ नजफगढ़ में चाकू से हमले के मामले में था वांटेड

क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ में एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह से जुड़े शख्स के सहयोगी पर चाकू हमले के आरोप में रोहित लांबा गिरोह के 22 वर्षीय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि गिरोहों के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता के चलते यह हमला किया गया था।

आरोपी आदित्य कुमार और उसके सहयोगियों रोहित लांबा तथा रितिक ठाकुर ने 26 जून को अफजल पर हमला किया था। उन्हें शक था कि उसने लांबा के ठिकानों के बारे में मोनू को सूचना दी थी। अफजल के बारे में संदेह है कि उसका संबंध प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर मोहित भारद्वाज उर्फ मोनू से है। पुलिस ने बताया कि अपराध को अंजाम देने के पश्चात अपने सहयोगियों के पकड़े जाने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए नजफगढ़ के धरमपुरा निवासी आदित्य फरार था और अपने ठिकाने बदल रहा था। पूछताछ में आदित्य ने पुलिस को बताया कि 26 जून को उनका अफजल से सामना हुआ था। उससे मोनू के ठिकाने के बारे में पूछा गया। जब अफजल ने कोई जानकारी होने से इनकार किया, तो रोहित ने उसके सिर पर पिस्तौल तान दी, जबकि रितिक ने चाकू निकाल लिया।

पुलिस के अनुसार आदित्य ने अफजल को पकड़े रखा, जबकि रोहित और रितिक ने उस पर हमला किया था। गली में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को आता देख आरोपी फरार हो गए थे। इस संबंध में नजफगढ़ थाने ने मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा कि यह हमला लांबा और मोनू के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता का नतीजा था। मोनू नजफगढ़ थाने का बीसी है। लगभग डेढ़ महीने पहले मोनू और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर लांबा पर चाकू से हमला किया था और तब से वे फरार थे। स्थानीय पुलिस के साथ संक्षिप्त गोलीबारी के बाद 28 जून को लांबा और रितिक की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से पुलिस आदित्य को ढूंढ़ रही थी। द्वारका मोड़ के पास जाल बिछाकर आदित्य गिरफ्तार किया गया। आदित्य ने 10वीं तक पढ़ाई की है और लगभग तीन साल पहले रिलायंस स्टोर में काम करते समय उसका संपर्क लांबा से हुआ था। पुलिस ने कहा कि बाद में वह गिरोह का सक्रिय सदस्य बन गया और प्रतिद्वंद्वियों की पहचान करने तथा उन पर हमला करने में मदद करने लगा।

ठक ठक गिरोह के दो बदमाश पकड़े छह लाख नकद व जूलरी बरामद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दक्षिण जिले की एएटीएस ने कुख्यात ठक ठक गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे 6 लाख नकद, लैपटॉप, गहने, स्कूटी और चोरी का अन्य सामान बरामद हुआ। इस ऑपरेशन से दिल्ली और हरियाणा में हुई चोरी की कई घटनाओं का खुलासा करने का दावा किया गया है।

पुलिस के अनुसार हाल ही में ठक ठक गिरोह के दो सक्रिय बदमाशों की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए एएटीएस की एक टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और सफलतापूर्वक गंगेश नायडू और विक्रम को पकड़ लिया। लगातार पूछताछ और तलाशी के बाद चोरी का लैपटॉप, नकद, मोबाइल फोन, गहने, चांदी की वस्तुएं, चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की गई। जांच से पता चला कि दोनों आरोपी एक अंतरराज्यीय ठक ठक गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। वे लोगों का ध्यान भटकाकर गाड़ियों से नकद व कीमती सामान चुराकर भाग जाते थे। गिरोह के अन्य साथियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लिखा जा रहा है नया अध्याय : रेखा

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को मटियाला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' में सम्मिलित हुई। जनसभा को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन और अंत्योदय का नया अध्याय लिखा रहा है। अब दिल्ली भी प्रधानमंत्री के विज़न के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। राजधानी में विकास की नई गति, नई सोच और नई कार्यसंस्कृति के साथ विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक संदीप सहरावत, जिला अध्यक्ष राज शर्मा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्‌घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **आशीष पुत्रः** अशोक **पताः** एन–15/152, निरंकारी कॉलोनी, निरंकारी स्कूल के पास, मुखर्जी नगर, दिल्ली, ने **E-FIR No. 80059030/2024 U/s 411 IPC थानाः मुखर्जी नगर, दिल्ली,** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **आशीष** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **आशीष** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्‌घोषणा की जाती है कि **E-FIR No. 80059030/2024 U/s 411 IPC थानाः मुखर्जी नगर, दिल्ली,** के उक्त अभियुक्त **आशीष** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **10.08.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री अमरदीप कौर
एसीजेएम (एन), कमरा नंबर 117
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/9056/NW/2026
(Court Matter)

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्‌घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **ओमकुमार, पुत्रः** देवेंद्र शर्मा, **पताः** गाँव फरुखाबाद, शिव मंदिर के पास, सेक्टर 73, नोएडा (यूपी) ने **FIR No. 80060951/25 U/s 303(2)/317(2) BNS थानाः सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **ओमकुमार** मिल नहीं रहा हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **ओमकुमार** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उद्‌घोषणा की जाती है कि **FIR No. 80060951/25 U/s 303(2)/317(2) BNS थानाः सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **ओमकुमार** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **06.08.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री दिव्यम लीला
जेएमएफसी–07, कमरा नंबर 508
साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

DP/9041/SE/2026
(Court Matter)

अधिकारियों को दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

सीएम ने लोकार्पण के साथ किया सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र एवं पीतमपुरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्कों के सौंदर्यीकरण, आधुनिक जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में चल रहे विकास कार्यों की

प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत पीतमपुरा स्थित बीडी-एफडी पार्क में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों के लोकार्पण से की। इस अवसर पर पार्क में लगाए गए 93 नए इलेक्ट्रिक पोल एवं आधुनिक लाइट व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सार्वजनिक पार्कों को अधिक सुरक्षित, सुंदर एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बेहतर हरित क्षेत्र न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल नई परियोजनाओं का उद्घाटन करना नहीं, बल्कि प्रत्येक योजना का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। सरकार क्षेत्रवार निरीक्षण के माध्यम से विकास कार्यों की नियमित समीक्षा कर रही है, ताकि नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, आधुनिक सार्वजनिक सेवाएं और स्वच्छ, सुरक्षित एवं विकसित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को जलभराव एवं सीवरेज संबंधी समस्याओं से स्थायी राहत दिलाने के लिए आधुनिक और दीर्घकालिक अवसंरचना विकसित कर रही है।

शालीमार बाग क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग क्षेत्र में वर्षा जल निकासी एवं सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा तैयार की गई विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें डीटी मॉल से सीए ब्लॉक तक दोनों ओर प्रीकास्ट ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण, सीए ब्लॉक से शालीमार विलेज चौक अंडरपास, आरयूबी से जीटी करनाल रोड (आजादपुर मंडी गेट) और शालीमार चौक से डीए ब्लॉक तक आधुनिक जल निकासी प्रणाली का निर्माण शामिल है। साथ ही शालीमार गांव, सहीपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही सीवरेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए अतिरिक्त सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा उससे संबंधित डिलीवरी लाइन का भी लोकार्पण किया गया।

कई इलाकों में हुआ जलभराव

बारिश में फिर बह गए दिल्ली सरकार के दावे, जलभराव ने खोली पोल

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के मानसून पूर्व तैयारियों के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के बुराड़ी, बवाना, नरेला विधानसभा क्षेत्र और आजादपुर के आसपास के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे स्थानीय लोगों को जाम आदि की भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बवाना विधानसभा के 'बेगमपुर', बुराड़ी विधानसभा तथा नरेला विधानसभा के कई हिस्सों में गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि नालियों की समय पर और गहराई से सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निकासी नहीं कर सका और गलियों में भर गया। पल्ला गांव के निवासी नत्थूराम ने जलभराव की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दिल्ली सरकार और एमसीडी की तैयारियों पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि हर वर्ष मानसून से पहले बड़े स्तर पर नालों और नालियों की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पहली ही बारिश में सामने आ जाती है।

गाद और कचरा पूरी तरह नहीं हटाया गया

निवासियों के अनुसार, यदि नालियों से गाद और कचरा पूरी तरह हटाया गया होता तो बारिश का पानी आसानी से निकल जाता और गलियों में जलभराव की नौबत नहीं आती। कई स्थानों पर लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद हर वर्ष वही समस्या क्यों दोहराई जाती है।

नियमित निगरानी और जवाबदेही तय की जाए

ग्रामीणों का कहना है कि दिल्ली सरकार के दावे बारिश में ही धूल जाते हैं जब पानी गलियों में भर जाता है। मानसून पूर्व तैयारियों की नियमित निगरानी और जवाबदेही तय किए बिना जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। बारिश के बाद सामने आई इन तस्वीरों और वीडियो ने एक बार फिर राजधानी की जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

राजधानी के कई क्षेत्रों में जमकर बरसे बादल

नई दिल्ली। दिल्ली में मानसून आगमन के बाद शनिवार को हुई पहली झमाझम बारिश के रूप में दर्ज हुई। बहुत कम समय लेकिन जमकर बरसे बादलों के चलते जगह जगह जलभराव से जाम जैसे हालात देखने को मिले। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आंकड़ों के अनुसार सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे के बीच अधिकृत सफदरजंग वेधशाला ने राजधानी में 29.0 मिमी, बारिश दर्ज हुई। जबकि पालम 27.1 मिमी, लोधी रोड 28.6,रिज 26.3 मिमी, आया नगर 27.6 मिमी, राजघाट 29.5 मिमी, पूसा 28.1 मिमी, नजफ़गढ़ 28.4 और मयूर विहार 29.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। आईएमडी के अनुसार सुबह से ही दम घोटू उमस बनी हुई थी। सुबह सापेक्ष आर्द्रता 77 प्रतिशत दर्ज की गई और दिन में अधिकांश समय आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश देखने को मिली। आईएमडी ने गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। बाद में कुछ हिस्सों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी और हवाओं, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ बारिश होने लगी। आईएमडी के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 1.6 डिग्री नीचे है। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा। ताजा अनुमान में आईएमडी ने बताया है कि 10 जुलाई तक हल्की मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। बता दें कि दिल्ली में इस बारे देरी के बाद दो जुलाई को मानसून ने दस्तक दी थी। लेकिन पहले दो दिन मानसून ने निराश किया और बारिश के नाम पर खानापूर्ति से ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन शनिवार को हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी होगी।

दिल्ली सरकार ने 52 अधिकारियों का किया स्थानांतरण

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

■ 19 अधिकारियों को दी गई पदोन्नति

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को और मजबूत करने की दिशा में वित्त एवं लेखा विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति के तहत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत 52 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इनमें 23 डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स और 29 वरिष्ठ लेखाधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग में कार्यकुशल अधिकारियों को जिम्मेदारी का दायरा बढ़ाते हुए 19 वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर) को पदोन्नत कर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पारदर्शी और जवाबदेह शासन के संकल्प के अनुरूप किए गए इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना, वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाना तथा विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और गतिशीलता सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और सुशासन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर शिथिलता, लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। वित्त एवं लेखा विभाग में किया गया यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल इसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कार्य संस्कृति को अधिक उत्तरदायी, परिणामोन्मुख और जनहित केंद्रित बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का मानना है कि समयबद्ध निर्णय, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेह प्रशासन से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक गति आएगी तथा जनता को सेवाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और कुशल तरीके से मिल सकेगा। इसी क्रम में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थलों पर कार्यभार ग्रहण कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

कांग्रेस ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री पंकज दे इस्तीफा

दवा खरीद घोटाले की हो 12 वर्ष की जांच

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) दवा खरीद घोटाले की जांच का दायरा पिछले 12 वर्षों तक बढ़ाने तथा सभी दवा खरीद, टेंडर, रेट कॉन्ट्रैक्ट, लोकल परचेज, गुणवत्ता परीक्षण तथा एक्सपायर दवाओं से जुड़े मामलों की व्यापक एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दवा घोटाले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ.पंकज कुमार सिंह के इस्तीफे की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दर्ज दोनों एफआईआर के साथ-साथ पूर्व वर्षों में प्राप्त सभी शिकायतों, सतर्कता जांचों, सीएजी ऑडिट टिप्पणियों तथा अन्य एजेंसियों की रिपोर्टों को भी इस जांच का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

यादव ने कहा कि दिल्ली में हजारों करोड़ रुपये के इस कथित सीपीए घोटाले की नींव वर्ष 2017 में रखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय दिल्ली की जरूरी दवाओं की सूची में लगभग 1,390 दवाएं शामिल थीं, किन्तु 1 अगस्त 2017 से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में लगभग 490 दवाओं को आवश्यक दवा सूची से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद सरकारी अस्पतालों को बड़े पैमाने पर लोकल परचेज का सहारा लेना पड़ा, जिससे खरीद प्रक्रिया बिखर गई, पारदर्शिता कमजोर हुई, प्रतिस्पर्धी निविदा व्यवस्था प्रभावित हुई तथा कमीशन आधारित खरीद के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न हुए। यादव ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान सीपीए आवश्यक दवाओं की समय पर आपूर्ति करने में विफल रहा, जिसके कारण अस्पतालों को अपनी आवश्यक 33 से 47 प्रतिशत आवश्यक दवाएं स्थानीय स्तर पर खरीदनी पड़ीं। ऑडिट में यह भी पाया गया कि पिछले दस वर्षों में आवश्यक दवा सूची का वार्षिक पुनरीक्षण नहीं किया गया और इसे केवल तीन बार तैयार किया गया। इसी प्रकार चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए जारी 86 टेंडरों में से केवल 24 को ही अंतिम रूप दिया गया तथा कई अस्पतालों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं।

भाजपा ने निगम के शिक्षा विभाग को भी बना दिया है भ्रष्टाचार का अड्डाः अंकुश

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने शासन में आने के बाद एमसीडी के शिक्षा विभाग को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। नारंग ने शिक्षा विभाग में मनमाने तरीके से शिक्षकों के तबादले पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए पूछा कि भाजपा बताए कि ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम बंद कर पर्ची सिस्टम क्यों लागू किया गया। भ्रष्टाचार के चलते ही ऑनलाइन प्रक्रिया को दरकिनार कर मनमाने तरीके से 550 शिक्षकों का ऑफलाइन ट्रांसफर किया गया है। आखिर क्यों नरेला के शिक्षक को घर से 30 से 40 किमी दूर शाहदरा भेज दिया, जहां रोज ड्यूटी आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है। नारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या महापौर प्रवेश वाही, उप महापौर और चेयरमैन मिलकर ट्रांसफर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह सीधे सीधे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ और शिक्षकों का उत्पीड़न है जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। नारंग ने कहा कि एमसीडी के शिक्षक सिविक सेंटर स्थित मेयर ऑफिस के बाहर धरना देने को मजबूर हैं। हालात यह है कि नरेला में रहने वाले शिक्षक को 50 किमी दूर शाहदरा भेज दिया गया है, जहां से उन्हें रोज आना-जाना पड़ेगा।

निगम में 50 करोड़ की कथित संगठित वसूली का आरोप

उपराज्यपाल से सीबीआई जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सिविल लाइंस जोन में कथित रूप से 50 करोड़ रुपये के संगठित वसूली रैकेट का मामला सामने आया है। एनजीओ 'मेरा अधिकार' के अध्यक्ष अश्वनी बागड़ी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को विस्तृत शिकायत भेजकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप, सीबीआई जांच और संबंधित अधिकारियों के निलंबन की मांग की है।

शिकायत में उपायुक्त (डीसी) सहित निगम के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है कि कथित रूप से फर्जी नोटिस जारी कर औद्योगिक इकाइयों और गोदाम संचालकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली की गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि वसूली के बाद संबंधित मामलों में न तो सीलिंग की कार्रवाई हुई और न ही अन्य वैधानिक कार्रवाई, जिससे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई गई है। उपराज्यपाल को भेजे गए पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, एमसीडी आयुक्त और मुख्य सतर्कता अधिकारी से भी मामले की स्वतंत्र जांच कराने, आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने, प्राथमिकी दर्ज कराने तथा संबंधित एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।

गोदामों को जारी किए गए फर्जी नोटिस

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सिविल लाइन जोन के उपायुक्त, सहायक आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कर्मियों द्वारा सिविल लाइन जोन में लगभग 1000 से अधिक फैक्ट्री/गोदामों को फर्जी नोटिस जारी किए और प्रति नोटिस 5-10 लाख रुपये की अवैध वसूली की गई है। वसूली लेने के बाद एक भी नोटिस पर सीलिंग/डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अनुमानित 50 करोड़ रुपये की अवैध वसूली हुई है।

कुछ कर्मियों की हुई विवादित पदस्थापना

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एमसीडी के सतर्कता विभाग के पूर्व आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ कर्मियों की विवादित पदस्थापना की गई। साथ ही सीवीसी में शिकायत और बाद में जारी स्थानांतरण आदेशों के बावजूद संबंधित कर्मियों को कार्यमुक्त नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। अश्वनी बागड़ी ने दावा किया है कि उन्होंने फरवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक एमसीडी, पुलिस, सीवीसी और सीबीआई सहित विभिन्न स्तरों पर कई शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

सुविधा शिविर में आईं 60 शिकायतें, तत्काल शुरू हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की ओर से शनिवार को नई दिल्ली के जय सिंह रोड स्थित एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में सुविधा शिविर का आयोजन किया। इस सुविधा शिविर में कुल 60 शिकायतें दर्ज की गईं, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्राप्त शिकायतें मुख्यतः कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, उद्यान, जन स्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्यिक, कर तथा संपदा विभाग से संबंधित थीं। शिकायत दर्ज कराने के अतिरिक्त बड़ी संख्या में नागरिकों एवं सेवा उपभोक्ताओं ने शिविर में पहुंचकर एनडीएमसी द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न नागरिक सेवाओं, जनकल्याणकारी पहलों तथा नागरिक हितैषी सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इस शिविर में नागरिकों को वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से आमने-सामने संवाद करने का अवसर मिला, जिससे उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने तथा उनके शीघ्र एवं प्रभावी समाधान में सहायता मिली। नीति-स्तर के निर्णयों से जुड़े मामलों में नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया एवं उनके निस्तारण की संभावित समय-सीमा से भी अवगत कराया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जनविश्वास को और मजबूती मिली। इस सुविधा शिविर में एनडीएमसी के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया और एक ही छत के नीचे समन्वित एवं त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित किया।

मुख्यमंत्री ने द्वारका में किया सोलर प्लांट का उद्घाटन

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को द्वारका स्थित एयर फोर्स एवं नेवल ऑफिसर्स एन्क्लेव में 500 किलोवॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखकर प्रसन्नता होती है कि अब आवासीय कॉलोनियां और सामुदायिक परिसर भी सोलर अपनाकर स्वच्छ, किफायती और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह परिवर्तन जितना पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'पीएम सूर्य घर योजना' के माध्यम से दिल्ली के पात्र परिवार रूफटॉप सोलर लगाकर 1 लाख रुपए से अधिक तक का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक कुलदीप सोलंकी, पूर्व विधायक धर्म देव सोलंकी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

जापानी पार्क से विनोबा कुंज तक निकाला बेरोजगार पैदल मार्च

पूर्व बस मार्शलों ने विधानसभा अध्यक्ष के आवास का किया घेराव

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

स्थायी रोजगार की मांग को लेकर दिल्ली सिविल डिफेंस के पूर्व बस मार्शलों ने शनिवार को रोहिणी स्थित जापानी पार्क से विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के निजी आवास विनोबा कुंज तक करीब तीन किलोमीटर लंबा 'बेरोजगार पैदल मार्च' निकाला।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बनने के 60 दिनों के भीतर रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 500 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद उनकी बहाली नहीं हुई। धरना स्थल पर मौजूद पूर्व बस मार्शल प्रतिनिधि मुकेश पाल सिंह ने कहा कि उन्होंने बातचीत और शांतिपूर्ण विरोध के सभी लोकतांत्रिक रास्ते अपनाए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। प्राप्त जानकारी के अनुसार, धरने में नरेंद्र कुमार राय, मुकेश पाल सिंह, विनोद कुमार पाल, आदित्य, रूबी, उर्मिला, कृपाशंकर, पारस ठाकुर, राजीव लाकड़ा, शिवम मौर्य सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पूर्व बस मार्शल शामिल रहे। उन्होंने घोषणा की कि अब आंदोलन को पूरे दिल्ली स्तर पर ले जाया जाएगा और आने वाले दिनों में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के आवासों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का करते रहे इंतजार

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, धरने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के निजी सहायक दो बार ज्ञापन लेने पहुंचे। हालांकि, बस मार्शलों ने कहा कि वे पहले ही कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं और अब वे चाहते हैं कि उनकी बात सीधे विधानसभा अध्यक्ष सुनें। उनका आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष उनसे मिलने नहीं आए और शाम को आवास से बिना बातचीत किए रवाना हो गए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पैदल मार्च और पूरे प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी तथा शांतिपूर्ण आयोजन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

बस मार्शलों ने पोस्टर और बैनर लेकर हिस्सा लिया

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, सुबह करीब 9 बजे शुरू हुए मार्च में महिला और पुरुष पूर्व बस मार्शलों ने पोस्टर और बैनर लेकर हिस्सा लिया। विनोबा कुंज पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और '60 दिन का वादा, 500 दिन धोखा' जैसे नारे लगाए। धरना लगभग छह घंटे तक चला।

बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में 10 हजार से अधिक बस मार्शलों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। तब से वे अपनी बहाली और स्थायी रोजगार की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।

वृक्षारोपण से मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरणः इन्द्राज

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

वृक्षारोपण केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का संकल्प है। जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतना ही ज्यादा वातावरण स्वस्थ होगा। सहकार से समृद्धि-सहकारिता सप्ताह 2026 के अंतर्गत शनिवार को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने द्वारका के सेक्टर- 24 स्थित ग्राम धूलसीरस में आयोजित वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर यह संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि पर्यावरण संरक्षण को अपना दायित्व मानते हुए एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो दिल्ली को अधिक हरित एवं प्रदूषण-मुक्त बनाया जा सकता है। मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि यह अभियान सहकारिता विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण (ग्रीन कवर) बढ़ाने तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर वार्ड द्वारका-सी की निगम पार्षद सुनीता रामनिवास पहलवान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने एक और सड़क किनारे बनी अवैध मजार हटाई

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गाजियाबाद

गाजियाबाद के जिला प्रशासन का अवैध मजारों के खिलाफ़ अभियान अभी भी जारी है। शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ सड़क किनारे बनाई गई एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। यह मजार लोनी क्षेत्र स्थित इंदिरा मार्केट में लोनी–गाजियाबाद मुख्य मार्ग के किनारे पर कई वर्ष पुरानी थी। प्रशासन के अनुसार, सड़क के किनारे बने इस अवैध निर्माण के कारण लंबे समय से यातायात प्रभावित हो रहा था तथा अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी। आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। इससे पहले भी जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त करवाई में कई मजार ध्वस्त की जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि धवस्त की गई सभी मजारे अवैध थी।ध्वस्तीकरण अभियान का नेतृत्व एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल ने किया।

ध्वस्त की गई सभी मजारे अवैध थी

उनके साथ नायब तहसीलदार लीलू सिंह, सूचना अधिकारी योगेंद्र सिंह तथा पुलिस विभाग से डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी, एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम एवं एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त लोनी क्षेत्र के छह थानों के प्रभारी निरीक्षक अपने-अपने पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। आवश्यकता के मद्देनज़र पिलखुवा क्षेत्र से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूरे अभियान के दौरान लगभग 300 पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिन्होंने क्षेत्र की घेराबंदी कर कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। इसके साथ ही लोगों द्वारा किए गए अस्थायी अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया, जिससे लोनी तिराहे पर यातायात बाधित हो रहा था। इस कार्रवाई के बाद यातायात व्यवस्था सुचारु हुई तथा आमजन को आवागमन में सुविधा प्राप्त हुई।

जिला प्रशासन का अवैध मजारों के खिलाफ़ अभियान जारी

अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार अभियान जारी रहेगा

अधिकारियों ने बताया कि अवैध निर्माण के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित होती थी और राहगीरों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता था। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को हटाया गया, जिससे अब सड़क पर यातायात पहले की अपेक्षा अधिक सुगम होने की उम्मीद है। कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया तथा संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक भूमि पर दोबारा किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों और अतिक्रमण के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार अभियान जारी रहेगा।

खबर संक्षेप

निवेश के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी

फरीदाबाद। स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर 10,00098 रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर थाना

सेंट्रल की टीम ने कार्रवाई करते हुये द्वितीय लेयर के खाताधारक सहित 3 आरोपियों को 1 जुलाई को गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान सिदांत निवासी रोहिणी दिल्ली, कपिल निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश व मनप्रीत निवासी गांव महिपालपुर दिल्ली को गिरफ्तार किया है। सिदांत व कपिल को देहरादून व मनप्रीत को फरीदाबाद सेक्टर 17 से काबू किया था। जांच में सामने आया कि घटनाक्रम में ठगी के 10,00,098 रुपए प्रथम लेयर के दो खातों में ट्रांसफर किये गये थे। इसके बाद द्वितीय लेयर में आरोपी सिदांत के खाता में ठगी की राशि में से 104000 रुपये आये थे। सिदांत द्वितीय लेयर का खाताधारक है, जिसने अपना खाता कपिल व कपिल ने यह खाता आगे मनप्रीत को दे दिया था। आरोपी ग्रेजुएट है। आरोपितों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उन्होंने डेढ़ लाख रुपये जमा कराये, जिस पर उनकी जमानत मंजूर हुई है।

रंजिश के चलते किया था हमला एक गिरफ्तार

फरीदाबाद। आपसी रंजिश के चलते धीरज नगर निवासी एक व्यक्ति पर हमला कर घायल करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3

जुलाई को थाना पल्ला की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अरुण निवासी धीरज नगर फरीदाबाद के रूप में हुई है। जिसको माननीय न्यायलय में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता अनुसार प्रवीण निवासी धीरज नगर ने थाना पल्ला में दी अपनी शिकायत में बताया कि 28 जून को उसका भाई ब्रिजेश अपने प्लाट गिरदावर इंक्लेव पर गया था। जहां ललित उर्फ लाला, प्रिंस, महिपाल व अरुण ने उस पर फावडा व पाईप से हमला कर दिया था। जिसकी शिकायत पर थाना पल्ला में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपितगण व शिकायतकर्ता पहले पड़ोसी थे।

अपनी चिंताओं से अवगत कराया

सोतई गांव में प्रस्तावित कूड़ा डंपिंग यार्ड को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री राजेश नागर से की मुलाकात

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

सोतई गांव में निगम द्वारा प्रस्तावित कूड़ा डंपिंग यार्ड के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर से मुलाकात की और अपनी चिंताओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि क्षेत्र में बनाए जा रहे डंपिंग यार्ड को तत्काल प्रभाव से अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि क्षेत्र की आबादी को संभावित प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके।

ग्रामीणों ने मंत्री राजेश नागर को बताया कि लगभग दो वर्ष पूर्व भी प्रशासन द्वारा इसी स्थान पर कूड़ा डंपिंग यार्ड स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस समय आपके सहयोग के कारण सरकार ने जनभावनाओं को समझा और डंपिंग यार्ड को वहां से हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब एक बार फिर प्रशासन उसी स्थान पर डंपिंग यार्ड विकसित करने की तैयारी कर

रहा है, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि सोतई गांव में कूड़ा डंपिंग यार्ड स्थापित किया जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के दर्जनों गांव इसकी चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने आशंका जताई कि डंपिंग यार्ड से निकलने वाली दुर्गंध, प्रदूषित जल और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करेंगे तथा लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए मंत्री राजेश नागर ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और चिंताओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और पर्यावरणीय चिंताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर वे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराएंगे।

ग्रामीणों की मांग को उचित मंच पर रखा जाएगा

मंत्री राजेश नागर ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा उठाई गई चिंताएं काफी हद तक उचित प्रतीत होती हैं और सरकार जनहित से जुड़े हर विषय पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ग्रामीणों की मांग को उचित मंच पर रखा जाएगा और ऐसा समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा जिससे आम जनता के हित सुरक्षित रह सकें तथा क्षेत्र का संतुलित विकास भी जारी रहे। फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा, सोतई गांव के पूर्व सरपंच भोली रावत, संतोष सिंह, हरिंदर आदि।

पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की

ऑटो लूटने के मामले में 4 गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर लेकर की जाएगी बरामदगी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

बीते 30 जून को थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के अंतर्गत एनएचपीसी चौक के पास एक ऑटो चालक से ऑटो, फोन व पैसे लूटने के मामले में अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम ने 3 जुलाई को 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जिनकी पहचान सुमरन व नितिन निवासी ओल्ड फरीदाबाद, मदन निवासी बल्लभगढ़ व सुभाष निवासी खेडीपुल के रूप में हुई है।

जिनको न्यायालय में पेश कर बरामदगी करने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव ने बताया कि 30 जून की रात को आरोपी ओल्ड फरीदाबाद से शिकायतकर्ता के ऑटो में सवारी बनकर बैठे थे। मदन, नितिन, सुमरन पीछे व सुभाष आगे बैठ गया था। जब एनएचपीसी फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो सुमरन ने ऑटो चालक की गर्दन पर चाकू लगा दिया और तीनों ने उसका फोन व जैब में रखे पैसे निकाल लिये तथा ऑटो सहित वहां से फरार हो गये।

घटना के मास्टरमाइंड का आपराधिक रिकार्ड रहा है

सुभाष इस घटना का मास्टरमाइंड है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक रिकार्ड रहा है। नितिन का भी आपराधिक रिकार्ड है। उन्होंने और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि 1 जुलाई को संदीप निवासी अनखीर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ के बीच ऑटो चलाता है। 30 जून की रात को समय करीब 9.30 बजे 4 लड़के ओल्ड चौक फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर जाने के लिए उसके ऑटो में बैठे थे। जब एनएचपीसी फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो पीछे बैठे एक लड़के ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसका ऑटो, फोन व पैसे छीनकर वहां से फरार हो गये। शिकायत पर थाना सराय ख्वाजा में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

14 अगस्त को भव्य महिला सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा

पूर्व आईएएस सुनीता वर्मा हरियाणा महिला स्वर्णकार संगठन की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त, सौंपी जिम्मेदारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

हरियाणा महिला स्वर्णकार संगठन ने प्रदेश एवं जिला स्तर पर नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए समाज की सक्रिय एवं प्रतिष्ठित महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हरियाणा सरकार में अनेक उच्च प्रशासनिक पदों पर

अपनी सेवाएं दे चुकीं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुनीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। वहीं प्रदेश महासचिव के पद पर उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता सपना वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। फरीदाबाद जिला इकाई में प्रख्यात कवयित्री डॉ. अनिता सोनी को जिला अध्यक्ष, कविता सोनी को जिला उपाध्यक्ष तथा इंदिरा वर्मा को जिला महासचिव एवं प्रीति वर्मा, मधु वर्मा, उपाध्यक्ष कविता वर्मा, सचिव जुही वर्मा, कविता वर्मा एडवोकेट, उपाध्यक्ष करषका कपिल, नीलम वर्मा, रितु वर्मा कमेटी मे नियुक्त किया गया है।

संगठन के वरिष्ठ सदस्यों एवं समाज के गणमान्य लोगों ने सर्वसम्मति से इन सशक्त महिलाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए विश्वास व्यक्त किया।

टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पत्नी को भी मारने का था इरादा

पत्नी के प्रेमी को सिर में मारी थी गोली, इलाज के दौरान मृत्यु

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

बीते 30 जून की रात को राजीव कॉलोनी स्थित किराए के मकान की छत पर सो रहे विपिन यादव निवासी विनायकपुर जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश के सिर में गोली मार दी गई थी। घटनाक्रम बारे जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला ने अपने पति पर गोली मारने का आरोप लगाया था।

जिसकी शिकायत पर थाना सेक्टर-58 में हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। 2 जुलाई की रात को विपिन की इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर दिल्ली में मृत्यु हो गई, जिस पर हत्या की धारा मामले में जोड़ी गई है।

एसीपी क्राईम अमन यादव ने बताया कि घटनाक्रम में निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई के लिए अनुसंधान अपराध शाखा सेक्टर-56 को सौंपा गया। अपराध शाखा प्रभारी उप निरीक्षक नरेश कुमार ने सूरज के नेतृत्व में एक टीम गठित की।

3 जुलाई को आरोपी को यूपी के जेसीबी चौक से गिरफ्तार किया

टीम ने जिला मैनपुरी, कानपुर उत्तर प्रदेश व फरीदाबाद के आसपास के क्षेत्र में लगातार रेड की और तकनीकी सहायता व गुप्त सूत्रों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई को आरोपी विजय निवासी नंगला पीपल जिला मैनपुरी हाल जसवंत नगर मोहल्ला जिला इटावा उत्तर प्रदेश को जेसीबी चौक के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। न्यायालय में पेशकर आगामी कार्रवाई के लिये पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा।

निर्माणाधीन इमारत के छज्जे पर सो रहा था कर्मी

छठी मंजिल से गिरने से कंपनी कर्मी की मौत

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गुरुग्राम

खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के गांव भांगरोला स्थित एक निर्माणाधीन इमारत की छठी मंजिल से गिरने पर एक कंपनी कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वह निर्माणाधीन इमारत के छज्जे पर सो रहा था।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी अनुसार, उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी 37 वर्षीय जय प्रकाश गुरुग्राम के गांव भांगरोला में किराये के कमरे में अकेले रहता था। वह एक निजी कंपनी में कार्यरत था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 2 जुलाई की रात वह शराब के नशे में निर्माणाधीन इमारत की छठी मंजिल के छज्जे पर सो गया था। आशंका है कि नींद के दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे राहगीरों ने इमारत के नीचे उसका शव पड़ा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खेड़कीदौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गो हेल्दी विद ताइवान 2026: स्वास्थ्य नवाचारों को मिलेगा वैश्विक मंच

गुरुग्राम। स्वास्थ्य और वेलनेस क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गो हेल्दी विद ताइवान 2026 अभियान के तहत इस वर्ष टॉप 20 मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस पहल के माध्यम से भारत सहित दुनिया भर के स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और नवप्रवर्तकों को अपने अभिनव विचारों को व्यावसायिक रूप देने और वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस अभियान का संचालन ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल कर रही है। अभियान की थीम डिजायनिंग हैल्थियर फ्यूसर टूगैदर रखी गई है। जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।

शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़

फरीदाबाद। गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिन्दूवादी नेता बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार पांचाल के साथ शादी करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड करते हुए क्राईम ब्रांच सेक्टर-48 की टीम ने पति-पत्नी सहित 5 आरोपियों को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 3 जुलाई को काबू करने में सफलता हासिल की है। जिनकी पहचान दानिश चमन, महविश दानिश महिला, सचिन, संजीव निवासी अलीगढ व प्रदीप निवासी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर आगामी पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस प्रवक्ता अनुसार थाना सारन में राजकुमार पांचाल की शिकायत पर शादी का झांसा देकर 40000 से अधिक की ठगी करने के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। जिसने अपनी शिकायत में बताया था कि उसको लड़की देखने के लिए 2-3 बार अलीगढ उत्तर प्रदेश बुलाया गया।

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

भारतीय गणित ओलंपियाड पात्रता परीक्षा (IOQM) 2026-27

भारतीय राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (INMO) 2027 में भाग लेने के इच्छुक छात्रों के लिए, राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड पात्रता परीक्षा (IOQM) में शामिल होना अनिवार्य है।
यह परीक्षा 6 सितंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी।
IOQM में सफल होने वाले छात्र INMO 2027 में भाग लेने के पात्र होंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड (IMO) 2027 और यूरोपीय गर्ल्स गणित ओलंपियाड (EGMO) 2028 में भारतीय टीम के आधिकारिक सदस्य के रूप में भागीदारी की दिशा में पहला चरण है।

अधिक जानकारी और पंजीकरण लिंक:
https://olympiads.hbcse.tifr.res.in एवं https://www.mtai.org.in/

पंजीकरण संबंधित परीक्षा केंद्रों पर सीधे किया जा सकता है
इसके अलावा, ऑनलाइन पंजीकरण भी **29 जून 2026** से शुरू होगा
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वेबसाइट: **https://ioqm.mtai.org.in/**

पंजीकरण की अंतिम तिथि: 25 जुलाई 2026

CBC 48143/11/0004/2627

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएसएस देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **सलमान पुत्रः रियाजुद्दीन पताः सी–554, अमन विहार, दिल्ली** ने case **FIR No. 264/2022 U/s 323/341 IPC, थानाः अमन विहार, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सलमान** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **सलमान** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि case **FIR No. 264/2022 U/s 323/341 IPC, थानाः अमन विहार, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **सलमान** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद / मुकद्मा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 31.08.2026** को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
सुश्री शगुन
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
उत्तर पश्चिम, कोर्ट नं. 109, प्रथम तल
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

DP/8939/RD/2026 (Court Matter)

सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने तैयार

कांग्रेसियों ने 2027 के चुनाव के लिए कसी कमर, जिलाध्यक्ष ने की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों से संवाद स्थापित किया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ गाजियाबाद

कांग्रेसियों ने 2027के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने शनिवार को जिला कार्यालय पर तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बैठक में जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को पूरी मजबूती और गंभीरता से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि नेतृत्व का स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यदि किसी प्रकार का गठबंधन होता है तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़े-भाई की भूमिका निभाने की स्थिति में चुनाव मे उतरेगी। उन्होंने कहा कि

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, संभावित विधानसभा प्रत्याशियों की तैयारी शुरू करने तथा प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी गाजियाबाद ने भी विधानसभा स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है।

बैठक में नई मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन, बूथ एवं ब्लॉक अध्यक्षों की समितियों के गठन और संगठनात्मक विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक माह जिला अध्यक्ष की निगरानी में विधानसभा-स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाग लेंगे।

इन बैठकों में क्षेत्र की जनसमस्याओं की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक होने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से भी संवाद स्थापित किया जाएगा। बैठक में प्रदेश और देश के ज्वलंत मुद्दों नीट परीक्षा पेपर लीक, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा हाल ही में राम मंदिर में हुई चोरी की घटना पर भी गंभीर चर्चा हुई।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे

गाजियाबाद में कांग्रेस संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरेगी। बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से बैठक में मेरठ से आए (शिक्षक) के लिए सुनील कुमार भारद्वाज सैनिक प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कर्नल सुधीर कुमार, अश्विनी त्यागी, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार शर्मा, बीडी दुबे, रिजवान मलिक, अलीमुद्दीन कसर, आशुतोष गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी विनोद धाम, डोली त्यागी महिला जिला अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार, आबिद अनवर कुरैशी, राजू शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, रूप किशोर, हाजी खुर्शीद, बाबूराम आर्य, सविता जयसवाल, रूबी मलिक शामिल रहे।

खबर संक्षेप

जुलाई में सिर्फ पढ़ाई नहीं डिजिटल ट्रेनिंग भी

लखनऊ। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सरकार माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक

सीमित न रखकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बना रही है। जुलाई में प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन के साथ बोर्ड परीक्षा आवेदन प्रक्रिया, सतत मूल्यांकन, डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक गतिविधियों व करियर मार्गदर्शन का व्यापक अभियान चलेगा।

राजू सिंह को एक गलती से विधायकी पर खतरा

मुजफ्फरपुर। जिले के साहेबगंज से भाजपा के विधायक राजू सिंह को विधानसभा की सदस्यता से

हाथ धोना पड़ सकता है। करीब साढ़े 7 साल पहले एक गलती की वजह से उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा गया है। उन्हें दिल्ली की अदालत ने गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। मामला 31 दिसंबर 2018 को नए साल के जश्न के मौके पर आयोजित एक पार्टी का है।

गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर

धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई

की है। पुलिस ने अदालत के आदेश के तहत उसके घर पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई भी की है। बता दें कि लंबे समय से फरार प्रिंस खान पर हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आगे भी आरोपी के खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में चल रही फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने अब बड़े स्तर पर परिणाम देना शुरू कर दिया है।

किसानों की डिजिटल पहचान की ओर तेजी से बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

फार्मर रजिस्ट्री में 2.38 करोड़ से अधिक किसानों का हुआ पंजीकरण, लक्ष्य का 82.69% कार्य पूरा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से डिजिटल कृषि व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में चल रही फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने अब बड़े स्तर पर परिणाम देना शुरू कर दिया है।

यूपी के गाजियाबाद और रामपुर में 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो गया है। प्रदेश सरकार की सक्रिय पहल के चलते अब तक 2.38 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 82.69 प्रतिशत है। प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से की गई थी।

केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान प्रगति के अनुसार अब तक 2, 38,72,418 किसानों का नामांकन किया जा चुका है, जबकि लगभग 49,98,007 किसानों का पंजीकरण अभी शेष है।

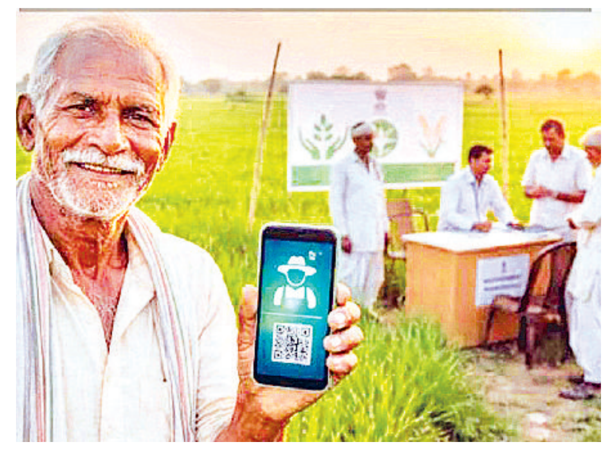

विवादों को कम करने में मदद मिलेगी

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि और किसानों के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना भी है। इसी क्रम में "अंश निर्धारण" का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अंश निर्धारण का कार्य 87.53 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इससे भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता बढ़ेगी और भविष्य में विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।

ताकि योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिले

योगी सरकार ने इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, कृषि विभाग और स्थानीय स्तर के कर्मचारियों को तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि अनुदान, ऋण सुविधा और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सके।

लखनऊ व प्रयागराज में गठित हुई विशेष बेंच, हर बुधवार को होगी सुनवाई

योगी सरकार का बड़ा फैसला

3 सदस्यीय पीठ करेगी शासकीय भूमि से जुड़े वादों की सुनवाई,सभी वाद होंगे सूचीबद्ध

अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति (यदि कोई हो) से संबंधित सभी वादों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

योगी सरकार प्रदेश में राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण सुधार कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बड़ा निर्णय लिया है।

धारा-9 के तहत लागू की गई नई व्यवस्था

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, भूमि विवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा राजस्व न्याय प्रणाली को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल देते रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गयी है। इसका उद्देश्य इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है, जिसके तहत लखनऊ एवं प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणी के सभी लंबित और नए वाद अब विशेष रूप से गठित तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

राजस्व व्यवस्था को बनाया अधिक उत्तरदायी

योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है। डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया तथा सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है। अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ का गठन इसी सुधार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी है। विशेषज्ञतापूर्ण सामूहिक निर्णय व्यवस्था से न केवल न्याय वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनेगी, बल्कि प्रदेश में राजस्व न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण को भी नई गति मिलेगी।

विशेष पीठ हर बुधवार को करेगी मामलों की सुनवाई

परिषद की अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण संभव होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता भी स्थापित होगी। वहीं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस श्रेणी के सभी लंबित एवं नए वादों की पहचान कर उन्हें निर्धारित विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराया जाए। इससे नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और मामलों के अनावश्यक लंबित रहने की संभावना भी कम होगी।

वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल

गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्रसंस्करण व निर्यात से बढ़ेगी किसानों की आय

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026 के तहत आम क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आम उत्पादकों, कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओ और निर्यातकों ने उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान गुणवत्तायुक्त आम की आपूर्ति और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यपाल ने ग्लोबल गैप प्रमाणन, वैज्ञानिक तुड़ाई, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और निर्यात संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

आत्मनिर्भर बनने पर जोर

कृषि विज्ञान केंद्रों को संसाधन संपन्न बनाने, सरकारी अनुदान का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने तथा महिलाओं को अचार, मुरब्बा और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों के प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने जनभवन में विकसित चंदन वाटिका, नक्षत्र वाटिका, स्केटिंग रिंग और स्पेस लैब जैसे नवाचारों का प्रदेशभर में विस्तार करने की भी बात कही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों से प्रसंस्करण और निर्यात को अपनाकर 'लोकल से ग्लोबल' की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

पेज एक का शेष

असंभव मामलों का निकाला ...

करती है। जन विश्वास सुधार जैसी पहलों ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा दिया है और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ने में योगदान दिया है। परिणाम सबके सामने है, जिसमें भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। 12 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। जबकि यूनिकॉर्न 4 से बढ़कर 125 हो गए हैं।

भ्रम में फंसने ...

भी करते हैं। इसके अलावा ई-20 कोई नया प्रयोग नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और जापान जैसे कई विकसित देशों में इसका इस्तेमाल सालों से सफलता के साथ किया जा रहा है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) की जांच में भी सामने आया है कि इससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो वाहन ई-20 के लिए प्रमाणित हैं, उनकी वारंटी और बीमा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। सरकार ने गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाने वाले वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा है कि ईंधन ग्रेड का एथेनॉल एक सख्त औद्योगिक प्रक्रिया से बनता है, जिसमें चीनी का अंश नहीं होता है, इसलिए गाड़ियों में चींटियां लगने की बात वैज्ञानिक रूप से गलत है। सरकार के अनुसार, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से देश को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। इस नीति के कारण भारत को तेल आयात में 1.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इसके साथ ही देश के किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है, जबकि कच्चे तेल के आयात में 310 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी भारी मदद मिली है, इसलिए वाहन मालिकों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

पर्यावरण के लिए यह अच्छा-गुलाटी : टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी ने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में समय समय पर कई सारे रेगुलेशन करने पड़ते हैं। ई-20 पर्यावरण के लिए अच्छा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है और जब पर्यावरण को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, ऐसे में ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।

यह जांची-परखी साइंटिफिक ...

एक्सपर्ट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने यह बात कही। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था।

ई-20 के ....

अपनी गाड़ियों को ई-20 पेट्रोल के हिसाब से ही बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल से गाड़ी के इंजन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। माइलेज के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि ई 20 पेट्रोल से गाड़ी की माइलेज में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि इसके कई फायदे भी हैं।

ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ...

प्रधानमंत्री 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान इस स्टेडियम की छत को बंद रखना चाहिए। वरना वह अपनी मौत के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे'।

इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड जाएंगे पीएम: बताते चलें कि पीएम मोदी की यह ऑस्ट्रेलिया यात्रा अगले सप्ताह सोमवार 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की जाने वाली हिंद-प्रशांत क्षेत्र के तीन देशों की यात्रा से जुड़ी हुई है। जिसकी शुरुआत वह 6 जुलाई को इंडोनेशिया से करेंगे और उसका दूसरा पड़ाव ऑस्ट्रेलिया होगा और अंत में पीएम न्यूजीलैंड जाएंगे।

मामले पर गंभीर ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी : ऑस्ट्रेलिया के सुरक्षा अधिकारियों ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। वहीं, उनके द्वारा अब तक की गई जांच-पड़ताल के दौरान इस फेसबुक खाते से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान करने के साथ ही आगे की जांच जारी है। लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। यह पूरा मामला भले ही एक फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसे हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। पुख्ता और विस्तृत जांच चल रही है। इस संबंध में आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के साथ सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

अल्बनीज ने भारत को बताया अहम साझेदार : इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पीएम मोदी की इस यात्रा की घोषणा की है। जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के मेलबर्न में स्वागत को लेकर उत्सुकता जताई है। साथ ही भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा महत्वपूर्ण साझेदार बताया है। पीएम अल्बनीज के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मेलबर्न में मेरे और पीएम मोदी के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा। जिसमें हमारी बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के अलावा साझेदारी से जुड़े हुए तमाम मामलों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

शांति, स्थिरता में अहम योगदान : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीन की उग्रता के बीच अल्बनीज ने यह भी कहा क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखने में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञात हो कि चीन लगातार क्षेत्र से जुड़े विभिन्न इलाकों पर अपना एकाधिकार जता रहा है। जिसे लेकर उसका न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि क्षेत्र के कई अन्य देशों के साथ भी विवाद चल रहा है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में 2020 के मध्य से जारी सैन्य विवाद पिछले साल अक्टूबर महीने में ही पूरी तरह से समाप्त हुआ है। अभी दोनों देश एलएसी पर अपनी-अपनी सेनाओं की पूर्व निर्धारित तैनाती को जस का तस बनाए रखने में जुटे हुए हैं।

15 साल 99...

ने जिस मैदान पर भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, उसी ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में सचिन तेंदुलकर ने 14 अगस्त 1990 को अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा था। तब 17 साल 112 दिन की उम्र में सचिन ने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 119 रन बनाकर भारत को हार से बचाया था।

सोने से मढ़ी ...

में गड़बड़ी और इन गंभीर आरोपों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की कल यानी 6 जुलाई को एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

सुरक्षा की कमान अब मिश्रा के हाथ : एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्र को अयोध्या राम मंदिर का एसपी सुरक्षा नियुक्त किया गया है। अभी तक जिनके हाथ में कमान थी, उनकी छुट्टी कर दी गई है।

बीएलओ निर्वाचन आयोग ...

है। देश में करीब 95 करोड़ मतदाता हैं और 1.80 करोड़ से अधिक चुनावकर्मी इस विशाल प्रक्रिया को संचालित करते हैं, जो भारत की पारदर्शिता और जवाबदेही का दुनिया में उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी विश्वसनीयता के कारण वर्ष 2026 में भारत विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में संभागायुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ और बीएलओ ने मिलकर मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस अभियान ने राज्य को देशभर में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 'ईसीआई नेट' एप जैसे डिजिटल नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के एसआईआर अभियान की उपलब्धियों पर आधारित विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ का मानदेय बढ़ाकर 6 हजार रुपए कर दिया गया है।

फिल्मों व वेब...

ध्यान 'प्लेटफॉर्म की जवाबदेही' तय करने पर है। टेलीग्राम को दी गई चेतावनी में कहा गया है कि वह केवल इस भरोसे नहीं बैठ सकता कि सरकार खुद एक-एक करके पायरेसी वाले चैनल्स की पहचान करेगी और उन्हें बताएगी।

यूएन ने सराहे कांगो में ...

स्थायी ऑपरेटिंग बेस 'साके' में एक भव्य परेड समारोह हुआ था। जिसमें सभी सैनिकों को सम्मानित किया गया। आयोजन में मोनुस्को के वरिष्ठ अधिकारी, फोर्स मुख्यालय के प्रतिनिधि, सैन्य नेतृत्व और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। सेना ने शनिवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। यहां बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह पदक उन सैन्य योद्धाओं को प्रदान किया जाता है। जिन्होंने यूएन के शांति मिशन में सराहनीय योगदान दिया हुआ होता है। पूर्व में 2023 में भारत को यूएन का सर्वोच्च सम्मान कहे जाने वाले ' डॉग हैमरशॉल्ड' पदक से भी सम्मानित किया गया था। जो कि शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई जैसे दो भारतीय शांति सैनिकों और शबर ताहिर अली (नागरिक यूएन कार्यकर्ता) को कांगो में उनके बलिदान के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया था।

यूएन के जनादेश ...

क्रियान्वयन में उल्लेखनीय साहस, दृढ़ता और अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने उनका सम्मान किया है।

यूएन के पदक का महत्व : भारतीय सेना को मिला यूएन का पदक सैन्य बल की उस गौरवशाली विरासत का सबूत है। जिसकी वजह से वह यूएन शांति अभियानों में दुनिया की सबसे भरोसेमंद और प्रमाणिक योगदानकर्ताओं में शुमार की जाती है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद से यह सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। वहीं, दूसरी ओर देखें तो यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा संघर्ष से जूझते इलाकों में रहने वाले कमजोर और पीड़ित समुदायों की रक्षा के उसके संकल्प से भी जुड़ा हुआ है।

मानकों से नहीं होगा कोई समझौता : सेना ने बताया कि यूएन की तरफ से दिया गया यह सम्मान कांगो में भारतीय सेना की बटालियन की क्षेत्र में तैनाती, बल की व्यावसायिक दक्षता, संचालन और संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के माध्यम की गई समर्पित सेवाओं का प्रतिफल है। कार्यक्रम के अंत में सभी शांति सैनिकों ने यूएन के नीले ध्वज को हमेशा ध्यान में रखते हुए सम्मान, साहस और उत्कृष्टता के साथ अपनी सेवाओं को क्रमवार बनाए रखते हुए व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानकों का पालन करने की एक बार फिर से शपथ ली। सेना के रणबांकुरों के इस संकल्प ने न केवल देश का मान बढ़ाया है। बल्कि उसके साथ-साथ दुनियाभर में शांति स्थापना के लिए पूर्ण समर्पण के साथ एक जिम्मेदार और भरोसेमंद राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को भी चार चांद लगा दिए हैं।

50 से ज्यादा मिशन में भारत की भागीदारी: गौरतलब है कि वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के वैश्विक लक्ष्य के साथ की गई थी। जिसमें भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता की भूमिका में शामिल रहा है। 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में 2 लाख 90 हजार से ज्यादा शांति सैनिक तैनात हैं। वर्तमान समय में 5 हजार से ज्यादा भारतीय शांति सैनिक 9 सक्रिय मिशन का हिस्सा हैं। जो कि वैश्विक शांति को बरकरार रखने के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं।

1947 में हल्के नीले रंग को अपनाया: यूएन शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट नाम से भी जाना जाता है। जिसे संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक ध्वज के हल्के नीले रंग से लिया गया है। वर्ष 1947 में यूएन ने इस रंग को स्वीकार किया था। जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। जबकि लाल रंग को युद्ध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी को लिखा पत्र

राम मंदिर वित्तीय अनियमितताओं की फोरेंसिक जांच की मांग

हरिभूमि न्यूज ▶▶ लखनऊ

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे, दान, भूमि क्रय, निर्माण कार्यों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र एवं फोरेंसिक जांच कराने की मांग को लेकर योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इससे जुड़े प्रत्येक आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है। पत्र में उन्होंने कहा कि चढ़ावे की नकदी, बहुमूल्य दान और अन्य वित्तीय मामलों में सामने आई कथित अनियमितताओं के बाद एसआईटी जांच, एफआईआर और कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए बहु-एजेंसी फोरेंसिक जांच जरूरी है।

भूमि खरीद व निर्माण कार्यों में लगाए गए कथित आरोपों की भी समग्र जांच की मांग

उन्होंने वर्ष 2021 में भूमि खरीद और निर्माण कार्यों में लगाए गए कथित आरोपों की भी समग्र जांच कराने की मांग की। अजय राय ने दान, बैंक खातों, लेखा-पुस्तकों, ऑडिट रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड, निविदाओं, निर्माण अनुबंधों और भूमि खरीद से जुड़े सभी दस्तावेजों का वैज्ञानिक परीक्षण कराने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध हो तथा यदि किसी स्तर पर धन शोधन या अन्य वित्तीय अपराध के संकेत मिलते हैं तो संबंधित एजेंसियां तत्काल विधिक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और शासन की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है इसलिए किसी भी स्तर पर संरक्षण दिए जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए

सीएम चौधरी ने की 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा

एजेंसी ▶▶ पटना

सम्राट सरकार ने बिहार में अपराध के नियंत्रण और त्वरित न्याय के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अपराध से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण एवं नियंत्रण के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट से गंभीर मामलों में तेजी से जांच की जा सकेगी और जल्दी सुनवाई के जरिए पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। गया में आयोजित नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी वाले इस राज्य में, करीब 14 करोड़ लोग न्याय के लिए न्यायपालिका, पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर निर्भर हैं।

क्या कभी हो पाएगी एलियन से मुलाकात !

क्या एलियन कभी पृथ्वी पर आएंगे? क्या उनसे हमारी मुलाकात हो पाएगी? इस सवाल का फिलहाल कोई सीधा 'हां' या 'ना' में जवाब देना मुश्किल है। एलियंस का धरती पर आना भले ही अभी विज्ञान कथाओं की तरह लगता हो, लेकिन वैज्ञानिक प्रयासों से भविष्य में, असंभव सा लगने वाला कुछ भी संभव हो सकता है।

कवर स्टोरी
शिखर चंद जैन

रात के समय जब हम आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल बार-बार उठता है, 'क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं?' या फिर किसी दूर के ग्रह पर हमारे जैसे ही या हमसे भी ज्यादा समझदार जीव रहते हैं? इन्हीं बाहरी दुनिया के जीवों को हम 'एलियन' या 'एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल' कहते हैं। गणितीय संभावनाओं को देखें तो ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन जरूर होना चाहिए। लेकिन अंतरिक्ष की असीम दूरियों को देखते हुए, उनका हमारे पास आना या हमारा उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन काम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ दशकों में, जैसे-जैसे हमारी तकनीक और बेहतर होगी, हम शायद सौर मंडल के किसी चांद या बाहरी ग्रह पर जीवन के छोटे अंश (जैसे बैक्टीरिया) खोजने में सफल हो जाएंगे।

क्यों बरकरार है संभावना

वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में खरबों तारे और ग्रह हैं। इतनी बड़ी जगह में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन हो, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए लगता है कि इस यूनिवर्स में कोई न कोई दूसरी दुनिया हो सकती है। खगोल वैज्ञानिक भी इस विषय पर यही सोचते हैं। इसीलिए वे सालों से एलियंस की खोज कर रहे हैं।

क्या एलियन पृथ्वी पर आएंगे!

हालांकि आम लोगों का मानना है कि कभी न कभी एलियन पृथ्वी पर आए होंगे या आएंगे। लेकिन वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तर्क के आधार पर खोजते हैं। एलियन पृथ्वी पर क्यों आना चाहेंगे? इसके वे कई तर्क देते हैं-

नए घर की खोज: जैसे हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन तलाश रहे हैं, वैसे ही एलियन भी अपने रहने के लिए एक नए और सुरक्षित ग्रह की तलाश में पृथ्वी पर आ सकते हैं।

संसाधनों की तलाश: अगर उनके अपने ग्रह के प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, खनिज या ऊर्जा आदि खत्म हो गए हों, तो वे पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करने के लिए यहां का रुख कर सकते हैं।

जिज्ञासा और शोध: हो सकता है कि एलियन भी हमारी पृथ्वी के वैज्ञानिकों की तरह खोजी स्वभाव के हों। वे ब्रह्मांड के दूसरे जीवों यानी हम इंसानों के बारे में जानने और हमसे दोस्ती करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं।

तकनीकी श्रेष्ठता: अगर कोई सभ्यता हमसे लाखों साल पुरानी है, तो उनके पास ऐसे स्पेसशिप हो सकते हैं जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज चल सकें। ऐसी तकनीक होने पर उनके लिए पृथ्वी तक आना बहुत आसान होगा।

इसके विपरीत एलियन का आना क्यों मुश्किल है, इसके भी कुछ तर्क देते हैं-

अत्यधिक दूरी: ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारे सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में भी आज की तकनीक से हजारों साल लग जाएंगे। एलियंस के लिए भी इतनी लंबी दूरी तय करना एक बड़ी चुनौती होगी।

समय का चक्र: हो सकता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में एलियन रहे हों, लेकिन वे इंसानों के पैदा होने से करोड़ों साल पहले ही खत्म हो चुके हों, या फिर वे तब आएंगे, जब इंसान धरती से गायब हो चुके होंगे।

संवाद की कमी: हमारी भाषा, रेडियो सिग्नल और सोचने का तरीका उनसे बिल्कुल अलग हो सकता है। मुमकिन है कि वे हमारे सिग्नलों को समझ ही न पा रहे हों।

वैज्ञानिक शोध और प्रयास

वैज्ञानिकों ने एलियंस को ढूंढ़ने और उनसे संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए हैं।

सेटी प्रोजेक्ट: सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जो अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमयी सिग्नलों पर नजर रखता है। वैज्ञानिक बड़े-बड़े रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके आसमान से आने वाली आवाजों और तरंगों को सुनते हैं, ताकि एलियंस का कोई संदेश पकड़ा जा सके।

वोयाजर के गोल्डन रिकॉर्ड्स: साल 1977 में नासा ने अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, जिनका नाम 'वोयाजर 1' और 'वोयाजर 2' है। इन स्पेसशिप में एक तांबे की बनी सीडी जैसी 'गोल्डन डिस्क' रखी गई है। इस डिस्क में पृथ्वी की आवाजें, संगीत, 55 भाषाओं में नमस्कार और हमारे ग्रह का नक्शा दर्ज है, ताकि अगर कभी यह किसी एलियन को मिले, तो वे हमारे बारे में जान सकें।

यूएफओ और यूएपी की जांच: दुनिया भर में कई बार आसमान में उड़ने वाली अजीबो-गरीब चीजों जैसे उड़न तश्तरी को देखने का दावा किया गया है। अब अमेरिकी सरकार और नासा जैसी एजेंसियां इन्हें 'यूएपी' (अनआइडेंटिफाइड एनोमैलुअस फैनोमेना) कहकर इन पर आधिकारिक रिसर्च कर रही हैं, ताकि यह साफ हो सके कि ये एलियंस के यान हैं या कोई प्राकृतिक घटना।

बहरहाल, भविष्य में कभी दूसरे ग्रह के वासियों एलियंस से पृथ्वीवासियों की कभी मुलाकात हो पाएगी या नहीं यह तो अभी नहीं कहा जा सकता लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कोशिश में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। *

केपलर-जेम्स वेब टेलीस्कोप

नासा के इन आधुनिक टेलीस्कोपों का काम अंतरिक्ष में 'एक्सोप्लैनेट्स' यानी हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह को खोजना है। वैज्ञानिकों ने अब तक हजारों ऐसे ग्रह खोजे हैं, जो 'गोल्डीलॉक्स जोन' में हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रह अपने तारे से न तो बहुत ज्यादा गर्म हैं और न ही बहुत ज्यादा ठंडे, जहां पृथ्वी की तरह पानी और जीवन मौजूद हो सकता है। इसमें जीवन की संभावना भी हो सकती है।

मार्स मिशन

हमारे सबसे नजदीकी ग्रह मंगल पर पानी और जीवन के निशान खोजने के लिए भारत का 'मंगलयान', नासा के 'परसवेरेंस' रोवर जैसे कई मिशन भेजे गए हैं। इनके जरिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म ढूंढ़ रहे हैं, जो अंतरिक्ष वासी एलियन या जीवन का पहला ठोस सबूत हो सकते हैं।

चिंताजनक है लगातार बढ़ता अंतरिक्ष में वेस्ट मैटर

जिस तरह से हम सबने अपनी पृथ्वी पर प्रदूषक वस्तुओं और कूड़े-कचरे का अंबार लगा रखा है, कुछ ऐसा ही हाल अंतरिक्ष का भी होता जा रहा है। स्पेस में स्पेसक्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स और सैटेलाइट्स का वेस्ट मैटर भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है।

स्पेस इश्यू
अंजू जैन

जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें टिमटिमाते तारे, चंद्रमा और कभी-कभी गुजरते हुए सैटेलाइट्स (उपग्रह) दिखाई देते हैं। यह नजारा बेहद जादुई लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस खूबसूरत अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी मुसीबत धीरे-धीरे पैर पसार रही है? इस मुसीबत का नाम है-'अंतरिक्ष का कचरा' या 'स्पेस डेब्री'।

क्या है स्पेस डेब्री: जैसे हम अपनी पृथ्वी पर प्लास्टिक, रैपर्स और खराब सामान फेंककर इसे गंदा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही इंसानों ने अंतरिक्ष को भी कबाड़खाना बनाना शुरू कर दिया है। अंतरिक्ष कचरा या स्पेस जंक उन सभी मानव-निर्मित बेकार चीजों को कहते हैं, जो अब किसी काम की नहीं रहीं और पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में चक्कर काट रही हैं। इस कचरे में बेकार हो चुके पुराने सैटेलाइट्स, रॉकेट्स के छूटे हुए टुकड़े, अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ से छूटे हुए औजार (जैसे स्क्रू-ड्राइवर, ग्लव्स) और सैटेलाइट्स के आपस में टकराने से बने करोड़ों छोटे-छोटे टुकड़े शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार, इस समय अंतरिक्ष में लाखों छोटे-बड़े टुकड़े तैर रहे हैं, जो एक बड़े खतरे की घंटी हैं।

स्पेस डेब्री में शामिल चीजें: स्पेस डेब्री में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे-जब किसी उपग्रह का जीवनकाल खत्म हो जाता है या उसका ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वह वहीं अंतरिक्ष में निष्क्रिय होकर घूमने लगता है। उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद रॉकेट के निचले और ऊपरी हिस्से अलग हो जाते हैं। ये हिस्से अंतरिक्ष में ही तैरते रह जाते हैं। जब दो सैटेलाइट्स आपस में टकराते हैं, तो उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। एक टक्कर से हजारों नए, छोटे-छोटे तीखे टुकड़े बन जाते हैं।

कुछ देश अपनी मिसाइल क्षमता को जांचने के लिए अंतरिक्ष में अपने ही पुराने सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ा देते हैं। इससे पल भर में बेशुमार कचरा फैल जाता है।

स्पेस वेस्ट से संकट: अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष तो इतना विशाल है, फिर वहां थोड़े से कबाड़ से क्या फर्क पड़ता है? अंतरिक्ष हमारा भविष्य है। अगर आज हमने इसकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाली पीढ़ी के लिए ब्रह्मांड के रहस्य जानने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके कई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अंतरिक्ष में ये टुकड़े धीरे-धीरे नहीं तैरते। इनकी रफ्तार बंदूक की गोली से भी 10 से 15 गुना तेज होती है, लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार में एक छोटा-सा पेंट का टुकड़ा या पेंच भी किसी सैटेलाइट से टकराए, तो उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा हमारे वैज्ञानिक रहते हैं। यदि कोई बड़ा टुकड़ा स्पेस स्टेशन से टकरा जाए, तो वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की जान पर बन आ सकती है। उन्हें कई बार खुद को बचाने के लिए आपातकालीन कैप्सूल में छिपना पड़ता है।

हम मोबाइल के जरिए जो बात करते हैं, जीपीएस से रास्ता देखते हैं, टीवी देखते हैं और मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, वे सब अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स की वजह से संभव होता है। अगर कचरे की वजह से ये सैटेलाइट्स नष्ट हो गए, तो हमारी पृथ्वी की आधुनिक लाइफलाइन एकदम रुक-सी जाएगी। अगर अंतरिक्ष में कचरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वे आपस में टकराकर और अधिक कचरा बनाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के चारों ओर कचरे की ऐसी घनी दीवार बन जाएगी कि इंसान कभी नया रॉकेट या सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज ही नहीं पाएगा। हम हमेशा के लिए पृथ्वी पर कैद हो जाएंगे।

निदान और समाधान: अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे की इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां जैसे भारत की इसरो, अमेरिका की नासा इस मलबे को साफ करने के लिए बेहद अनोखे तरीकों पर काम कर रही हैं। वैज्ञानिक ऐसे विशेष सैटेलाइट बना रहे हैं, जो अंतरिक्ष में जाकर बड़े मलबे पर जाल फेंकेंगे या हारपून (भाला) मारकर उसे पकड़ेंगे और खींचकर पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ ले आएंगे।

कुछ जापानी कंपनियां ऐसे सैटेलाइट्स का परीक्षण कर रही हैं, जिनमें बहुत शक्तिशाली चुंबक लगे होंगे। ये चुंबक लोहे और धातु के मलबे को अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेंगे। इस तरह कई और तकनीकें अपनाई जा रही हैं। संभव है इसका स्थायी समाधान खोज लिया जाएगा। *

गजल
हबीब कैफी

चला गया कोई

उम्र अपनी बढ़ा गया कोई
नाम लेते ही आ गया कोई
मैंने थामा था हाथ कांटों में
फूल पाकर छुड़ा गया कोई
उसके सारे निशान जिंदा हैं
कैसे कह दूं चला गया कोई
इक तने पर लिखे थे बरसों से
नाम दोनों मिटा गया कोई
नींद यूं ही नहीं हुई गायब
तेरे किस्से सुना गया कोई
सिर्फ इक बात मैंने पूछी थी
बातें क्या-क्या सुना गया कोई
जिक्र जब भी वफा का आया है
सर झुका कर चला गया कोई

व्यंग्य / सूर्यकुमार पांडेय

महंगाई से मुलाकात

चाहने को हम भी बहुत कुछ चाहते हैं। हमारी पहली चाहत तो यह ही है कि अपने पास अकूत वैध संपत्ति हो। वैध इसलिए, क्योंकि बुल्डोजर से सबको डर लगता है। बड़े-बड़े मुर्गे हलाल हो गए, फिर भला इस पिद्दी के शोरबे की क्या ही औकात है? हमारी दूसरी चाहत है कि महंगाई नाम की चीज को अपने देश से धक्के मार कर बाहर निकाल देना चाहिए। अंतर्मन में कुछ ऐसी भी चाहतें हैं, जिन्हें सार्वजनिक कर दें तो जूते पड़ने लगेंगे। हमारे एक मित्र ने एक महिला को सिर्फ 'आइ लव यू' कहा था। एक वह दिन था और एक आज का दिन है, अस्पताल से लौटकर आया है और प्रत्येक महिला को बुआ-दीदी से नीचे नहीं बोलता है।

इंसान कामनाओं का कोष है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। सबको फेसबुक-एक्स आदि के दरिया में डालकर अपनी भड़ास निकालने से अच्छा है कि भाग्यवादी बन जाओ। 'जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।' हम भी रह ही रहे हैं। घोर महंगाई की चपत खाकर भी हंस रहे हैं। यूं किसी के चाहने या न चाहने से क्या होता है? भला मैं भी कहां चाहता था, फिर भी आज महंगाई से मेरी मुलाकात हो ही गई। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। पहले कभी-कभार भेंट होती थी। इन दिनों वह मुझसे रोज ही किसी-न-किसी बहाने मेरे घर पर मिलने आ जाया करती है। जब मैं घर से बाहर रहता हूं तो वह वहां पर भी मुझसे टकरा जाती है। बाजार जाऊं तो वहां भी मिल जाती है। सड़क पर चल रहा होता हूं, तब भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। पत्नी कहती है, 'यह मुई मेरी सौत है। इसकी निगाह तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारी जेब पर भी रहती है।'

मैं अकसर यह महसूस करता हूं कि मेरी जेब में रखा हुआ पर्स भी जरूरत से ज्यादा दुबला हो चुका है। महंगाई डायन के प्रकोप के चलते 'चंद क्वॉइन' ही शेष बचे हुए हैं। गनीमत है कि वह पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। शायद इसी दुबले पर्स पर महंगाई डाका डालने पर उतारू है। जिसके पास धन नहीं है, उसको न चोरी का डर सताता है और न रहजनी का। उसे एकमात्र डर सताता है तो महंगाई का।

मेरा प्रतिदिन महंगाई से इसी तरह मिलना होता रहा तो एक दिन इस गरीब की जान ही निकल जाएगी। आप जानते हैं कि गरीब की जान उसकी हलक में अटकी होती है। यह उस चिड़िया की तरह होती है, जिसे जब तक दाना-पानी मिलता रहता है, चहकती रहती है, जिस दिन मिलना बंद हो गया, फुर्र से उड़ जाती है। लोग यूं ही प्राण को पखेरू नहीं कहते हैं।

मैं इस नामाकूल महंगाई से कितना भी बचना चाहता हूं, लेकिन वह है कि हाथ धोकर मेरे गले पड़ती जा रही है। आज महंगाई फिर एक बार मुझसे मिलने आई है। वह आवश्यकता से अधिक मोटी दिख रही है। पिछली बार जब उससे मिलना हुआ था, तब भी वह मोटी ही थी, लेकिन इस बार उसके शरीर की चर्बी पर एक और परत चढ़ चुकी है। वैसे भी जो प्रतिदिन दूसरों की जेब पर डाका डालता हो, उसका मोटा हो जाना अचरज की बात नहीं है। मैं अपने आस-पास के ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं, जो दूसरों को लूटते रहते हैं और मोटे हो जाते हैं। महंगाई भी पुष्ट हो रही है। वह मुझसे कहने लग गई, 'तुम मेरे नाम का रोना रोते रहते हो, मैंने सोचा आज एक बार और मिल लेती हूं! कहो, कैसे मिजाज हैं?' मैंने कहा, 'मिजाज की छोड़ो। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम जिस अनुपात में मोटी होती चली जा रही हो, हम उसी अनुपात में दुबले हो रहे हैं। उधर तुम्हारी खुराक बढ़ती जा रही है, इधर हम अपने को किसी दिहाड़ी मजदूर की पगार जैसा बेबस पाते हैं।'

महंगाई जैसे आज विश्व हास्य दिवस मनाने के मूड में थी। वह पहले खूब हंसी, फिर मुझे छेड़ती हुई बोली, 'देख रही हूं। तुम्हारे पांवों में बेबसी के घुंघरू बंधे हुए है, फिर भी तुम ठुमक रहे हो। तुम जैसे बकरे को कहां पता है कि कल मैं तुमको किस भारी-भरकम रूप में मिलने वाली हूं!' *

पुस्तक चर्चा / विज्ञान भूषण

विडंबनाओं पर कटाक्ष

आज के बहुरूपिए समय में तमाम तरह की विडंबनाओं और विसंगतियों के संग जीने के लिए हम सब इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि किसी भी प्रकार के विद्रूप में असहज महसूस नहीं करते हैं। लेकिन एक व्यंग्यकार की सजग दृष्टि न केवल जीवन और व्यवस्था में धंसे विद्रूप को इंगित करती है, उस पर कटाक्ष भी करती है। सुपरिचित व्यंग्यकार मुरली मनोहर श्रीवास्तव के ऐसे ही चुने हुए 65 व्यंग्यों का संग्रह 'डेढ़ इंच मुसकान वाले लोग' हाल में छपकर आया है। इनमें कहीं वे नेशनल कैरेक्टर से लेकर, आटा से ज्यादा डाटा की चिंता करते नजर आते हैं, तो कहीं चुटकी लेते हुए मीडिया का महिमा मंडन करते दिखते हैं। 'ऑफिस रस' शीर्षक व्यंग्य में वह लिखते हैं, 'जिसे एक बार ऑफिस रस की लत लग गई, वह इसकी प्रॉपर डोज के बिना रह ही नहीं पाता। वह कहीं भी रहे, किसी भी हाल में पड़ा हो, इस रस की प्राप्ति के लिए छटपटाता रहता है।' हर खास-ओ-आम की जिंदगी में आज की तारीख में इंटरनेट डाटा का क्या महत्व हो चुका है, इस बारे में व्यंग्यकार की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। 'आटा और डाटा' शीर्षक व्यंग्य में वह कहते हैं, 'कई बार लगता है कि आटा न भी मिले तो चलेगा पर डाटा खत्म हो गया तो जीकर क्या करेंगे? लड़ाई यह है कि आटा जन-जन तक पहुंचा कि डाटा?' *

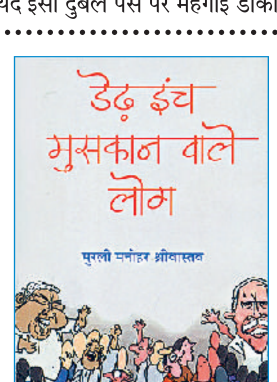

पुस्तक: डेढ़ इंच मुसकान वाले लोग (व्यंग्य संग्रह), **लेखक:** मुरली मनोहर श्रीवास्तव, **मूल्य:** 400 रुपए, **प्रकाशक:** विद्या विहार, नई दिल्ली

खबर संक्षेप

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को दी विदाई

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने जून में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का विदाई समारोह शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित किया। समारोह में जून 2026 में सेवानिवृत होने वाले वीरन सिंह भलावी, इशा मूलचंदानी, हेमलता मेघश्याम, ओमप्रकाश राजपूत, महेश उपाध्याय, रत्नेश पाराशर, याकूब खान, कैलाश चंद्र सैनी, शैलेंद्र कुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, मेवा बाई एवं और राजकुमार पटेल मंत्रालय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत विदाई दी गई। समारोह में मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के सलाहकार आशीष सोनी द्वारा सेवानिवृत शासकीय सेवकों के सुखद एवं स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए विदाई दी गई।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह योजनाः कलेक्टर के वित्तीय अधिकार बढ़े

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कलेक्टरों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब कलेक्टर आवश्यकता पड़ने पर दो लाख रुपए से अधिक की राशि भी निराश्रित निधि से स्वीकृत कर खर्च कर सकेंगे। अब तक कलेक्टरों को निराश्रित निधि से सीमित राशि खर्च करने का अधिकार था।
एक बार में अथवा एक माह के भीतर अधिकतम 25 हजार रुपए और पूरे वित्तीय वर्ष में निर्धारित सीमा तक ही ब्याज की राशि का उपयोग किया जा सकता था। वहीं, जमा राशि पर अर्जित ब्याज से अधिकतम दो लाख रुपए तक के भुगतान की अनुमति थी।नए आदेश के तहत कलेक्टरों को निराश्रित निधि के मूलधन और ब्याज दोनों का उपयोग करते हुए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार दिए हैं।

बालोतरा में प्रधानमंत्री मोदी ने दो रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण

नई दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में 58 किलोमीटर लंबी चूरू–सादुलपुर दोहरीकरण परियोजना तथा 46 किलोमीटर लंबी चूरू–रतनगढ़ दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पत किया। कुल 104 किलोमीटर लंबाई की इन परियोजनाओं का निर्माण लगभग 892 करोड़ की लागत से किया गया है।
इन परियोजनाओं से रेल लाइन की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे अधिक यात्री एवं मालगाड़ियों का संचालन संभव हो सकेगा। इससे रेल यातायात का दबाव कम होगा, ट्रेनों की समयपालनता में सुधार आएगा, यात्रा समय घटेगा तथा रेल परिचालन अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनेगा।
साथ ही माल परिवहन की गति और दक्षता बढ़ने से व्यापार, कृषि, उद्योग तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इन परियोजनाओं से चूरू जिले एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी तथा व्यापार, निवेश, रोजगार और समग्र क्षेत्रीय विकास के नए अवसर सृजित होंगे।

सूचना
सभी पाठकों से अनुरोध है कि हरिभूमि समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) में दिए गए तथ्यों/दावों के बारे में अपने विवेक से निर्णय लें और विज्ञापन के दावों की विश्वसनीयता को परखें। हरिभूमि समूह के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की विज्ञापनों के तथ्यों से सम्बन्धित कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नए विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम

विधानसभा में प्रश्न सही होगा तो जवाब भी सटीक आएगा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रश्नकाल में सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन प्रश्नकाल को स्थगित नहीं करना चाहिए। कई बार प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न में एक-दो मिनट तो भाषण में ही निकाल देते हैं। इससे समय भी जाया होता है, और प्रश्न भी कई बार घूम जाता है। जब प्रश्न घूम जाता है तो सरकार का जवाब भी घूम जाता है।

यदि सरकार से ठीक जवाब लेना है, या सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, तो पूरक प्रश्न सटीक होना चाहिए। अध्यक्ष तोमर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नए विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में बोल रहे थे। वे सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए संसदीय प्रश्न एवं अन्य संसदीय उपकरणों की महत्ता विषय पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एवं विभिन्न राज्यों से आए पीठासीन अधिकारी, लोकसभा व विधानसभाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

विधायकों को प्रश्न के बारे में अध्ययन करना चाहिए

कार्यक्रम को संबोधित करते तोमर।

तोमर ने कहा कि इसके लिए निश्चित रूप से विधायकों को प्रश्न के बारे में अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न की सार्थकता विधायक की प्रतिष्ठा भी है। प्रश्न संक्षिप्त और सार्थक हो। प्रश्न सार्थक होगा और पूरक प्रश्न सीधा व सटीक होगा तो जवाब भी सटीक आएगा। यदि सरकार के पास जवाब नहीं होगा तो सरकार निरुत्तर होगी। यदि सार्थक जवाब आएगा, तो आपके कार्य की प्रशंसा होगी। इसलिए प्रश्नकाल का उपयोग हम सब लोगों को बहुत ही ध्यान पूर्वक और अच्छे तरीके से करना चाहिए।

विधानसभा लोकतंत्र की जीवंत व्यवस्था का प्रतिपादन

तोमर ने कहा कि व्यक्तिगत जीवन की शुद्धता ही सार्वजनिक जीवन की शुद्धता को सार्थक करती है। विधानसभा केवल संसदीय कार्यवाही का विवरण नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस जीवंत व्यवस्था का प्रतिपादन है, जहां सत्ता अपने आप में अंतिम नहीं होती, बल्कि हर क्षण परीक्षण के अधीन रहती है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ यही है कि शासन शक्ति के साथ-साथ उत्तरदायित्व भी लेकर चलता है, और यह उत्तरदायित्व केवल नैतिक नहीं, बल्कि संस्थागत होता है।

क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो समस्या से सही रूप में रूबरू होंगे

तोमर ने कहा कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के पहले क्षेत्र में भ्रमण भी होना चाहिए। यदि क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो समस्या से सही रूप में रूबरू होंगे। कई बार लोग हमको प्रश्न बना कर दे देते हैं। हमको भी लगता है कि प्रश्न लगाना है और बने बनाए प्रश्न मिल गए हैं तो क्यों मेहनत करें? लेकिन प्रश्न को हमें अपने हाथ से लिखना चाहिए। प्रश्न अपने हाथ से लिखेंगे तो उसे प्रश्न के प्राण को समझ पाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रश्न व्यक्ति विशेष पर केंद्रित न हो। जब व्यक्ति विशेष पर प्रश्न केंद्रित होता है तो फिर उसके गलत अर्थ भी निकलते हैं। गलत अर्थ पर जब चर्चा होती है तो विधायक की प्रतिष्ठा धूमिल होती है।

विषय महत्वपूर्ण होगा तो ध्यानाकर्षण लगते ही पूरी सरकार में खलबली मच जाएगी

तोमर ने कहा कि ध्यानाकर्षण लगाते समय भी हम सब लोगों को इसके पीछे की भावना पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इसका महत्व कम हो जाएगा। विषय महत्वपूर्ण होगा तो ध्यानाकर्षण लगते ही पूरी सरकार में खलबली मच जाएगी। तोमर ने कहा कि जिस व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन जनता सुनिश्चित कर देती है, उसके लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है।

90 करोड़ से बदलेगी पर्यटन की तस्वीर, होटल की छत पर बनेगा हेलिपैड

यादविन्द्रा गार्डन और टिक्कर ताल बनेंगे विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र : नायब

यादविन्द्रा गार्डन के पास आधुनिक सुविधाओं से युक्त वन स्टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित होगा

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने राज्य को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पिंजौर स्थित ऐतिहासिक यादविन्द्रा गार्डन और मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के निर्देश दिए। दोनों परियोजनाओं पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 'वेड इन इंडिया' विजन के अनुरूप यादविन्द्रा गार्डन के पास आधुनिक सुविधाओं से युक्त वन स्टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के निर्देश दिए। यहां कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर सहित विवाह समारोहों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर एक आलीशान होटल बनाया जाएगा, जिसकी छत पर अत्याधुनिक हेलिपैड की सुविधा होगी, ताकि देश-विदेश से आने वाले मेहमान सीधे हवाई मार्ग से पहुंच सकें।

बटरफ्लाई पार्क व एक्वेरियम भी विकसित किए जाएंगे

विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि यादविन्द्रा गार्डन के विकास के दौरान इसकी ऐतिहासिक और पारंपरिक विरासत को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना यहां संगीतमय फव्वारे, बटरफ्लाई पार्क और एक्वेरियम विकसित किए जाएंगे। आकर्षक लाइटिंग के जरिए रात के समय भी यह स्थल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण बनेगा। मोरनी के निकट स्थित टिक्कर ताल को एडवेंचर पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की भी योजना है। यहां मौजूदा सुविधाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा एडवेंचर पार्क, बोटिंग, हॉन्टेड हाउस समेत अन्य आकर्षण विकसित किए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को रोमांचक और यादगार अनुभव मिल सके।

सीए देश की आर्थिक मजबूती के प्रमुख स्तंभ : मुख्यमंत्री

■ सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 को संबोधित किया

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और देश में हर महीने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है जो देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का प्रतीक है। इस टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाने में चार्टेड अकाउंटेंट्स (सीए) का बड़ा योगदान है। इंस्टीच्यूट आफ चार्टेड अकाउंटेटस ऑफ इंडिया द्वारा पंचकूला में सेंटर आफ एक्सिलेंस स्थापित करने के लिए 5 एकड भूमि की मांग पर मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्रीशनिवार को पंचकूला स्थित इंद्रधनुष आडिटोरियम में सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन प्रज्ञान 2026 को मुख्यअतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

बाबा लखी शाह बंजारा गुरुभक्ति, अदम्य साहस और राष्ट्रसेवा के प्रतीक

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुभक्ति, अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रसेवा के प्रतीक बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लखी शाह बंजारा जी का जीवन भारतीय संस्कृति, गुरुभक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए जो अद्वितीय साहस एवं समर्पण का परिचय दिया, वह सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय इतिहास सदैव बाबा लखी शाह बंजारा जी के अतुलनीय पराक्रम, त्याग और समर्पण का साक्षी रहेगा। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अदम्य वीरता और अटूट आस्था का परिचय दिया, जो भारतीय समाज के लिए अमूल्य विरासत है।

भारत, जर्मनी की साझेदारी मजबूत करने में मप्र निभाएगा बड़ी भूमिका

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल की ओर से मुख्यमंत्री से मप्र में ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में जर्मनी के केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी बोर्ड की सदस्या एवं बैंक की सीईओ सुश्री क्रिस्टियाने लाईबेक, कंट्री डायरेक्टर वूल्फन मूथ, जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि गॉटफ्रीड वॉन और अन्य सदस्य, प्रबंध संचालक मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड चंद्रमौली शुक्ला, विशेष गढ़पाले सहित केन्द्र सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यनमंत्री डॉ. यादव ने भारत एवं जर्मनी के बीच दशकों पुरानी मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश भाईयों की तरह हैं। इनमें आपसी साझेदारी को और अधिक प्रबल बनाने में मप्र बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है।

कीवे ने लॉन्च किया Hypevolt-R, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिली नई पहचान

नई दिल्ली। कीवे इंडिया ने आज अपने अब तक के सबसे उन्नत इलेक्ट्रिक स्कूटर **Keeway Hypevolt-R** को लॉन्च किया। इसके साथ ही कंपनी ने भारत के प्रीमियम परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में प्रवेश किया है। दमदार प्रदर्शन के साथ रोजमर्रा के उपयोग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया **Hypevolt-R** आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक तकनीक और स्मार्ट इंजीनियरिंग का बेहतरीन मेल है। इस स्कूटर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,99,000 रखी गई है। यह क्रिस्टल व्हाइट और प्लेटिनम ग्रे रंगों में उपलब्ध होगा। ग्राहक कीवे इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मात्र 5,000 देकर इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।**Hypevolt-R** को पारंपरिक इलेक्ट्रिक स्कूटरों से कहीं बेहतर राइडिंग अनुभव देने के लिए विकसित किया गया है। इसकी तेज थ्रॉटल रिस्पॉन्स, शानदार एक्सीलरेशन और स्मूद पावर डिलीवरी इसे भारत के सबसे रोमांचक इलेक्ट्रिक स्कूटरों में शामिल करती है। इस लॉन्च पर कीवे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, विकास झाबाख ने कहा **Hypevolt-R** भारत में कीवे की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ग्राहक केवल एफिशिएंसी नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और रोजमर्रा की प्रैक्टिकैलिटी सब कुछ एक ही पैकेज में चाहता है।

एआई का उपयोग करने वाले डॉक्टर भविष्य का नेतृत्व करेंगे :

हैदराबाद। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने के साथ चिकित्सा अनुसंधान एवं रोगी देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह विचार एआईजी हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. डी. नागेश्वर रेड्डी ने आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के 16वें स्थापना दिवस व्याख्यान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ हेल्थकेयर विषय पर बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान हमेशा मानवीय संवेदनशीलता और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का समन्वय रहा है। इसलिए एआई को डॉक्टरों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने वाले सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा में निदान, उपचार, चिकित्सा शिक्षा और रोगी देखभाल के लिए मल्टीमॉडल एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। डॉ. रेड्डी ने कहा कि एआई दवा खोज, रेडियोलॉजी, टेलीमेडिसिन, प्रिसिजन मेडिसिन, जीनोमिक्स, कैंसर की प्रारंभिक पहचान, त्वचा रोगों के निदान तथा दूरस्थ रोगी निगरानी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। उन्होंने बताया कि एआई ने नई दवाओं के विकास की प्रक्रिया को दशकों से घटाकर लगभग दो वर्षों तक सीमित कर दिया है और आने वाला दशक फार्मास्युटिकल अनुसंधान के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा। डॉक्टरों के बीच एआई को लेकर व्याप्त आशंकाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एआई डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा, लेकिन जो डॉक्टर एआई का उपयोग करना जानते हैं, वे उन डॉक्टरों से आगे निकल जाएंगे जो इसका उपयोग नहीं करते। एआई स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है।

महापौर ने मालीखेड़ी विसर्जन घाट के विकास कार्यों का लिया जायजा

भोपाल । महापौर मालती राय ने शुक्रवार को मालीखेड़ी में विसर्जन घाट पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विसर्जन घाट के सभी कार्यों को श्रद्धालुजन की सुविधा के दृष्टिगत निर्धारित मानकों अनुसार जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व में किए गए कामें सहित प्रचलित व आगामी कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की व शेष सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मूर्ति विसर्जन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सुगमता के साथ पूर्ण कराने की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराया जाए। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि निगम द्वारा मालीखेड़ी में विसर्जन घाट पर सीढ़ियां, रिटर्निंग वॉल, नालियों का निर्माण आदि कार्य कराए जा चुके हैं।

पूर्व रेलवे ने "ईस्टर्न रेलवे इज़ वॉचिंग यू" अभियान का भव्य शुभारंभ किया

हावड़ा। स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्व रेलवे ने आज हावड़ा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य समारोह में अपने व्यापक स्वच्छता जागरूकता अभियान के दूसरे चरण "ईस्टर्न रेलवे इज़ वॉचिंग यू" का औपचारिक शुभारंभ किया। यह अभियान इस वर्ष अप्रैल में प्रारंभ किया गया था और आज का यह कार्यक्रम पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री मिलिंद देऊस्कर के गतिशील नेतृत्व में अभियान के नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। इस चरण में रेलवे परिसरों में गंदगी फैलाने और थूकने के विरुद्ध जीरो शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई गई है। इस अभियान का मूल संदेश है कि रेलवे परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पूर्व रेलवे हर समय सतर्क है और परिसर की निरंतर निगरानी की जा रही है। क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न (सीसीटीवी) कैमरों के व्यापक नेटवर्क तथा रेलवे कर्मचारियों की सक्रिय निगरानी के माध्यम से यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाते या थूकते हुए पाया जाता है, तो उस पर तत्काल मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा।जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे ने एक अभिनव पहल भी शुरू की है। यदि कोई रेल यात्री किसी व्यक्ति को गंदगी फैलाते या थूकते हुए देखता है, तो वह उसकी तस्वीर लेकर स्थान का विवरण सहित व्हाट्सऐप नंबर 9002022780 पर भेज सकता है।

जोरदार बारिश होने से लोगों ने ली उमस से राहत, रायपुर में भी झमाझम

मानसून पूरी तरह एक्टिव, बादलों की गड़गड़ाहट और गरज-चमक के बीच बरसे बदरा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। शनिवार की शाम 4:30 बजे रायपुर में जमकर बारिश हुई। बादलों की गड़गड़ाहट और गरज चमक के बीच जमकर बदरा बरसे। इस दौरान बिजली चमकती रही और तेज अंधड़ चलते रहे। झमाझम बारिश होने से लोगों ने उमस से राहत ली। पिछले चार-पांच दिनों से रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार उमस पड़ रही थी। शनिवार की शाम को हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। झमाझम बारिश रायपुर में होती रही। इस दौरान तेज हवाएं चलने और मेघ गर्जन से रायपुर के कई इलाकों में बिजली गुल रही।

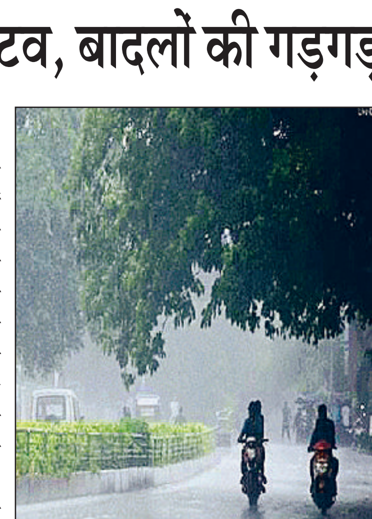

राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज

छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से अगले पांच दिनों तक प्रदेशभर में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने के संकेत हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सभी संभागों में कहीं न कहीं अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई।

इन जिलों में यलो अलर्ट जारी

प्रदेश में शुक्रवार को सबसे अधिक तापमान अंबिकापुर में 32 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान पेंड्रा में 21.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, दुर्ग और बेमेतरा समेत कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। शनिवार को जधानी रायपुर शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भा.न.स.स.देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **राहुल** पुत्र राम नारायण निवासी मकान नंबर 0332, सनाधि पार्क के पास बरवाला, बवाना, आउटर नॉर्थ, दिल्ली ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276/19 धारा 324/34 भा.द.स, थाना बवाना, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **राहुल** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त **राहुल** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा कि जाती है की उक्त अभियुक्त **राहुल, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276/19 धारा 324/34 भा.द.स, थाना बवाना, दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **03.08.2026** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेश से
सुश्री भारती बेनीवाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-05
उत्तरी ज़िला, कमरा नंबर 114, पहली मंजिल
रोहिणी न्यायालय, दिल्ली
DP/8995/ON/2026

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **नसीम उर्फ ज़ावेद, पुत्रः** मो. ताहीर, **पताः** मकान नं. के–113, जनता कॉलोनी, वेलकम, दिल्ली ने मुकदमा **FIR No. 531/2020, U/s 25/54/59 A ACT, थानाः वेलकम, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **नसीम उर्फ ज़ावेद** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **नसीम उर्फ ज़ावेद** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि मुकदमा **FIR No. 531/2020, U/s 25/54/59 A ACT, थानाः वेलकम, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **नसीम उर्फ ज़ावेद** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **05.08.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
सुश्री दीपाक्षी राणा
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी – 03
कोर्ट नं. 19, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली
DP/9118/NE/2026
(Court Matter)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **रूबी पुत्र श्री शैलेन्द कुमार पताः मकान नं 1003, 12 गज टीसी कैम्प रघुबीर नगर, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 172/2022 धारा 160 भा.द.स. के तहत** थानाः तिलक नगर, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **रूबी** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **रूबी** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 172/2022 धारा 160 भा.द.स. के तहत थानाः तिलक नगर, दिल्ली के उक्त रूबी** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **21.08.2026** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री विकास मदान
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी–07
पश्चिम तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली
DP/9157/WD/2026

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण आजकल काफी चर्चा में है। इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर गहरी चोट पहुंची है। सवाल उठता है कि इस मामले में कहां चूक हुई और क्या किया जाना चाहिए था, जिसका पालन नहीं हो पाया? आखिर प्रबंधन को लेकर ऐसी क्या व्यवस्था बनाई जाए, जिससे मंदिरों के कामकाज में पारदर्शिता आए, जबकि भारत के अनेक प्रमुख मंदिरों खास तौर पर दक्षिण के प्रबंधन इतने अच्छे हैं कि उनमें ज्यादा परिवर्तन या हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। आज भी वहां समितियों की बैठकें होती हैं और उनके अनुसार निर्णय भी होते हैं। उनकी प्रबंधन समितियां बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं और दान का प्रबंधन करती हैं। उत्तर भारत के मंदिर इनसे क्या सबक ले सकते हैं? सभी बड़े धार्मिक संस्थान में दान प्रबंधन को लेकर समय-समय सार्वजनिक जानकारी, नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग से भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है। हालांकि राम मन्दिर चन्दा मामले की जांच संबंधित राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही है। दूसरी ओर, क्या राममंदिर चढ़ावा चोरी विवाद भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से प्रभावित करेगा। यदि हां तो कितना और नहीं तो क्यों नहीं? ***इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...***

सरकारी व्यवस्था से परे हो मंदिर प्रबंधन

विश्लेषण
अवधेश कुमार
वरिष्ठ स्तंभकार

> **काफी समय से मंदिरों के प्रबंधन को लेकर देश में लगातार बहस और विमर्श चल रहा है। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका भी पड़ी हुई है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी के बाद इस विषय को एक बहुत बड़े वर्ग ने नए सिरे से गर्म करने की कोशिश की है। इनमें नेताओं, निहित स्वार्थी तत्वों, मंदिरों के महत्व से अनभिज्ञों आदि की बड़ी संख्या शामिल है। हालांकि संपूर्ण इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की कोई भी व्यवस्था शत- प्रतिशत बेईमानी, पाप, भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुई हो इसके उदाहरण न के बराबर हैं। प्रश्न यही है कि आखिर श्रेष्ठतम व्यवस्था क्या हो सकती है? मंदिरों के आविर्भाव के साथ भारत में इसकी स्थापित परंपराएं हैं।**

पिछले काफी समय से मंदिरों के प्रबंधन को लेकर देश में लगातार बहस और विमर्श चल रहा है। मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका भी पड़ी हुई है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी के बाद इस विषय को एक बहुत बड़े वर्ग ने नए सिरे से गर्म करने की कोशिश की है। इनमें नेताओं, निहित स्वार्थी तत्वों, मंदिरों के महत्व से अनभिज्ञों आदि की बड़ी संख्या शामिल है। हालांकि संपूर्ण इतिहास में किसी धार्मिक स्थल की कोई भी व्यवस्था शत- प्रतिशत बेईमानी, पाप, भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हुई हो, इसके उदाहरण न के बराबर हैं। हां, ऐसा करने वालों को दंड, पाप मोचन तथा सुधार की व्यवस्था सतत् रही है।

इसके बावजूद हमारे मंदिर हर दृष्टि से धार्मिक मान्यताओं और हमारी आस्थाओं के अनुरूप पावन पुण्य स्थल बन रहें, श्रद्धालुओं के मन में वहां से जीवन में शुचिता, नैतिकता, सेवा, दान व ईमानदारी की प्रेरणा मिले इसके लिए मनुष्य के रूप में जितना संभव है, श्रेष्ठतम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न यही है कि आखिर श्रेष्ठतम व्यवस्था क्या हो सकती है? मंदिरों के आविर्भाव के साथ भारत में इसकी स्थापित परंपराएं हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारे मंदिर केवल कर्मकांड, पूजा- पाठ व दर्शन के केंद्र नहीं थे। मंदिरों की भूमिका समाज के मुख्य शक्ति केंद्र के रूप में भी थी। आज भी प्रमुख मंदिरों द्वारा शिक्षालय, अस्पताल, औषधालय,योग आश्रम, विचार प्रसार केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रकाशन, मुफ्त भोजनालय, समाज के निर्धन निराश्रित लोगों की सहायता सेवा आदि संचालित होते हैं।

यह उसी परंपरा का अंग है। ज्यादातर मंदिर ऐसा करते हुए प्रचार-प्रसार में नहीं पड़ते ते इसलिए दुनिया में ईसाई मिशनरियों ने ही यह भाव फैलाया है कि दान, गरीबों की सेवा, मनुष्य को शिक्षित करने की भूमिका केवल वही निभाते हैं। यह सरासर झूठ है। साफ है कि अगर मंदिरों के प्रबंधन की बात करें तो उसके पूरे व्यापक आयाम को ध्यान में रखकर ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

समाज और सत्ता का समन्वय

राजा या वैभवशाली, संपन्नशाली लोग मंदिर अवश्य बनवाते थे और प्रबंधन में उनकी भूमिका भी होती थी, पर संपूर्ण निजी मंदिरों को छोड़कर नियंत्रण जैसी स्थिति नहीं रही। उसके संपूर्ण विधि विधान ही नहीं, प्रबंधन की विधियां भी धर्म क्षेत्र - द्वारा ही निर्धारित होती थी। मंदिर के प्रबंध का सूत्र समाज क्षेत्र और सत्ता तंत्र के समन्वय से होता था। दक्षिण में आगमों के द्वारा मंदिर के पूजा विधान तय होते थे। समाज की समितियां कई बार जिसे सभा - महासभा कहते थे जिनमें विद्वान बुजुर्ग आदि होते थे, प्रतिदिन की व्यवस्था संभालते थे। आज भी हम दक्षिण के कुछ मंदिरों के अंदर धन देख, सुनकर चकित होते हैं और कई प्राचीन राज परिवार अभी भी मंदिरों की प्रमुख भूमिका में हैं। पर उनका नियंत्रण नहीं है। भाव यही है कि हम केवल उस धन के न्यासी हैं, उनमें से रति भर भी स्वयं के लिए उपयोग करने का अधिकार हमें नहीं है।

संपूर्ण देश के लिए एक संरचना उपयुक्त नहीं

वस्तुतः मंदिरों को सरकारी व्यवस्था, ट्रस्ट तंत्र के हवाले करना सच कहें तो धार्मिक विधान के ही विपरीत है और उससे उसकी मूल स्वायत्तता दुष्प्रभावित हो जाती है। झूठे वही खाता बनाने पड़ते हैं। दूसरे, संपूर्ण देश के लिए कोई एक संरचना उपयुक्त नहीं हो सकती।

यह भी ध्यान रखिए कि भारत के अनेक प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन इतने अच्छे हैं कि उनमें ज्यादा परिवर्तन या हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। आज भी समितियों की बैठकें होती हैं और उनके अनुसार निर्णय भी होते हैं। मूल बात हिंदू समाज के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की है जो आगे बढ़ रही है। अच्छा हो कि धर्म तंत्र, धार्मिक विशेषज्ञ, समाज क्षेत्र में इसके अन्य ज्ञाता, आस्थावान इतिहासकार सब मिलकर धार्मिक विघ्नों एवं परंपराओं के आरोप स्थानीय स्थान पर व्यवस्था बनाएं। मंदिरों के महत्व, उनकी व्यवस्था को न जानने वाले निहित स्वार्थी तत्वों के हल्ला बोल में पड़ने की आवश्यकता नहीं।

चैरिटेबल सोसायटी एक्ट

यह भी समझने की आवश्यकता है कि भारत में विविधताओं के बीच मूल भाव एक ही रहा है किंतु स्थानीय प्रकृति , परंपरा, रीति - रिवाज , धार्मिक आस्थाएं, ज्ञान आदि के अनुसार ही मंदिरों के प्रबंधन होते थे। हजार वर्षों के आक्रमणों, परकीय शासनों के कारण समस्याएं पैदा हुई और स्वतंत्रता के बावजूद जीवन का मूल होते हुए भी समाज की प्राथमिकता में नहीं रहा। बावजूद आज भी प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था अपनी स्थापित परंपरा के अनुसार अभी भी काफी हद तक उपयुक्त और प्रेरणादायी हैं। दरअसल, अंग्रेजों ने भारत को हर दृष्टि से गुलाम करने के लिए 1860 में चैरिटेबल सोसायटी एक्ट बनाया तथा सभी के लिए इस कानून के तहत निबंधन अनिवार्य किया। इस एक कानून ने पूरे भारत में मंदिरों से लेकर सेवा परंपराओं सहित दान शालाओं, शिक्षा शालाओं की प्रकृति को ही विकृत कर दिया। आज भी ऐसे सरकारी विभागों की दशा कैसी है, वे कैसा व्यवहार करते हैं यह अनुभव दिल दहलाने वाला है।

व्यवस्था में भ्रष्टाचार का दलदल

कम से कम इस तरह के प्रबंधन से मंदिरों की स्वतः स्फूर्त सुधार व्यवस्था के साथ-साथ पूरा कर्मकांड तक दुष्प्रभावित होता है। राज्यों के धार्मिक न्यास बोर्डों के हस्तक्षेप के कारण धार्मिक, सत्यनिष्ठ, नैतिक लोगों के लिए भी मंदिर का संचालन कठिन हो जाता है। मंदिरों में तात्कालिक कई खर्च ऐसे होते हैं जो दे दिए पर उनका हिसाब-किताब रखना कठिन होता है। कई बार कुछ निर्माण होते हैं जिनके सम्पूर्ण व्यय को लिखना लगभग असंभव होता है।

न्यास बोर्डों को उनके फॉर्मेट के अनुरूप के साथ हिसाब - किताब चाहिए होता है। इनको पुजारी की नियुक्ति से लेकर प्रबंधन तक में हस्तक्षेप का अधिकार कई राज्यों में है। इस कारण पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। हिंदू समाज के पतन के कारण गांवों व शहरों के बड़ी संख्या में मंदिरों की संपत्तियों पर स्थानीय लोगों, बाहुबलियों और प्रभावी लोगों का कब्जा हो गया है और मंदिर पतन की अवस्था में हैं।

निगरानी, जवाबदेही और पूर्ण पारदर्शिता जरूरी

व्यवस्था
सुशील देव
स्वतंत्र पत्रकार

सनातन संस्कृति में कोई भी मंदिर लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक होता है। मगर जब मंदिरों की कुव्यवस्था को लेकर स्वर उठने लगते हैं तो आस्था, विश्वास और श्रद्धा पर गहरी चोट पहुंचती है। अयोध्या के राम मंदिर में यही हुआ है। दान की चोरी का मामला बेहद निंदनीय है। करोड़ों लोगों की आस्था, लंबे संघर्ष और सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष के बाद यह मंदिर दोबारा अस्तित्व में आया था। यह मंदिर केवल धर्म-अध्यात्म का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए दान में चोरी का मामला वित्तीय अनियमितता से ज्यादा गंभीर है। अयोध्या का राम मंदिर मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हर कोई इस घटना की निंदा कर रहा है। अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। चढ़ावे या चंदे की लूट की चर्चा धर्मानुरागियों को आहत कर रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह एक असाधारण और अति निंदनीय घटना है, जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मंदिर प्रबंधन और सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की। इससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हुईं हैं। पूछताछ और जांच की कार्रवाई चल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा की जांच कर रही एसआईटी टीम ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले पांच सालों के खातों को फिर से आडिट करेगा, क्योंकि शुरूआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। देश में ऐसे कई मंदिर हैं जो कई बार चढ़ावे या चंदा गबन के कारण चर्चा में रहे हैं। ऐसे में न केवल उन मंदिरों के प्रबंधन को भी चुस्त—दुरूस्त रहना चाहिए, बल्कि स्थानीय प्रशासन और सरकार को निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया था। तभी से मंदिर में बड़ी मात्रा में चढ़ावा आ रहा है। साल 2024-25 में मंदिर ट्रस्ट ने कुल 327 करोड़ रुपए की आमदनी बताई थी, जिसमें 153 करोड़ चढ़ावे के रूप में मिली थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन 7 जून 2026 को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्रों से लगभग 7 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन हुआ है। इन आरोपों से पूरी अयोध्या में राजनीतिक भूचाल आ गया। इसके बाद भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कथित चंदा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कथित चंदा चोरी जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने कैश हैंडलिंग प्रक्रिया और डोनेशन बॉक्स की जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाला और वहां के कर्मचारियों से बात की तो कई विरोधाभास नजर आया। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई। नतीजतन, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुछ कर्मचारियों सहित आठ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी कारण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूरी कहानी से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ा, उनसे जो चढ़ावा मिला, उसे मंदिर ट्रस्ट सही रूप से व्यवस्थित रखने में नाकाम साबित हुआ। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट को मई अंतिम सप्ताह में ही कथित चंदा चोरी की भनक लगी थी, जब बैंकों में जमा हो रही रकम और दान पेटियों में कम चढ़ावा मिलने का शक हुआ था। उसके बाद वहां हिडन कैमरे लगा दिए थे और चौकसी बढ़ा दी गई थी। बावजूद इसके, कुछ लोभी प्रवृत्ति के लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया। यह घोटाला अब सरकार और जनता की अदालत से आगे कानून की अदालत तक पहुंच चुका है। इस मामले में चाक-चौबंद व्यवस्था होती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। राम मंदिर में अब तक जो भी दान प्राप्त हुआ, वह करोड़ों लोगों की आस्था की अमानत है। दान राशि के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। श्रद्धालुओं को नियमित रूप से यह जानकारी मिलनी चाहिए कि कितनी राशि प्राप्त हुई और उसका उपयोग किन कार्यों में किया जा रहा है। इसके लिए स्वतंत्र ऑडिट, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, सार्वजनिक आय-व्यय विवरण और डिजिटल दान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी लोगों का विश्वास होता है और यह विश्वास पारदर्शिता एवं नियमित संवाद से ही मजबूत होता है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने दलील दी है कि तमाम आरोप निराधार हैं। मंदिर निर्माण और दान राशि का पूरा लेखा-जोखा निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर रखा जा रहा है। अब तक सभी वित्तीय लेनदेन कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर किए गए हैं। जबकि विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दान राशि और भूमि खरीद से जुड़े कुछ मामलों पर पारदर्शिता बढ़ाने तथा स्वतंत्र जांच की लगातार मांग की जा रही है। सभी बड़े धार्मिक संस्थान में दान प्रबंधन को लेकर समय-समय सार्वजनिक जानकारी, नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग से भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है। सनद रहे कि मंदिर चढ़ावा विवाद का असर बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर पर भी पड़ा है।

> **धार्मिक संस्थान में दान प्रबंधन को लेकर समय-समय सार्वजनिक जानकारी, नियमित ऑडिट और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग से भ्रम की स्थिति को कम किया जा सकता है। सनद रहे कि मंदिर चढ़ावा विवाद का असर बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर पर भी पड़ा है।**

लोकहित में व्यय की जाए दान की रकम

मंथन
उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

अयोध्या के श्रीरामलला मंदिर के चढ़ावे की चोरी के खुलासे के बाद दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। समाज के एक वर्ग की ओर से उत्तर भारत के मंदिरों को भी सबक लेने और उनकी ही तर्ज पर प्रबंधन चलाने की मांग उठ रही है। इसकी वजह यह है कि दक्षिण भारत के बड़े मंदिरों, तिरूपति, अयप्पा, सबरीमाला, मीनांबकम् आदि के चढ़ावे की हेराफेरी की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। यह नहीं भूलना चाहिए कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उसे उचित बैंक तक पहुंचाने का भी तकरीबन वैसा ही इंतजाम किया गया है, जैसा शिरड़ी के साईं मंदिर या दक्षिण भारत के मंदिरों में किया गया है। असल समस्या मंदिर प्रबंधन में तैनात कर्मचारियों के चरित्र की है।

अगर कर्मचारी और अधिकारी ईमानदार होंगे तो फिर कड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं रह जाती। जहां तक दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन की बात है तो वहां के मंदिरों का प्रबंधन मोटे तौर पर संबंधित राज्य के कानून के जरिए बनाए गए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड करते हैं। हालांकि कुछ मंदिरों का प्रबंधन और संचालन उत्तर भारत के मठों की तरह वंशानुगत महंतों और ट्रस्टियों द्वारा भी किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड मंदिर की आय, दान, पुजारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं। मोटे तौर पर यह व्यवस्था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के ज्यादातर बड़े मंदिरों में लागू है। इसके तहत सरकार की ओर से मंदिर के लिए एक आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होता है, जो मंदिर के रोजाना का प्रशासन, सुरक्षा और कर्मचारी आदि की व्यवस्था देखते हैं। सरकार की ओर से नियुक्त बोर्ड में स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों, विद्वानों और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड प्रबंधन मंदिरों के चढ़ावे पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इसके लिए विशेष तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहां सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। चढ़ावे से प्राप्त रकम के आय-व्यय का लेखा-जोखा राज्य सरकार हर साल कर करती है। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर और कर्नाटक के उडुपी के मठ का प्रबंधन वहां के पारंपरिक शाही परिवार या उत्तर भारत की तरह वंशानुगत मठ के महंत के जरिए होता है, लेकिन इन मंदिरों के चढ़ावे आदि पर राज्य सरकार की निगरानी होती है। दक्षिण भारत के ज्यादातर बड़े मंदिरों के आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप होता है। हालांकि मंदिर की पूजा-पद्धति, अनुष्ठान, स्थानीय त्योहार आदि के आयोजन में राज्य सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। इस पर फैसले लेने का अधिकार वहां के पुजारियों को होता है। कुछ इसी तरह का प्रबंधन उत्तर भारत के भी कुछ बड़े मंदिरों का भी होता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में पारित श्रीमहाकालेश्वर मंदिर अधिनियम के तहत गठित 'महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति'करती है। उज्जैन के जिलाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस समिति में उज्जैन नगर निगम के पार्षद, राज्य सरकार द्वारा नामित संस्कृत के विद्वान और पुजारी सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी इसकी दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था और प्रबंधन के लिए एक प्रशासक को नियुक्त करते हैं। तिरूपति देवस्थान बोर्ड की ओर से करीब 35 स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर भारत का प्रसिद्ध वैष्णोदेवी मंदिर का भी संचालन कुछ इसी तरह होता है। 1986 में सरकार द्वारा बनाया गया श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड मंदिर और उसके चढ़ावे आदि का प्रबंधन करता है। श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड जम्मू-कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णोदेवी विश्वविद्यालय संचालित करता है। बोर्ड कटरा में श्री माता वैष्णोदेवी गुरुकुल का भी संचालन करता है। पटना के महावीर मंदिर का प्रबंधन भी इसी तरह से जनहित के लिए महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर आरोग्यालय आदि का संचालन करता है। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रबंधन की तरह श्रीरामलला मंदिर के प्रबंधन की मांग का एक वर्ग विरोध भी कर रहा है। इसके लिए दक्षिण भारत के मंदिरों की व्यवस्था का उत्तर वालों को गहन अध्ययन करना चाहिए और उसी तरह की व्यवस्था को अपनाना चाहिए। चूंकि चढ़ावे की रकम आम लोगों के दान की रकम होती है, लिहाजा इस रकम को लोकहित में स्कूल और अस्पताल चलाने, गरीबों को रोजगार आदि दिलाने का इंतजाम करने के मद में खर्च किया जाना चाहिए।

दक्षिण भारत के ज्यादातर बड़े मंदिरों के आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप होता है। हालांकि मंदिर की पूजा-पद्धति, अनुष्ठान, स्थानीय त्योहार आदि के आयोजन में राज्य सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। इस पर फैसले लेने का अधिकार वहां के पुजारियों को होता है।

आपदा प्रबन्धन में माहिर है भाजपा

दान चोरी प्रकरण
सुनील अमर
स्वतंत्र पत्रकार

देश का माहौल इन दिनों अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर में हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण से उद्वेलित है। मामले की जांच भी हो रही है। अपने देश का मिजाज ही कुछ ज्यादा धार्मिक है, इसलिए धर्म-कर्म होते रहते हैं और स्वाभाविक है कि उनमें अव्यवस्थाएं भी होती रहती हैं। अयोध्या का राम मन्दिर कांड कोई पहला नहीं है। देश के कई प्रमुख मन्दिरों में इससे पहले भी ऐसे कांड होते रहे हैं जिनमें तिरुमला वेंकटेश्वर मन्दिर, सबरीमला मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर तथा बीते जून महीने में ही हुए योग नरसिम्हा स्वामी मन्दिर का चढ़ावा चोरी मामले चर्चित हैं। अयोध्या मन्दिर का मामला इसलिए ज्यादा उबाल ले रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या आन्दोलन की नाव पर चढ़कर अपना राजनीतिक अभीष्ट प्राप्त किया।

दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रधानमन्त्री कार्यालय ने ही इस ट्रस्ट का गठन किया, इसके सदस्यों का चयन किया और खास बात यह कि इस ट्रस्ट की गतिविधियों को सूचना के अधिकार के बाहर कर दिया। रही बात राम मन्दिर चढ़ावा चोरी कांड से जनता पर असर पड़ने की तो अगर अतीत में हम देखें तो पता चलता है कि इस देश की जनता की राजनीतिक याददाश्त और भावनाएं दोनों बहुत टिकाऊ नहीं हैं। आखिर इसी देश में आपातकाल लगा, तमाम ज्यादतियां हुईं और मौका मिलने पर जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर जनता सारे दुःख भूल गई और दोबारा उसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता में स्थापित कर दिया। असल सवाल है जनता को बहलाने-फुसलाने का और भाजपा का प्रचार तंत्र इसमें माहिर है। भाजपा को राजनीतिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर लड़ना आता है। सांगठनिक तौर पर भाजपा आज देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। एक समय था कि वामदलों को कॉडर आधारित दल कहा जाता था। कांग्रेस के पास भी सेवादल हुआ करता था। बसपा संस्थापक कांशीराम ने भी पहले बामसेफ ही बनाया था लेकिन आज ये दल अपने इस मूलभूत ढांचों को खो बैठे हैं, जबकि भाजपा के साथ उसका मातृ संगठन आरएसएस अपने समस्त आनुषांगिक संगठनों के साथ आज पूरी क्षमता से कार्यरत है। ऐसे ताकतवर इन्फ्रास्ट्रक्चर से अन्य दल क्या मुकाबला कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा के पास अभी आपदा प्रबन्धन का थोड़ा समय है और भाजपा इसमें पारंगत है। आखिर बीते लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट, जिसके अन्तर्गत ही अयोध्या भी आती है, सपा के हाथों हार जाने के बाद भाजपा ने इसकी एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर को उपचुनाव में येन-केन-प्रकारेण जीत ही लिया था और प्रचारित किया था कि अयोध्या की जनता भाजपा से नाराज नहीं है। दूसरे, चुनावी प्रक्रिया इधर के वर्षों में बहुत हाईटेक और बहुत ज्यादा खर्चीली हो गई है। इस लिहाज से देखें तो भाजपा के मुकाबले कोई भी राजनीतिक दल टिकता ही नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक और पेचीदगी की बातें अपनी जगह। हिन्दू धर्म में दान की परम्परा बहुत उदारमना है। यहां तो 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' कहकर भगवान को चढ़ावा अर्पित किया जाता है। एक आस्थावान हिन्दू दान करने के बाद उसे भूल जाता है और फिर आगे उसका हिसाब नहीं रखता। जैसे भिखारी को भिक्षा देकर उस पर यह शर्त नहीं थोपी जाती कि वह इसे कैसे खर्च करेगा। यही वजह है कि देश के अन्य हिस्सों की बात छोड़ दें तो इस मुद्दे पर अयोध्या में स्थानीय स्तर पर जनता का कोई भी मुखर विरोध नहीं है। जो विरोध है वह संस्थागत स्तर पर ही है और भाजपा जनता की इस अमुखरता को भुनाएगी ही। राम मन्दिर चन्दा मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही है। आने वाले समय में भाजपा पर इसका क्या राजनीतिक असर दिखेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह महत्वपूर्ण होगा कि जांच का नतीजा क्या निकला। जिम्मेदार किसे ठहराया गया, सजा किसे हुई तथा व्यवस्था में परिवर्तन क्या किया गया और इन सबका जनता पर असर कैसा हुआ। भाजपा किसी लकीर को छोटा साबित करने के लिए बड़ी लकीर खींचने में माहिर है। चुनाव में अभी समय है और संभावना है कि तब तक भाजपा कोई ऐसा राजनीतिक/ सामाजिक तूफान खड़ा कर सकती है, जिसमें यह मन्दिर चढ़ावा चोरी ओझल ही हो जाए।

हिन्दू धर्म में दान की परम्परा बहुत उदारमना है। यहां तो 'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' कहकर भगवान को चढ़ावा अर्पित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि एक आस्थावान हिन्दू दान करने के बाद उसे भूल जाता है और फिर आगे उसका हिसाब नहीं रखता।

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक्स पर दी जानकारी, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में

लिखा कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने को मंजूरी दे दी है। परंपरानुसार सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। दोनों सदनों में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी कराई जाएगी। करीब 3सप्ताह के इस मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी।

बजट सत्र में 152 घंटे कामकाज हुआ था

इससे पहले संसद का बजट सत्र विगत 18 अप्रैल को समाप्त हुआ था। 28 जनवरीको शुरू हुए संसद के बजट सत्र में कई अहम विधेयक पारित कराए गए थे। स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक सत्र के दौरान 31 बैठकें हुईं। लगभग 151 घंटे 42 मिनट तक चली कार्यवाही के दौरान कई अहम विधेयकों पर चर्चा कराई गई थी।

किन मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष?

बीते दिनों मेडिकल की पढ़ाई से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षा- नीट के पेपर लीक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी विवाद जैसे कई मामले लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में हंगामा होने की आशंका है। इसके अलावा तृणमूल के दो फाड़ होने का मुद्दा भी चर्चा में है। नजरें स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं। कांग्रेस अंडमान की ग्रेट निकोबार परियोजना पर भी लगातार हमलावर है। ऐसे में हंगामे और नारेबाजी से सत्र की कार्यवाही बाधित हो सकती है।

12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए 9 विधेयक पारित

बिरला ने बताया था कि सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 09 विधेयक पारित किए गए। 131वें संविधान संशोधन विधेयक, 2026, संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पर 21 घंटे 27 मिनट तक चर्चा हुई। 131 सदस्यों ने भाग लिया था। कार्य-उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत रही थी।

संसद में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बिल

मित्तल बोले- न्याय सब के लिए समान होना चाहिए

राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने कहा है कि पुणे के केतन अग्रवाल का केस बहुत ही

ज्यादा चिंताजनक है। उनका कहना है कि केतन और उसके परिवार वालों को निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे पिछले साल संसद में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बिल भी पेश कर चुके हैं।

बजट सत्र में ये बिल पारित हुए

- औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
- उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
- वित्त विधेयक, 2026
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
- जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
- 93 प्रतिशत उत्पादकता, चर्चा में कई सदस्यों ने भाग लिया।

खबर संक्षेप

निर्वासन के लिए 50 बांग्लादेशी बंगाल पहुंचे

सलेम। तमिलनाडु से 50 बांग्लादेशी नागरिकों के समूह को ट्रेन से बंगाल भेजा गया ताकि उन्हें

उनके देश वापस भेजा जा सके। पुलिस ने जानकारी दी। वापस भेजे जा रहे इन लोगों में 44 पुरुष और छह महिलाएं शामिल हैं। इन्हें पहले सलेम जिले के अत्तूर तालुक कार्यालय परिसर में बने विशेष निरुद्ध शिविर में रखा गया था।

शिंदे को वायरल बुखार अस्पताल में भर्ती

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वायरल बुखार और सर्दी की शिकायत के बाद

ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराए गए उपमुख्यमंत्री को चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि शिंदे को जल्द अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

करनाल में कृषि-रसायन कारखाने में भीषण आग

चंडीगढ़। हरियाणा के करनाल में शनिवार को एक कृषि-रसायन कारखाने में भीषण आग लग गई।

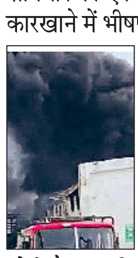

सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि नगला चौक के पास स्थित कारखाने के गोदाम में आग लगने के समय कोई मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।

मुंबई में बारिश से स्कूल-कॉलेज बंद

मुंबई। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अत्यधिक भारी बारिश का 'रेड अलर्ट' के बाद बीएमसी ने शनिवार

को महानगर के सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में दोपहर की पाली के लिए अवकाश घोषित कर दिया। बीएमसी ने बताया कि अत्यधिक भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर यह फैसला किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन

हम लोगों की सुविधाओं में कर रहे इजाफा युद्धकाल में विपक्ष ने नागरिकों को 'डराया'

प्रधानमंत्री ने पौधरोपण भी किया

एजेंसी ▶▶ जोधपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संशोधित 'उड़ान' योजना भी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य देश में विमानन कनेक्टिविटी का विस्तार और विमानन-आधारित विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें टर्मिनल की विभिन्न विशेषताओं की जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह परियोजना 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। इसमें आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस दौरान मोदी ने कहा कि युद्ध के दौरान कई अफवाहें फैलाई गईं। देशवासियों को डराया गया।

संशोधित 'उड़ान' योजना लॉन्च की विपक्ष पर बोला हमला → **480** करोड़ की लागत से तैयार हुआ → **23,000** वर्ग मीटर में फैला → **20** लाख यात्रियों को हर साल संभालने में सक्षम

उड़ान योजना की शुरुआत करते प्रधानमंत्री मोदी

राजस्थान की विरासत और हरित

राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित इस टर्मिनल की वास्तुकला में मेहराब और झरोखों जैसे पारंपरिक तत्वों को आधुनिक डिजाइन के साथ समाहित किया गया है। ऊर्जा-कुशल प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय और हरित भवन निर्माण पद्धतियां इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।

योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपए का प्रावधान

पीएम मोदी ने संशोधित 'उड़ान' योजना भी लॉन्च की। योजना के तहत 28,840 करोड़ रका आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य विमानन-आधारित विकास को गति देना है।

100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलिपैड विकसित होंगे

अप्रयुक्त हवाई पट्टियों का उपयोग करते हुए 100 हवाई अड्डों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए 12,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया

गिनाईं ये उपलब्धियां, विकास में बड़ा कदम बताया

प्रधानमंत्री ने जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल और करीब 79,459 करोड़ की लागत से विकसित पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण किया। रिफाइनरी से जुड़े पेट्रोकेमिकल जोन के विकास की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। इस रिफाइनरी से निकलने वाले उप-उत्पादों पर आधारित प्लास्टिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 'उड़ान' से मारवाड़ की समृद्ध विरासत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के इस अनूठे संगम में देश-विदेश से आने वाले यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

पचपदरा रिफाइनरी की खास बातें

पचपदरा रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल है। इसके निर्माण के लिए 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई।

राजस्थान की धरती के कण-कण ने हमें स्वाभिमान की सीख दी

पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान की धरती के कण-कण ने हमें स्वाभिमान की सीख दी है। यह रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी। भाजपा की सरकारें केवल परियोजनाओं का शिलान्यास करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़तीं।

छोटे-छोटे क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह टर्मिनल मारवाड़ के विकास को नई गति देगा। इसके तहत दूर-दराज के छोटे-छोटे क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा। राजस्थान के 54 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए।

युद्ध के बीच घरेलू गैस की कीमतें रहीं अप्रभावित

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। सरकार ने प्रभावी प्रबंधन के जरिए इसकी कीमत करीब 950 रुपए के आसपास बनाए रखी।

हमने किसानों को 300 रुपए में दी यूरिया

पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण खाद का गंभीर संकट पैदा हो गया था। एक बोरी यूरिया की कीमत 3,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच गई थी। हमने किसानों को यूरिया मात्र 300 रुपए में उपलब्ध कराया, सब्सिडी भी दी।

दूसरे देशों के साथ दोस्ती बहुत काम आई

पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ दोस्ती बहुत काम आई। पहले भारत 25-26 देशों से ईंधन का आयात करता था, लेकिन संकट के समय भारत की रणनीति का जलवा दिख गया।

पहली बार लखनऊ पहुंचे नबीन

रोड शो में बरसे फूल... प्रदेश मुख्यालय में की अहम बैठक

मुख्यमंत्री योगी ने किया नबीन का स्वागत

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ लखनऊ

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नितिन नबीन शनिवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पगुच्छ देकर व भगवा अंगवस्त्र पहनाकर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। योगी ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों व कार्यकर्ताओं का परिचय भी कराया। योगी ने 'एक्स' पर लिखा कि प्रभु श्रीराम एवं लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण के चरणरज से पावन हुई संस्कृति, संस्कार और सृजन की साधना स्थली उत्तर प्रदेश में नबीन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

फिर से कमल खिलेगा

नबीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फिर से कमल खिलेगा और पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाया गया प्यार और स्नेह संकेत देता है कि 2027 में कमल निश्चित रूप से खिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 'डबल इंजन' सरकार मोदी-योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदल दिया है, कमल निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में खिलने के लिए तैयार है।

योगी बोले- हार्दिक स्वागत व अभिनंदन

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर किए गए पोस्ट में लिखा कि प्रभु श्रीराम एवं लीलाधारी भगवान श्रीकृष्ण के चरणरज से पावन हुई संस्कृति, संस्कार और सृजन की साधना स्थली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

उत्साह बता रहा फिर बनेगी भाजपा सरकार

नबीन ने कहा कि उत्तर प्रदेश की इस धरती को नमन करता हूं। प्रभु श्रीराम की धरती, भोले बाबा की धरती, श्रीकृष्ण की धरती को नमन करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करता हूं। यह उनका कार्यक्षेत्र रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है, निश्चित रूप से भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। इस कार्ययोजना पर हम काम कर रहे। नबीन का स्वागत करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष/केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, भूपेंद्र चौधरी, एके शर्मा, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता 'नन्दी', संजय निषाद, दारा सिंह, जेपीएस राठौर, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, संजय सेठ, ब्रजलाल, महापौर सुषमा खर्कवाल समेत जनप्रतिनिधि शामिल रहे।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर खुशखबर

रेलमंत्री ने बताया.. 80 फीसदी काम पूरा, अगले साल से सफर

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। अगले साल अगस्त तक

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर पहली ट्रेन शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को ऐलान किया है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला सेक्शन 2027 में तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य 80 फीसदी पूरा हो चुका है।

चरणों में शुरू होगा पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

वैष्णव ने बताया कि प्रोजेक्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगले साल सूरत से बिलिमोरा तक का पहला सेक्शन चालू हो जाएगा, इसके बाद वापी से सूरत वाला सेक्शन शुरू होगा. फिर वापी से अहमदाबाद वाला सेक्शन पूरा किया जाएगा।

बिहार में एक और पुल गिरा

ब्रिज का स्लैब गिरने से कई मजदूर घायल

समस्तीपुर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले ताजपुर-बख्तियारपुर गंगा सेतु के निर्माण कार्य के दौरान शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर-जौनापुर गंगा घाट के पास निर्माणाधीन पुल के पिलर संख्या-58 के समीप अचानक स्लैब टूटकर गिर गया।

ममता को एक और बड़ा झटका

प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा

एजेंसी ▶▶ कोलकाता

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बेनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है।

एक दिन पहले ही ममता के पार्टी ऑफिस पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया था और अब टीएमसी की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। चंद्रिमा को ममता की करीबी नेता माना जाता है।

3 जून को ही प्रदेश अध्यक्ष बनीं

चंद्रिमा को बंगाल चुनाव में हार के बाद 3 जून को ही सुब्रत बक्शी की जगह अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ममता ने विधायकों की बगावत के बाद पार्टी की सभी समीतियों को भंग कर दिया था और संगठन में बड़े बदलाव किए थे। चंद्रिमा ने लिखा कि वे सौंपे गए टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने मध्य वर्ग को भारत का वृद्धि इंजन बताया

500 शहर बनेंगे नए आर्थिक केंद्र, गतिविधियां बढ़ेंगी

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

फ्रांस के प्रमुख आर्थिक मंच 'रेनकॉन्ट्रेस इकनॉमिक्स डी एक्स-एन-प्रोवेंस' में बोलीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मध्य वर्ग को केवल वृद्धि का लाभार्थी नहीं, भारत का वृद्धि इंजन बताया। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 500 शहर आर्थिक गतिविधि के अगले केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार हैं। सीतारमण फ्रांस के एक प्रमुख आर्थिक मंच 'रेनकॉन्ट्रेस इकनॉमिक्स डी'एक्स-एन-प्रोवेंस' में एक पैनल चर्चा में भाग ले रही थीं। उन्होंने बताया कि आज भारत की 31 फीसदी आबादी मध्य वर्ग में आती है। भारत की अर्थव्यवस्था खुलने के बाद से मध्य वर्ग सालाना 6.3 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। उनका अनुमान है कि भारत में कुल खर्च का 93 फीसदी मध्य वर्ग या थोड़े संपन्न उपभोक्ताओं के कारण होगा। सीतारमण ने बताया कि यह मध्य वर्ग केवल महानगरों में केंद्रित नहीं है।

कोविड के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही

सीतारमण ने कहा कि मध्य वर्ग की खपत ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। एक ओईसीडी अध्ययन का हवाला देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण भारत 2030 से 2035 के बीच मध्य वर्ग की आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। कोविड-19 के बाद भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसका मुख्य कारण मध्य वर्ग द्वारा प्रेरित खपत है।

मध्य वर्ग के लिए सरकार दे रही सहूलियतें

मध्य वर्ग के आकार को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इनमें वित्तीय समावेशन, हालिया जीएसटी दर युक्तिकरण और बिना गारंटी ऋण प्रदान करना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इन पहलों का हिस्सा है। इन कदमों से मध्य वर्ग को लाभ मिल रहा।

लोग तकनीकी कौशल को उन्नत कर रहे

सीतारमण ने कहा कि लोग आगे रहने के लिए लगातार अपने तकनीकी कौशल को उन्नत कर रहे हैं। जो लोग एआई से नौकरियों के विस्थापन से डरते हैं, उनके लिए सरकार व्यापक सहायता दे रही है। देश भर में एआई-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में जिला स्तर पर एआई कौशल शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

पति को निजता का अधिकार, उचित प्रतिबंध भी संभव, दावा खारिज किया

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें तलाक के मामले में विवाह-बाह्य संबंध के आरोपी पति के 'निजता के अधिकार' के दावे को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पत्नी पति पर लगे विवाह-बाह्य संबंध के आरोप को साबित करने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड और होटल बुकिंग से जुड़ी जानकारी जैसे साक्ष्य जुटाने के लिए अदालत की मदद ले सकती है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अलग रह

रहे पति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। अपील खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमें हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती।

हाई कोर्ट ने यह कहा था

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून विवाह-बाह्य संबंध को तलाक का वैध आधार मानता है। ऐसे में किसी विवाहित पुरुष पर यदि विवाह के दौरान किसी अन्य महिला के साथ यौन संबंध का आरोप है, तो केवल 'निजता के अधिकार' का हवाला देकर उसे कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार संरक्षित मौलिक अधिकार है, पर यह पूर्ण या असीमित नहीं है।

■ 60 हजार बचाने के चक्कर में गंवा सकते हैं 82 लाख रुपये

■ कंपाउंडिंग बताता है कि निवेश में समय ही सबसे बड़ी पूंजी

■ जल्दी शुरुआत करने वालों को मिलता है सबसे बड़ा फायदा

एसआईपी में सिर्फ 1 वर्ष की देरी पड़ सकती है भारी

निवेश मंत्रा
बिजनेस डेस्क

म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जितना अधिक पैसा निवेश करेंगे, उतना बड़ा फंड तैयार होगा। यह बात सही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। निवेश विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश की रकम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है निवेश की शुरुआत का समय। यदि कोई व्यक्ति एसआईपी शुरू करने में सिर्फ एक साल की भी देरी करता है तो उसे भविष्य में लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार कंपाउंडिंग की ताकत समय के साथ सबसे अधिक काम करती है। यही वजह है कि एसआईपी की पहली किस्त की कीमत आखिरी किस्त से कई गुना ज्यादा होती है। एक साल की देरी केवल 12 किस्तों का नुकसान नहीं कराती, बल्कि उन किस्तों पर मिलने वाले वर्षों के रिटर्न से भी निवेशक वंचित रह जाता है।

क्यों सबसे अहम है पहली एसआई

कंपाउंडिंग का अर्थ है कि निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगता है। यानी आपका पैसा केवल बढ़ता नहीं, बल्कि बढ़ा हुआ पैसा भी कमाई करता है। यदि कोई निवेशक 30 वर्ष तक लगातार एसआईपी करता है, तो पहले साल जमा की गई रकम को पूरे 30 वर्षों तक बढ़ने का मौका मिलता है। वहीं अंतिम वर्ष में जमा की गई राशि को केवल कुछ महीनों का ही समय मिलता है। यही कारण है कि शुरुआती निवेश की ताकत सबसे अधिक होती है। विशेषज्ञ इसे निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा जादू मानते हैं। जितनी जल्दी शुरुआत होगी, कंपाउंडिंग उतना ही अधिक काम करेगी।

एक साल की देरी का बड़ा नुकसान

मान लीजिए कोई निवेशक हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करता है और उसे औसतन 12 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न मिलता है। यदि वह लगातार 30 वर्षों तक निवेश करता है तो कुल निवेश राशि 18 लाख रुपये होगी। इस अवधि के अंत में उसका फंड लगभग 1.76 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि वही निवेशक एसआईपी शुरू करने में सिर्फ एक वर्ष की देरी कर देता है और केवल 29 वर्ष निवेश करता है, तो उसका अंतिम फंड घटकर लगभग 1.56 करोड़ रुपये रह जाएगा। यानी केवल 60 हजार रुपये (12 किस्तें) का निवेश टालने की कीमत लगभग 20.43 लाख रुपये हो सकती है। यह उदाहरण बताता है कि निवेश में सबसे बड़ा नुकसान बाजार की गिरावट नहीं, बल्कि समय गंवाने से होता है।

जितनी बड़ी एसआई, उतना नुकसान

एक साल की देरी का असर निवेश राशि बढ़ने के साथ और भी ज्यादा दिखाई देता है। यदि कोई निवेशक हर महीने 2,000 रुपये की एसआईपी करता है तो एक साल की देरी से लगभग 8.17 लाख रुपये का संभावित नुकसान हो सकता है। 10,000 रुपये मासिक एसआईपी करने वाले निवेशक के लिए यही नुकसान बढ़कर लगभग 40.87 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं यदि मासिक एसआईपी 20,000 रुपये की है तो केवल एक साल की देरी भविष्य में करीब 82 लाख रुपये के संभावित फंड को कम कर सकती है। यही कारण है कि निवेश विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि ₹सही समय का इंतजार मत कीजिए, समय को अपने पक्ष में कीजिए।

आखिर में रफ्तार पकड़ती है कंपाउंडिंग

एसआईपी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि शुरुआती वर्षों में निवेश की रफ्तार धीमी लगती है, लेकिन बाद के वर्षों में वही निवेश तेजी से बढ़ने लगता है।

उदाहरण के तौर पर 5,000 रुपये की मासिक एसआईपी में

- 10 वर्ष बाद कुल निवेश लगभग 6 लाख रुपये होगा और फंड करीब 11.62 लाख रुपये बन सकता है।
- 20 वर्ष बाद कुल निवेश 12 लाख रुपये होगा, लेकिन फंड करीब 50 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
- 30 वर्ष पूरे होने पर कुल निवेश 18 लाख रुपये रहेगा, जबकि फंड बढ़कर लगभग 1.76 करोड़ रुपये हो जाएगा।
- यानी अंतिम दस वर्षों में केवल 6 लाख रुपये का अतिरिक्त निवेश पूरे फंड को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.76 करोड़ रुपये तक पहुंचा देता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है।

शुरुआत में देरी हो गई तो क्या करें?

यदि किसी कारणवश एसआईपी शुरू करने में देरी हो गई है तो भी नुकसान की भरपाई की जा सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि आपने पहला साल गंवा दिया है तो शेष अवधि में अपनी मासिक एसआईपी थोड़ी बढ़ाकर इस अंतर को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपकी योजना 5,000 रुपये मासिक एसआईपी की थी और एक साल की देरी हो गई, तो अगले 29 वर्षों तक लगभग 5,655 रुपये प्रति माह निवेश करके उस संभावित अंतर को काफी हद तक भरा जा सकता है। यानी हर महीने केवल 655 रुपये अतिरिक्त निवेश भविष्य में लाखों रुपये का अंतर पैदा कर सकता है।

छोटी एसआईपी भी बनेगी बड़ा फंड

- कई लोग सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम होना जरूरी है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।
- वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि यदि फिलहाल बड़ी राशि उपलब्ध नहीं है तो 500 रुपये, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है। जैसे-जैसे आय बढ़े, वैसे-वैसे एसआईपी की राशि भी बढ़ाई जा सकती है।
- नियमित निवेश और लंबी अवधि का अनुशासन ही बड़ा कोष तैयार करने की सबसे प्रभावी रणनीति है।

समय ही सबसे बड़ा निवेश है

विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश की दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं, बल्कि समय है। बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों को कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। यदि आप भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो निवेश की शुरुआत टालने के बजाय जितनी जल्दी संभव हो, उतनी जल्दी एसआईपी शुरू करें। छोटी-सी शुरुआत भी समय के साथ करोड़ों रुपये का फंड तैयार कर सकती है। इसलिए निवेश का सबसे अच्छा समय आज है, क्योंकि एक साल की देरी भविष्य में लाखों नहीं, बल्कि बड़े निवेशकों के लिए करोड़ों रुपये तक का अंतर पैदा कर सकती है।

पीपीएफ या म्यूचुअल फंड पर लें लोन?

- इमरजेंसी में कौन सा विकल्प है बेहतर
- अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर निवेश तोड़े बिना मिल सकती रकम
- दोनों विकल्पों के फायदे, नुकसान और किसके लिए कौन बेहतर

बिजनेस डेस्क

अचानक मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस में नकदी की जरूरत या किसी अन्य जरूरी खर्च के लिए अक्सर लोग अपने निवेश तोड़ देते हैं। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेश को समय से पहले भुनाने के बजाय उसके बदले लोन लेना कई बार अधिक फायदेमंद साबित होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और म्यूचुअल फंड, दोनों पर लोन लेने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन दोनों की शर्तें, ब्याज दरें और लोन की सीमा अलग-अलग हैं। ऐसे में जरूरत और निवेश के आधार पर सही विकल्प चुनना जरूरी है।

पीपीएफ पर लोन: कम ब्याज, लेकिन सीमित सुविधा

पीपीएफ पर लोन केवल एक निश्चित अवधि के दौरान ही लिया जा सकता है। खाता खुलने वाले वित्तीय वर्ष के तीसरे साल से लेकर छठे वित्तीय वर्ष तक ही यह सुविधा मिलती है। यदि पहले लिया गया लोन पूरी तरह चुका दिया गया हो, तभी अगला लोन लिया जा सकता है। लोन की अधिकतम राशि आवेदन से दो वित्तीय वर्ष पहले के खाते में उपलब्ध बैलेंस के केवल 25 प्रतिशत तक सीमित होती है। चूंकि पीपीएफ सरकार समर्थित बचत योजना है, इसलिए इस पर ब्याज भी कम लगता है। वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलता है और लोन की ब्याज दर इससे केवल 1 प्रतिशत अधिक यानी लगभग 8.1 प्रतिशत है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी निवेशक को चार लाख रुपये का लोन चाहिए तो उसके पीपीएफ खाते में लगभग 16 लाख रुपये का बैलेंस होना आवश्यक होगा, क्योंकि केवल 25 प्रतिशत राशि ही लोन के रूप में मिल सकती है।

म्यूचुअल फंड पर लोन : ज्यादा रकम और अधिक लचीलापन

म्यूचुअल फंड के बदले लोन निवेशकों के लिए अधिक लचीला विकल्प माना जाता है। यह सुविधा फिजिकल और डीमैट दोनों रूपों में रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर उपलब्ध है। इसका लाभ व्यक्तिगत निवेशकों के अलावा एचयूएफ, कंपनियां, एलएलपी, ट्रस्ट और साझेदारी फर्में भी ले सकती हैं। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और लिक्विड फंड सभी पर लोन मिल सकता है, हालांकि लोन की सीमा फंड के प्रकार पर निर्भर करती है। डेट और लिक्विड फंड पर आमतौर पर 70 से 80 प्रतिशत तक लोन मिल जाता है, जबकि इक्विटी फंड पर यह सीमा लगभग 50 प्रतिशत रहती है। यदि किसी निवेशक को चार लाख रुपये की जरूरत है तो करीब आठ लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश के आधार पर यह राशि मिल सकती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेशक की यूनिट्स बिकती नहीं हैं और वे बाजार में निवेशित बनी रहती हैं, जिससे लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण जारी रहता है।

ब्याज और जोखिम में बड़ा अंतर

म्यूचुअल फंड पर लोन की ब्याज दर आमतौर पर 9 से 12 प्रतिशत के बीच होती है। कई बैंक और वित्तीय संस्थान इसे ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में देते हैं, जिसमें केवल इस्तेमाल की गई राशि पर ही ब्याज देना पड़ता है। हालांकि इसमें एक जोखिम भी है। यदि बाजार गिरता है और म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) कम हो जाती है, तो बैंक अतिरिक्त सिक्योरिटी या आंशिक भुगतान की मांग कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर गिरवी रखी गई यूनिट्स बेची भी जा सकती हैं।

किसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जो नियमित एसआईपी करते हैं और अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना चुके हैं, म्यूचुअल फंड पर लोन बेहतर विकल्प माना जाता है। इससे निवेश टूटता नहीं और कंपाउंडिंग का लाभ भी जारी रहता है। स्वरोजगार या व्यवसाय करने वालों के लिए भी म्यूचुअल फंड पर लोन अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें बड़ी राशि अपेक्षाकृत जल्दी मिल सकती है।

एसआईएफ की बढ़ती लोकप्रियता से लंपसम निवेश को मिल रही है चुनौती

10 लाख की न्यूनतम निवेश सीमा के बावजूद एसआईएफ की ओर बढ़ा रुझान

जानकारी
बिजनेस डेस्क

विशेषज्ञों का कहना है कि पहले लॉन्ग-शॉर्ट निवेश रणनीति का लाभ केवल कैटेगरी-III अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) के माध्यम से ही मिल पाता था। लेकिन एआईएफ में निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये होती है, जो अधिकांश निवेशकों की पहुंच से बाहर है। इसके विपरीत एसआईएफ में केवल 10 लाख रुपये से निवेश संभव है। इससे संपन्न निवेशकों को कम पूंजी में वही निवेश रणनीति अपनाने का अवसर मिल रहा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में एचएनआई निवेशक अब एसआईएफ को अपनाने लगे हैं।

म्यूचुअल फंड उद्योग में लंपसम निवेशकों के लिए एक नया विकल्प तेजी से उभर रहा है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआईएफ) की बढ़ती लोकप्रियता अब पारंपरिक इक्विटी म्यूचुअल फंडों के लंपसम निवेश को चुनौती देती दिखाई दे रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के महीनों में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में लंपसम निवेश घटने के पीछे एसआईएफ की बढ़ती स्वीकार्यता भी एक अहम वजह हो सकती है। पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंडों में शुद्ध निवेश (नेट इनफ्लो) में करीब 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दूसरी ओर एसआईपी (एसआईपी) निवेश लगातार मजबूत बना रहा। इससे यह संकेत मिला कि छोटे निवेशक नियमित निवेश जारी रखे हुए हैं, जबकि बड़े निवेशक अब नए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।

सात माह में सात गुना बढ़ा एयूएम

पिछले वर्ष शुरू किए गए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स ने बेहद कम समय में निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। अक्टूबर 2025 में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) लगभग 2,010 करोड़ रुपये था, जो मई 2026 तक बढ़कर 13,814 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया। यानी महज सात महीनों में इनका आकार लगभग सात गुना बढ़ गया। हालांकि एसआईएफ में निवेश के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये की सीमा तय की गई है, फिर भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (एचएनआई) निवेशकों में इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है।

हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट स्कीम पसंद

एसआईएफ के भीतर सबसे अधिक लोकप्रियता हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट स्कीम को मिली है। मई 2026 तक इस श्रेणी में करीब 9,709 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो कुल एसआईएफ एसेट्स का लगभग 70 प्रतिशत है। इन योजनाओं में प्रति फोलियो औसत निवेश भी सबसे अधिक रहा। हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट स्कीम में औसत निवेश करीब 33.86 लाख रुपये प्रति फोलियो दर्ज किया गया। इसके मुकाबले इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट स्कीम में यह आंकड़ा 15.64 लाख रुपये और इक्विटी एक्स-टॉप-100 लॉन्ग-शॉर्ट स्कीम में 12.77 लाख रुपये रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा बताता है कि संपन्न निवेशक इस नई श्रेणी पर तेजी से भरोसा जता रहे हैं।

क्यों बढ़ रही है एसआईएफ मांग

बाजार जानकारों के अनुसार एसआईएफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह निवेशकों को बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न देने की कोशिश करता है। विशेष रूप से हाइब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति बाजार में गिरावट के दौरान भी नुकसान को सीमित रखने का प्रयास करती है। हालिया बाजार सुधार के दौरान इन योजनाओं ने सकारात्मक रिटर्न देकर निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। यही वजह है कि कई निवेशक अब पारंपरिक लंपसम इक्विटी निवेश की जगह एसआईएफ को प्राथमिकता दे रहे हैं।

म्यूचुअल फंडों पर पड़ेगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि एसआईएफ पारंपरिक म्यूचुअल फंडों का स्थान ले लेंगे। फिलहाल इसका प्रभाव मुख्य रूप से बड़े लंपसम निवेशकों तक सीमित है। एसआईपी निवेश में किसी प्रकार की कमजोरी देखने को नहीं मिली है। इससे स्पष्ट है कि खुदरा निवेशक अभी भी नियमित निवेश के लिए पारंपरिक म्यूचुअल फंडों पर भरोसा बनाए हुए हैं। हालांकि यदि एसआईएफ का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहता है तो आने वाले वर्षों में बड़े निवेशकों का एक हिस्सा इस श्रेणी की ओर शिफ्ट हो सकता है।

किन निवेशकों के लिए बेहतर है एसआईएफ

विशेषज्ञों के अनुसार एसआईएफ उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनके पास पहले से बड़ा निवेश पोर्टफोलियो है और जो बाजार की अस्थिरता के बीच बेहतर जोखिम प्रबंधन चाहते हैं। विशेष रूप से ऐसे निवेशक जो एकमुश्त बड़ी राशि निवेश करते हैं और केवल इक्विटी पर निर्भर नहीं रहना चाहते, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प बन सकता है। इसके अलावा फिक्स्ड इनकम निवेशक, जो सीमित जोखिम के साथ अपेक्षाकृत बेहतर रिटर्न चाहते हैं, वे भी भविष्य में इस श्रेणी की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

अभी भी कई चुनौतियां बाकी

हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि एसआईएफ को व्यापक स्तर पर लोकप्रिय होने में अभी समय लगेगा। निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने, वितरकों को प्रशिक्षित करने और लंबी अवधि का प्रदर्शन रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ही यह श्रेणी बड़े पैमाने पर स्वीकार की जाएगी। निवेशकों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे केवल शुरुआती प्रदर्शन देखकर निवेश न करें, बल्कि फंड की रणनीति, जोखिम, शुल्क और अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें।

लंबी अवधि में बदल सकता है निवेश का परिदृश्य

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय निवेश उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। जैसे-जैसे निवेशकों की समझ बढ़ेगी, वे पारंपरिक इक्विटी और डेट फंडों से आगे बढ़कर नई निवेश रणनीतियों को भी अपनाएंगे। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इसी बदलाव का संकेत हैं। यदि इनका प्रदर्शन स्थिर और बेहतर बना रहता है तो आने वाले वर्षों में यह हाई नेटवर्थ निवेशकों के पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि खुदरा निवेशकों के लिए एसआईपी आधारित म्यूचुअल फंड अभी भी सबसे सरल, अनुशासित और प्रभावी निवेश विकल्प बने हुए हैं।

20 साल की एसआईपी में सिर्फ पांच फंड ही बने असली 'वेल्थ क्रिएटर'

बिजनेस डेस्क। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले अधिकांश निवेशकों का सपना होता है कि उन्हें लंबे समय तक लगातार बेहतर रिटर्न मिले। हालांकि, ऐसा करने वाले फंड बहुत कम हैं। करीब 600 सक्रिय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के विश्लेषण में केवल पांच ऐसी योजनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने 3, 5, 10, 15 और 20 वर्ष जैसी सभी प्रमुख निवेश अवधियों में 15 प्रतिशत से अधिक सालाना एसआईपी रिटर्न दिया है। यह विश्लेषण वैल्यू रिसर्च के 29 जून 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित है। सबसे खास बात यह है कि इस सूची में कोई भी फ्लेक्सी-कैप या लार्जकैप फंड शामिल नहीं है। दो मिडकैप, दो हेल्थकेयर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम आधारित फंड ने निवेशकों को लंबी अवधि में शानदार संपत्ति बनाने का अवसर दिया। यह दर्शाता है कि मजबूत सेक्टरों में लंबे समय तक धैर्य के साथ निवेश करने वाले निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिला।

ये हैं पांच सबसे सफल एसआईपी फंड

- इस सूची में एचएसबीसी मिडकैप फंड (रेगूलर) पहले स्थान पर है। इस फंड ने 3 वर्ष में 20.05%, 5 वर्ष में 21.46%, 10 वर्ष में 18.39%, 15 वर्ष में 18.96% और 20 वर्ष में 17.70% का वार्षिक एसआईपी रिटर्न दिया। निवेशक ने 20 वर्षों तक हर महीने 10,000 की एसआईपी की होती, तो उसका निवेश बढ़कर 1.86 करोड़ हो जाता।
- दूसरे स्थान पर एसबीआई हेल्थकेयर ऑपर्च्युनिटी फंड (रेगूलर) रहा। इसने 20 वर्षों में 16.80 प्रतिशत वार्षिक एसआईपी रिटर्न दिया और 10,000 मासिक निवेश को लगभग 1.68 करोड़ रुपये में बदल दिया।
- तीसरे स्थान पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड रहा। इस फंड ने 20 वर्षों में 16.52 प्रतिशत का रिटर्न दिया और लगभग 1.61 करोड़ का कोष तैयार किया।
- चौथे स्थान पर यूटीआई हेल्थकेयर म्यूचुअल फंड (रेगूलर) रहा, जिसने 20 वर्षों में 15.61 प्रतिशत रिटर्न देते हुए 10,000 की मासिक एसआईपी को लगभग 1.45 करोड़ रुपये तक पहुंचाया।
- पांचवें स्थान पर डीएसपी इंडिया टीआईजीईआर फंड (रेगूलर) रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर आधारित इस फंड ने 20 वर्षों में 15.40 प्रतिशत रिटर्न दिया और निवेशकों का कोष करीब 1.40 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।

अमेरिकी ब्याज दरों, ट्रेजरी यील्ड और वैश्विक अनिश्चितता से बढ़ा दबाव

सात माह के निचले स्तर पर सोना-चांदी, ऐसे में क्या करें निवेशक

बिजनेस डेस्क

जुलाई की शुरुआत सर्राफा बाजार के लिए झटके भरी रही। 1 जुलाई को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी, फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति के संकेत और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। इसका असर यह हुआ कि सोना और चांदी दोनों सात महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट केवल नकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर भी बन सकती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1,701 रुपये यानी 1.19 प्रतिशत टूटकर करीब 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी 5,380 रुपये यानी 2.35 प्रतिशत लुढ़ककर 2.23 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कमजोरी का यही रुख दिखाई दिया। कॉमेक्स पर सोना करीब 4,000 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर के आसपास सात महीने के निचले स्तर पर कारोबार करता रहा, जबकि चांदी लगभग तीन प्रतिशत गिरकर 57.73 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

अमेरिकी फेड की सख्ती बनी सबसे बड़ी वजह

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का सख्त रुख है। हाल के दिनों में फेड अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आती है तो इस वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है। ब्याज दरें बढ़ने से निवेशकों का रुझान सोने जैसी बिना ब्याज वाली परिसंपत्तियों से हटकर बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की ओर बढ़ जाता है। यही कारण है कि सोने और चांदी पर बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है।

ट्रेजरी यील्ड और मजबूत डॉलर का असर

अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यानी ट्रेजरी की यील्ड में तेजी ने भी सोने की चमक फीकी कर दी है। जब ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है तो निवेशकों को सुरक्षित और बेहतर रिटर्न वाले विकल्प मिलने लगते हैं। इससे सोने की मांग घटती है। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती आने से भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ा। चूंकि सोने का कारोबार डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर मजबूत होने पर अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है और मांग कमजोर पड़ जाती है।

मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव भी चिंता का कारण

मध्य-पूर्व में एक बार फिर बढ़ते तनाव ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में आई तल्खी तथा शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को सतर्क बना दिया है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे तनाव के दौरान सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन इस समय ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भी वैश्विक महंगाई को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। यदि तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ सकती है, जिससे केंद्रीय बैंक ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रख सकते हैं।

अब अमेरिकी आंकड़ों पर टिकी नजर

बाजार की अगली दिशा काफी हद तक अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। निवेशकों की नजर जून के **ADP** रोजगार आंकड़ों और नॉन-फार्म पेरोल डेटा पर है। यदि रोजगार के आंकड़े मजबूत आते हैं तो फेड के लिए ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने का आधार मजबूत होगा, जिससे सोने पर दबाव बना रह सकता है। वहीं, यदि आंकड़े उम्मीद से कमजोर आते हैं तो ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद बढ़ेगी और सोना-चांदी में रिकवरी देखने को मिल सकती है।

विशेषज्ञ बोले- जल्दबाजी नहीं, रणनीति के साथ ही करें निवेश

विशेषज्ञों की राय: अभी सतर्कता जरूरी

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल तकनीकी रूप से सोना और चांदी दोनों कमजोर स्थिति में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे बना रहता है तो अगला मजबूत सपोर्ट 3,600 डॉलर प्रति औंस के आसपास दिखाई देता है। इसी तरह चांदी यदि 60 डॉलर प्रति औंस के नीचे टिकती है तो इसमें 50 डॉलर प्रति औंस तक गिरावट की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि लगातार बिकवाली के कारण दोनों धातुएं अब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में किसी भी सकारात्मक वैश्विक संकेत या कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के बाद तेज तकनीकी रिकवरी भी संभव है।

क्या यह खरीदारी का सही समय है?

विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी का निवेश लक्ष्य पांच से दस वर्ष या उससे अधिक का है तो ऐसी गिरावट चरणबद्ध निवेश (स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट) का अवसर बन सकती है। एकमुश्त निवेश करने के बजाय किस्तों में खरीदारी करना अधिक सुरक्षित रणनीति मानी जा रही है। इससे यदि कीमतें और गिरती हैं तो औसत खरीद मूल्य कम किया जा सकता है। वहीं अल्पकालिक ट्रेडर्स को फेडरल रिजर्व के अगले संकेत, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए।

दीर्घकाल में बनी रहेगी सोने की अहमियत

सोना सदियों से महंगाई, आर्थिक संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के दौरान सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प माना जाता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पकाल में कीमतों में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन लंबी अवधि में सोना निवेश पोर्टफोलियो को स्थिरता देने का महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। यही कारण है कि वित्तीय सलाहकार कुल निवेश का एक हिस्सा सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं में रखने की सलाह देते हैं। मौजूदा गिरावट को केवल कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक निवेश के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी जोखिम क्षमता, निवेश अवधि और वित्तीय सलाहकार की राय को जरूर ध्यान में रखना चाहिए।

केप वर्दे ने छुड़ाए अर्जेंटीना के पसीने, मेस्सी सेना ने एक्स्ट्रा टाइम में जीता कड़ा मुकाबला

शर्मनाक रिकार्ड

एक विश्व कप में दो आत्मघाती गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हानी

अर्लिंगटन। मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी एक ही टूर्नामेंट में दो आत्मघाती गोल करने वाले विश्व कप के इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। आस्ट्रेलिया के मिडफील्डर एडेन ओ नील की 55वें मिनट में लगाई गई फ्रीकिक पर गेंद हानी के सिर से टकराकर मिस्र के गोल के भीतर ही चली गई। इससे पहले आस्ट्रेलियाई मिडफील्डर कोनोर मेटकाफे से टकराने के कारण हानी को चिकित्सा सहायता लेनी पड़ी थी। बेल्जियम के खिलाफ ग्रुप चरण में 1-1 से ड्रॉ रहे मैच में भी उन्होंने आत्मघाती गोल किया था।

एजेंसी ▶▶| मियामी गार्डन्स

इस विश्व कप में साहस और कौशल की नई परिभाषा लिखने वाले छोटे से देश केप वर्दे ने खिताब की प्रबल दावेदार मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को नाकों चने चबवा दिए और अतिरिक्त समय तक चले इस मुकाबले को जीतने के बाद लियोनेल मेस्सी और उनकी टीम ने मस्तक पर छलके पसीने को पोछकर मानों राहत की सांस ली। इसके साथ ही विश्व कप में 'छिपे रुस्तम' केप वर्दे का शानदार अभियान यही खत्म हो गया और जीत के साथ अर्जेंटीना अंतिम 16 में पहुंच गया। आसानी से हार नहीं मानने वाले केप वर्दे ने नियमित समय में और फिर अतिरिक्त समय में बराबरी के गोल दागे। अर्जेंटीना के तीसरे गोल का वह जवाब नहीं दे सके और मेस्सी की टीम ने 3-2 से मुकाबला जीता।

छोटे देश ने कराया इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज

हारने के बावजूद अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित इस द्वीप देश ने विश्व कप के इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। जीत के बाद अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने कहा,' मैं केप वर्दे को श्रेय देना चाहूंगा। सच यही है कि जब लोग कहते हैं कि कोई विरोधी टीम कमतर नहीं होती और आज केप वर्दे ने साबित कर दिया कि वह शानदार टीम है। केप वर्दे के लिए डाइनी बोर्गेस ने 111वें मिनट में गोल दागा जबकि क्रिस्टियन रोमेरो का आत्मघाती गोल अर्जेंटीना के खाते में गया। लिसांद्रो मार्तिनेज ने 92वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से बढत दिलाई।

केप वर्दे के लिए काब्राल और डुआर्टे ने दागे बराबरी के गोल

केप वर्दे के लिए सिडनी लोपेज काब्राल और डेरॉय डुआर्टे ने बराबरी के गोल दागकर अर्जेंटीना समर्थकों को स्तब्ध कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि पेनल्टी शूटआउट से ही फैसला होगा, जिसमें मेस्सी का सामना वोजिन्हा से होगा लेकिन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में जीत दर्ज की। अब अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा, जिसने अटलांटा में पेनल्टी शूटआउट में आस्ट्रेलिया को हराया।

पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता मिस्र, ऑस्ट्रेलिया बाहर

अर्लिंगटन। होसाम अब्दुलमागुद ने शूटआउट में निर्णायक गोल किया, जिसके दम पर पहली बार विश्व कप नॉकआउट मुकाबला खेलते हुए मिस्र ने आस्ट्रेलिया के पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया जबकि निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर था। मिस्र ने चौथी बार विश्व कप खेलते हुए यह जीत दर्ज की है। वहीं आस्ट्रेलिया नॉकआउट में तीन में से एक भी बार जीत नहीं सका है। अब मिस्र का सामना मंगलवार को गत चैम्पियन अर्जेंटीना से होगा, जिसने केप वर्दे को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई है। शूटआउट में आस्ट्रेलिया के हैरी साउटार का निशाना चूका और 18 वर्ष के लुकास हेरिंगटन का शॉट क्रॉसबार से टकरा गया। मिस्र के लिए होसाम के अलावा महमूद साबिर, रामी राबिया और लिवरपूल के पूर्व स्टार मोहम्मद सालाह ने गोल दागे। मांसपेशी की चोट के बावजूद सालाह ने यह मैच खेला। आस्ट्रेलिया के लिए ये शूटआउट में जैकसन इरविन और अवेर माबिल ने गोल किए। इमाम अशूर ने 13वें मिनट में हेडर पर गोल करके मिस्र को बढत दिला दी थी। आस्ट्रेलिया ने 55वें मिनट में बराबरी की जब मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी एक ही विश्व कप में दो आत्मघाती गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

घाना को हराकर कोलंबिया अंतिम 16 में

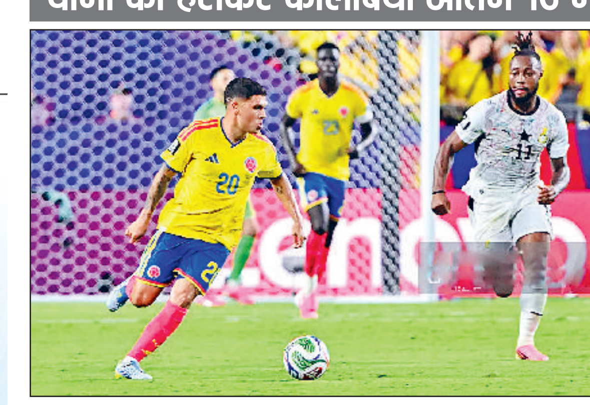

कंसास सिटी। जोन एरियास ने शुरुआती मिनटों में लुई सुआरेस के क्रॉस पर गोल किया और इसी एक गोल के दम पर कोलंबिया ने भीषण गर्मी के बीच घाना को हराकर विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली। कोलंबिया का सामना अब मंगलवार को वैंकूवर में स्विटजरलैंड से होगा। मैच शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर ही कोलंबिया के फॉरवर्ड जोन कोरडोबा को जांघ के पीछे की मांसपेशी में चोट लग गई, जिसके बाद कोच नेस्टर लोरेंजो को सुआरेज को बुलाना पड़ा। यह इंटर मियामी के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी सुआरेज नहीं बल्कि स्पोर्टिंग सीपी के लिए खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने आते ही अपने प्रदर्शन की छाप छोड़ी और 14वें मिनट में डेनियल मुनोज से गेंद लेकर एरियास को जबर्दस्त क्रॉस दिया, जिन्होंने घाना के गोलकीपर लारेंस एटि जिगि को छकाकर गोल कर दिया।

खबर संक्षेप

हुलेनकोर्ट महिला ओपन खिताब की दौड़ में दीक्षा

हुलेनकोर्ट। दीक्षा डागर खिताब की दौड़ में बनी हुई है और भारत की चारों गोल्फर ने हुलेनकोर्ट महिला ओपन के कट में प्रवेश कर लिया। दीक्षा बढ़त पर थी लेकिन इवन पार 72 का स्कोर करके संयुक्त तीसरे स्थान पर खिसक गई। उन्होंने तीन बर्डी लगाए लेकिन तीन बोगी भी किए। भारत की अदिति अशोक ने भी लेडीज यूरोपीय टूर पर प्रभावी वापसी करके संयुक्त आठवां स्थान हासिल कर लिया। अवनि प्रशांत संयुक्त 18वें स्थान पर है जबकि प्रणवी उर्स संयुक्त 56वें स्थान पर है। स्पेन की कैरोलिना चाकारा ने सात अंडर 65 और कुल नौ अंडर स्कोर करके बढत बना ली है।

20 को ग्लास्गो रवाना होगी जिम्नास्टिक्स टीम

नई दिल्ली। भारत की कलात्मक जिम्नास्टिक्स टीम आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के तहत लंदन में तीन सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर पूरा करने के बाद 20 जुलाई को ग्लास्गो के लिए रवाना होगी। यह प्रशिक्षण शिविर 29 जून से शुरू हुआ, जिसके लिए कोष भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने 'टारगेट एशियन गेम्स ग्रुप' और 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' के तहत दिया था। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए महिला टीम में ओलंपियन प्रणति नायक, निश्का अग्रवाल, ईशिता रेवाले और प्रतिष्ठा सामंता शामिल हैं। पुरुष टीम में तपन मोहंती, तपेश्वरनाथ दास, स्वातिश केपी और योगेश्वर सिंह को जगह मिली है। राकेश पात्रा पुरुष टीम के कोच हैं जबकि पायल भट्टाचार्जी और अशोक कुमार मिश्रा महिला टीम के कोच के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

बेथल का शानदार अर्धशतक

टी-20 श्रृंखला : इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया

▶▶| **सूर्यवंशी का पदार्पण रहा फीका**

▶▶| **बिश्नोई के ओवर में 29 रन बने, बेथेल ने 76 रन बनाए**

भाषा ▶▶| मैनचेस्टर

रवि बिश्नोई का एक महंगा ओवर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पर भारी पड़ा जहां इंग्लैंड ने शनिवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ओवर शेष रहते छह विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले आयरलैंड ने भारत को 2 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से हराया था। मैच का निर्णायक मोड़ 17वां ओवर साबित हुआ, जिसमें रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए। ओवर की शुरुआत उन्होंने लगातार दो नो-बॉल से की और इसके बाद जैकब बेथल ने तीन शानदार छक्के जड़कर मैच पूरी तरह इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। बेथल ने 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। दिन की शुरुआत 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के पदार्पण को लेकर उत्साह के साथ हुई थी, लेकिन अंत 22 वर्षीय जैकब बेथल की विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम रहा। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह (40 रन पर तीन विकेट) ने फिल सॉल्ट और जोस बटलर को खाता खोले बिना आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान हैरी ब्रूक ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 39 रन बनाए। उन्होंने अर्शदीप के एक ओवर में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 27 रन बटोरे और दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। अक्षर पटेल (20 रन पर एक विकेट) ने हैरी ब्रूक को विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराकर भारत को राहत दिलाई, लेकिन तब तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद बेथल और टॉम बैंटन ने चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर भारतीय स्पिन आक्रमण को प्रभावी नहीं होने दिया। बैंटन ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए। भारतीय स्पिनरों में केवल अक्षर ही प्रभाव छोड़ सके।

विंबलडन में हार पर बोले भांबरी, हमने बहुत नर्वस मैच खेला

एजेंसी ▶▶| लंदन

भारत के डबल्स खिलाड़ी युकी भांबरी ने कहा है कि विंबलडन के पहले राउंड में मिली हार की वजह उनका और साथी खिलाड़ी माइकल वीनस का टूर्नामेंट का दबाव नहीं झेल पाना है। भांबरी और न्यूजीलैंड के वीनस को पहले राउंड में डच-अमेरिकन जोड़ी जीन-जूलियन रोजर और थियोडोर वाइनगर ने 3-6, 4-6 से हराया, जिसमें इंडो-कीवी जोड़ी को सर्व पर खुद को हावी करने में मुश्किल हुई, और वे किसी भी ब्रेक-पॉइंट के मौके को भुनाने में नाकाम रहे। भांबरी ने कहा, हमारे खेल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक में खेलते हुए, मुझे लगता है कि यह मौका मुझे और मेरे साथी खिलाड़ी माइकल वीनस को मिल गया। हम दबाव नहीं झेल पाए।

हमने बहुत नर्वस मैच खेला, और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। हमारा मूवमेंट तेज नहीं था, हमारा रिटर्न खराब था। हम सर्व पर रिदम नहीं बना पाए। पहले राउंड से बाहर होने के बावजूद 33 साल के भांबरी भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा, मैं और माइकल साथ में अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले हमारे कुछ अच्छे नतीजे रहे हैं। उम्मीद है कि हम कुछ और विंबलडन में वापस आकर इसे ठीक करेंगे। हम इस अनुभव से सीखेंगे और अगली बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भांबरी ने अपना फोकस भारत के दक्षिण कोरिया के खिलाफ आने वाले डेविस कप क्वालीफायर मुकाबले पर किया, और इसे देश के लिए एक बड़ा मौका बताया।

अनुष का शानदार प्रदर्शन जीता रजत पदक

नई दिल्ली। भारत के स्टार घुड़सवार खिलाड़ी अनुष अग्रवाला ने जर्मनी के हेगन में आयोजित कैवालिएरो ड्रेसेज डेज प्रतियोगिता के सीडीआई1 प्री सेंट जॉर्ज वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। 'स्ट्रेट हॉर्स फ्लोरियाना' पर सवार अनुष ने 70.147 प्रतिशत अंक हासिल किए और 22 प्रतिभागियों के बीच दूसरे स्थान पर रहे। अनुष और फ्लोरियाना के बीच बेहतरीन तालमेल तथा सटीक प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने प्रतिष्ठित 70 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी निरंतरता को दर्शाता है। इस स्पर्धा में जर्मनी की चार्लोट-मारिया शूर्मन 72.304 प्रतिशत अंक के साथ पहले स्थान पर रहीं। यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है, जब 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय ड्रेसेज टीम के चयन को लेकर अनुष विवाद के केंद्र में हैं। उन्हें चार सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया बल्कि रिजर्व खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है।

अंडर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 : भारत की झोली में आए चार पदक, सुमित ने जीता गोल्ड

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रोहतक

थाईलैंड के पटाया आयोजित अंडर-20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवानों ने पहले ही दिन धमाकेदार आगाज़ किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय दल ने मैट पर अपना जबरदस्त दबदबा दिखाते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक सहित कुल चार पदक अपने नाम किए। भारतीय खेमे के लिए सबसे बड़ी सफलता 70 किलोग्राम भारवर्ग में आई, जहाँ युवा और प्रतिभाशाली पहलवान सुमित कुमार लक्ष्मण भास्कर ने स्वर्ण पदक जीतकर तिरंगा लहराया। सुमित ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपने आक्रामक खेल और बेहतरीन दांव-पेच के दम पर विरोधी पहलवानों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया और एकतरफा जीत दर्ज करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं, 79 किलोग्राम भारवर्ग में भारत के सौरभ यादव ने भी शानदार तकनीक का प्रदर्शन किया. सौरभ ने फाइनल तक का सफर बेहद दमदार तरीके से तय किया, लेकिन खिताबी मुकाबले में कड़े संघर्ष के बाद उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा, कांस्य पदक के मुकाबलों (रिपेचेज राउंड) में भी भारतीय पहलवानों की बादशाहत देखने को मिली। 57 किलोग्राम भारवर्ग में रोहित ने और 97 किलोग्राम हेवीवेट भारवर्ग में लकी ने अपने-अपने मुक़ाबलों में विरोधी पहलवानों को चारों खाने चित करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीते। फ्रीस्टाइल इवेंट के पहले ही दिन चार पदक आने पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने सभी विजेता पहलवानों और उनके कोचों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पहले दिन के इस शानदार प्रदर्शन से बाकी बचे भारवर्गों के भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में भारत की झोली में कई और बड़े पदक आ सकते हैं।

ग्रैंड शतरंज टूर : गुकेश और केमेर ने हासिल किए दस अंक

प्रज्ञानानंदा ने जीते तीनों मुकाबले, रैपिड वर्ग में 12 अंक

एजेंसी ▶▶| जगरेब

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने आखिरी दिन तीनों मुकाबले जीतकर ग्रैंड शतरंज टूर के क्रोएशिया चरण में रैपिड श्रेणी में 12 अंक लेकर फ्रांस के फिरोजा अलीरजा के साथ संयुक्त शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। दूसरे दिन पिछड़ रहे प्रज्ञानानंदा ने आखिरी दिन क्रोएशिया के इवान सारिच, रोमानिया के डीक बोगडेन डेनियल और नीदरलैंड के अनीश गिरि को हराया। फ्रांस के मैक्सिम वाचियेर लाग्रेव और उजबेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव 11 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहे। विश्व चैंपियन डी. गुकेश और जर्मनी के विंसेंट केमेर ने दस अंक हासिल किए। अब ब्लिट्ज वर्ग के 18 दौर खेले जाने हैं। गिरि के आठ अंक हैं जबकि डीक और नीदरलैंड के जोर्डन वान फोरीस्ट उनसे एक अंक पीछे हैं।

पूर्व विश्व चैंपियन क्रामनिक निलंबित

बिलिंग्स। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने पूर्व विश्व चैंपियन ब्लादीमिर क्रामनिक को कम से कम एक साल के लिए निलंबित कर दिया है, जिन्होंने डेनियल नारोदित्स्की समेत साथी खिलाड़ियों पर धोखेबाजी के आरोप लगाए थे, जो साबित नहीं हुए। नारोदित्स्की का पिछले साल 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। क्रामनिक ने उन पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए इसे सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। अमेरिकी ग्रैंडमास्टर नारोदित्सकी ने शिक्षाप्रद यूट्यूब वीडियो और लाइवस्ट्रीम के जरिए खेल के आनलाइन दौर को लाने में मदद की थी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया था। क्रामनिक ने एपी को भेजे ईमेल में कहा कि वह इस निलंबन को चुनौती देंगे। शतरंज महासंघ ने कहा कि क्रामनिक ने बिना पर्याप्त सबूतों के सार्वजनिक रूप से धोखाधड़ी का आरोप लगाया जो 'साइबर बुलिंग' के खिलाफ उनके नियमों का उल्लंघन है। महासंघ ने कहा कि धोखाधड़ी से निपटना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है लेकिन आरोपों पर उनकी प्रक्रियाओं के जरिए ही कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें उचित सबूतों का समर्थन मिलना चाहिए। नारोदित्स्की ने कहा था कि क्रामनिक के आरोपों का उन पर काफी असर पड़ा है।

अमित शाह बोले- हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार

23 और व्यक्ति 'आतंकवादी' घोषित इसमें 17 पाकिस्तानी, 6 भारतीय

यूएपीए के तहत केंद्र सरकार का फैसला

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 23 और व्यक्तियों को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया है। घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) से भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं।

आतंक के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस'

अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' विजन को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 23 खूंखार आतंकवादियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमलों, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकी संगठनों की मदद, फंड जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। मोदी सरकार भारत और देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अब तक 57 व्यक्ति घोषित किए आतंकवादी

केंद्र ने 2019 में यूएपीए में संशोधन के बाद पहली बार व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान लागू किया था। अब तक अधिनियम की धारा 35 के तहत कुल 57 व्यक्तियों को यूएपीए की चौथी अनुसूची में 'आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका।

अलग-अलग संगठनों से जुड़े हैं आतंकी

गृह मंत्रालय द्वारा घोषित 23 आतंकवादियों में अधिकांश का संबंध जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जमात-उद-दावा (जेयूडी), हरकत-उल-मुजाहिद्दीन (एचयूएम), पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल), अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से है। इन पर सीमा पार घुसपैठ, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने, आतंकी फंडिंग, युवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण शिविर संचालित करने और भारत में कई बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने या उन्हें अंजाम देने के आरोप हैं।

सूची में जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर मसूद शामिल

गृह मंत्रालय ने जिन 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है, उनमें मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हाफिज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट, गुलाम फरीद, हारून रशीद गनई, बिलाल अहमद मीर, आबिद कयूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वालीद, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ ताईबी, ओवैस फारूज, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, वसीम नूर जाट और मोहम्मद शहीद फैसल शामिल हैं। मसूद इलियास कश्मीरी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर है। वह 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के सुंजवान में सुरक्षा बलों पर हुए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमले में शामिल था।

मसूद कश्मीरी

किताबों में आतंकियों को बताया 'महान'

एलजी सिन्हा ने 8 अधिकारी सस्पेंड किए, जांच के आदेश

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची दो विवादित किताबों के मामले में एक्शन लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को सेवा से हटा दिया गया है। सरकार ने पूरे मामले की हाई-लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं। साथ ही, अलगाववाद से जुड़ी 'बेहद आपत्तिजनक सामग्री' वाली दोनों किताबों के लेखकों और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव राम निवास शर्मा ने कहा कि इस विवादित किताब को फौरन सभी सरकारी स्कूलों से वापस मंगा लिया गया है।

मनोज सिन्हा

यह गंभीर अपराध

जम्मू-कश्मीर में सरकारी स्कूलों के लाइब्रेरी में उपलब्ध किताब में आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं को महान हस्ती के तौर पर बताया गया। इस पर भाजपा विधायक विधानसभा प्रतिपक्ष नेता सुनील शर्मा ने कहा इसे गंभीर अपराध बताया है। इस किताब का नाम 'ग्रेट पर्सनेलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर' है। किताब में आतंकवादी मकबूल भट्ट को 'शहीद' बताया और हाफिज सईद को भी महान हस्ती बताने का दावा किया गया। वहीं, अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, शब्बीर अहमद शाह और मौलवी फारूक को कश्मीर का 'स्वतंत्रा सेनानी' बताया गया है।

खबर संक्षेप

रूसी तेल टर्मिनल पर यूक्रेन का फिर से हमला

मॉस्को। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के एक तेल टर्मिनल पर हमला हुआ। रूसी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह हमला शहर के कीरोव्स्की जिले में हुआ, जहां बाल्टिक सागर के किनारे तेल टर्मिनल स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव के मुताबिक, रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने शहर और आसपास के इलाकों में 72 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं दी गई है।

स्पेन में पकड़ा गया गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों

नई दिल्ली। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इनपुट पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों स्पेन के मेड्रिड शहर में पकड़ा गया। स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों ने गोल्डी ढिल्लों को हिरासत में लिया। गोल्डी एनआईए का वांटेड आरोपी भी है और उसके ऊपर 10 लाख का इनाम है। 5 लाख का इनाम पंजाब पुलिस ने भी उसके ऊपर घोषित किया हुआ है। कनाडा में हुई फायरिंग की कई घटनाओं में गोल्डी ढिल्लों का हाथ था। पंजाब में भी संगठित अपराध की कई घटनाओं में गोल्डी ढिल्लों आरोपी है। पहले वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा था।

टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026 के मौके पर पीयूष गोयल बोले

एफटीए पर कनाडा के साथ वार्ता अच्छी प्रगति पर, पेरू से कई मुद्दों पर मतभेद

पीएम मोदी ने उद्योग को गुणवत्ता के लिए प्रेरित किया

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद संग संवाद भारत द्वारा अंतिम रूप दिए गए मुक्त व्यापार समझौते का पूरक बनेगा। इसका उद्देश्य समझौते के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। यह एफटीए को लागू करना आसान बनाएगा और उसके लाभों को हासिल करने में मदद करेगा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने साफ किया कि भारत और पेरू के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) निकट भविष्य में संपन्न होने की संभावना नहीं है। इसका मुख्य कारण कुछ उत्पादों के लिए बाजार पहुंच से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं।

गोयल ने यह भी बताया कि कनाडा के साथ एफटीए वार्ता अच्छी प्रगति पर है। गोयल ने टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026 के मौके पर बातें कही। पीयूष गोयल ने वैश्विक आर्थिक मंदी की चिंताओं पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम में 50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विजिटर्स की मेजबानी हुई है। यह भारत की आर्थिक सफलता की कहानी का साफ संकेत है। यह देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग को लगातार गुणवत्ता, स्केल और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। गोयल ने विश्वास जताया कि खिलौना उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और यह उल्लेखनीय प्रगति के लिए पूरी तरह तैयार है।

देश के खिलौना उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल

"भारत अपने घरेलू उद्योगों के हित की रक्षा कर रहा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फाइल फोटो

पेरू से एफटीए होने में काफी समय लगेगा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेरू के साथ मुक्त व्यापार समझौते में देरी का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। भारत कई ऐसे उत्पादों के लिए पेरू को बाजार में पहुंच की पेशकश नहीं कर सकता है। दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। गोयल ने साफ किया कि उन्हें नहीं लगता कि पेरू के साथ एफटीए बहुत जल्द संभव हो पाएगा। यह मुद्दा दोनों पक्षों के लिए एक बड़ी बाधा है। भारत अपने घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करना चाहता है।

कनाडा संग वार्ता का दूसरा दौर सोमवार से

पीयूष गोयल ने बताया कि कनाडा के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है। वार्ता का अगला महत्वपूर्ण दौर सोमवार को शुरू होने वाला है। भारत सरकार अगले छह महीनों में इस समझौते को संपन्न करने का प्रयास कर रही है। यह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को नई गति देगा।

इजराइल से भी चर्चा जारी

इजराइल के साथ प्रस्तावित एफटीए पर भी बातचीत और चर्चाएं जारी हैं। हालांकि, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। गोयल ने उम्मीद जताई कि शांति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वार्ता को तेज किया जा सकेगा। भारत दोनों देशों के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जल्द जाएंगे ब्रुसेल्स

मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वह विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ब्रुसेल्स जाएंगे। वे यूरोपीय आयोग के साथ भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) संवाद में भाग लेंगे। गोयल ने कहा कि यह संवाद भारत द्वारा अंतिम रूप दिए गए मुक्त व्यापार समझौते का पूरक बनेगा। इसका उद्देश्य समझौते के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। यह एफटीए को लागू करना आसान बनाएगा और उसके लाभों को हासिल करने में मदद करेगा। यह बैठक भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भविष्य के व्यापारिक संबंधों की नींव रखेगा।

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

भारत गणराज्य की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईए) शनिवार से प्रभावी हो गया। इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा पूर्वानुमानित निवेश माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। द्विपक्षीय निवेश समझौता निवेशकों और उनके निवेशों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही, यह दोनों देशों को अपने वैध सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप संप्रभु नीतिगत अधिकार बनाए रखने का पर्याप्त लचीलापन भी देता है। यह समझौता अंतरराष्ट्रीय निवेश कानून के आधुनिक सिद्धांतों और विकसित होते न्यायशास्त्र के अनुरूप तैयार किया गया है। सरकार के अनुसार, इस समझौते से भारत और इजराइल के बीच सीमा पार निवेश में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और द्विपक्षीय साझेदारी को भी नई मजबूती मिलेगी।

लाहौर पुलिस ने की गिरफ्तारी, पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

गैंगरेप का आरोपी निकला भारत को गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री का पोता

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

भारत द्वारा आतंकवाद के मामले पर पिछले साल पहलगाम हमले के बाद स्थगित की गई सिंधु जल संधि के मामले को लेकर अक्सर भारत को धमकी देने वाले पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की इन दिनों अपने ही देश में जमकर छीछालेदर हो रही है। मामला बेहद गंभीर है, जिसमें डार के पोते रजा डार को दो विदेशी महिलाओं (नीदरलैंड और वेनेजुएला) से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

लाहौर की एक अदालत ने मामले से जुड़े सभी चार आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जबकि एक अन्य आरोपी अभी तक फरार है।

दूतावासों के दखल के बाद हुई गिरफ्तारी

यह पूरा मामला पिछले महीने 29 जून का है। जब रजा डार ने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर इन दोनों विदेशी महिलाओं का अपहरण कर उन्हें जबरन बंधक बनाकर रखा और फिर उनका गैंगरेप किया। लाहौर पुलिस की जांच के मुताबिक, इन दोनों विदेशी महिलाओं से रजा डार की मुलाकात पिछले साल 2025 में सिंगापुर में हुई थी। जिससे यह साफ हो जाता है कि यह सभी एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। क्रिप्टोकरंसी वेंचर में भी तीनों बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे हैं। वह रजा डार ही था जिसने इन दोनों महिलाओं की पाकिस्तान यात्रा के लिए बिजनेस वीजा से जुड़ी तमाम व्यवस्था भी की थी। अब इस मामले के सामने आने के बाद इन दोनों विदेशी महिलाओं को जल्द पाकिस्तान से इनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया चल रहा है।

इशाक डार के इस्तीफे की उठी मांग

वहीं, इस प्रकरण के सामने आने के बाद पाकिस्तान में उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के इस्तीफे की मांग की जाने लगी है। पाकिस्तानी सीनेटर फैसल वावदा ने इसे लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया में तर्क देते हुए कहा है कि गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद इशाक डार पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें पाकिस्तान की छवि की जरा सी भी चिंता है तो अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

5 से 15 जुलाई तक चलेगा यात्रा कार्यक्रम, शुरुआत खाड़ी क्षेत्र के देशों से होगी

आज से 6 देशों की विदेश यात्रा पर रहेंगे डॉ. एस. जयशंकर

- **कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान होते हुए न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स जाएंगे विदेश मंत्री**

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच विदेश मंत्री डॉ.एस.जयशंकर रविवार (5 जुलाई) से 6 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में बताया कि विदेश मंत्री की इस यात्रा का कार्यक्रम 5 से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। गौरतलब है कि जयशंकर की यह यात्रा एक ऐसे समय पर हो रही है। जब बीते दिनों अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान ओमान की खाड़ी के इलाके में अमेरिकी नौसेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई थी।

इसके अलावा तीनों देशों के बीच क्षेत्र में शांति स्थापना को लेकर शांति समझौते की कवायद में नई दिल्ली द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से स्वतंत्र और निर्बाध वैश्विक नौवहन को बनाए रखने के लिए जारी सभी प्रयासों को अपना समर्थन देने का ऐलान किया गया है।

यात्रा की शुरुआत खाड़ी क्षेत्र से होगी

डॉ. जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक अपनी इस यात्रा की शुरुआत खाड़ी क्षेत्र के कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान जैसे चार देशों से करेंगे। जहां उनकी इन सभी देशों के अपने समकक्षों यानी विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी। साथ ही इस दौरे में भारत का ध्यान खाड़ी के इन चारों देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य में और अधिक आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। वहीं, यह दोनों पक्षों को एक ऐसा अवसर भी प्रदान करेगा। जिसमें वह क्षेत्रीय घटनाक्रमों और साझा हितों से जुड़े हुए विभिन्न मामलों को लेकर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

न्यूयॉर्क में जारी होगा यूएनएससी अभियान

खाड़ी के बाद विदेश मंत्री न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे और वहां पर 13 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के लिए वर्ष 2028-29 में भारत के कार्यकाल के लिए एक आधिकारिक अभियान को लांच करेंगे।

ब्रसेल्स में होगी भारत-ईयू व्यापार वार्ता

मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव 14 से 15 जुलाई तक ब्रुसेल्स होगा। जहां पर वह भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार और तकनीकी परिषद की तीसरी बैठक में भाग लेंगे। साथ ही उनकी ईयू और बेल्जियन भागीदारों के साथ भी बातचीत होगी।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सैंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ.हिमांशु द्विवेदी। आरएनआई नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109